



नई दिल्ली, लखनऊ और रायपुर से प्रकाशित

पायनियर



वायनाड की त्रासदी
से अलग तरीके से
निपटना होगा
राष्ट्रीय-10

www.dailypioneer.com

कोचिंग सेंटर मौत मामले की सीबीआई करेगी जांच

दिल्ली हाईकोर्ट ने सौंपी, कहा-यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनता को इस पर संदेह न हो

पीटीआई। नई दिल्ली

दिल्ली उच्च न्यायालय ने यहां राजेंद्र नगर में स्थित एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे तीन विद्यार्थियों की डूबने से हुई मौत के मामले की जांच शुरू करने को दिल्ली पुलिस से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी। उच्च न्यायालय ने इस मामले की जांच को सीबीआई को यह सुनिश्चित करने के लिए सौंपी कि जनता को जांच पर कोई संदेह न हो।



कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडला की पीठ ने आपराधिक मामले में सीबीआई द्वारा की जाने वाली जांच की निगरानी के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीबीसी) को एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने को कहा। अदालत ने कहा, घटना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनता को जांच के संबंध में कोई संदेह न हो, यह अदालत मामले की जांच सीबीआई को सौंपती है। पीठ ने बेसमेंट में पानी भरने से तीन विद्यार्थियों की मौत के

मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा एक वाहन चालक को गिरफ्तार किए जाने पर कटाक्ष करते हुए कहा, गनीमत है कि आपने बेसमेंट में घुसने वाले बारिश के पानी का चालान नहीं काटा। वाहन (शेष पेज 9)

नीट-यूजी में शुचिता का उल्लंघन नहीं शीर्ष अदालत ने कहा, इसलिए परीक्षा रद्द नहीं की गई

राजेश कुमार। नई दिल्ली

पेपर के आरोपों और परीक्षा में अन्य अनियमितताओं पर बढ़ते विवाद के बावजूद वर्ष 2024 (नीट यूजी 2024) के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा स्नातक परीक्षा को रद्द नहीं करने का विस्तृत कारण बताते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि कोई प्रणालीगत कमी नहीं थी। पेपर लीक केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था। शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया, इसलिए इस वर्ष की परीक्षा के संबंध में दोबारा परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी। अपने 63 पन्नों के फैसले में, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि एनटीए को 'फिलप फ्लॉप' से बचना चाहिए, जो इस साल देखा गया क्योंकि यह छात्रों के हित में काम नहीं करता है। इसने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (स्नातक) आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के कामकाज की समीक्षा के लिए गठित पूर्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में केंद्र द्वारा नियुक्त पैनल के दायरे का भी विस्तार किया। शीर्ष अदालत ने कहा कि चूंकि पैनल का दायरा बढ़ा



नीट से पहले चिकित्सा शिक्षा खुला व्यवसाय थी: नड्डा

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

हाल ही में हुए नीट पेपर लीक विवाद के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने परीक्षा प्रणाली का बचाव करते हुए कहा कि नीट शुरू होने से पहले चिकित्सा शिक्षा एक खुला व्यवसाय बन गई थी और प्रत्येक पीजी सीटें 8 करोड़ रुपये से 13 करोड़ रुपये में बेची गईं। डीएमके के राज्यसभा सदस्य एम. मोहम्मद अब्दुल्ला के एक निजी सदस्य के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान चिंताओं



को संबोधित करते हुए, नड्डा ने इस बात पर जोर दिया कि चिकित्सा शिक्षा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार से निपटने के (शेष पेज 9)

दिया गया है, इसलिए समिति परीक्षा प्रणाली में कमियों को दूर करने के विभिन्न उपायों पर 30 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

पीठ ने कहा कि राधाकृष्णन पैनल को परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए तकनीकी प्रगति को अपनाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने पर विचार करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने विवादों से घिरी नीट-यूजी 24 परीक्षा को रद्द करने से इनकार करने के अपने 23 जुलाई के आदेश के लिए विस्तृत कारण बताए। वर्तमान में पर्याप्त सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं है जो इंगित करती है अन्य रूपों का एक प्रणालीगत लीक या प्रणालीगत कदाचार। वर्तमान में, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री इस आरोप की पुष्टि नहीं करती है कि व्यापक कदाचार हुआ है जिसने परीक्षा की अखंडता से समझौता किया है। इसके विपरीत, डेटा का आकलन यह दर्शाता है ऐसा कोई विचलन नहीं है जो यह दर्शाता हो कि प्रणालीगत धोखाधड़ी हुई है।

पीठ को ओर से लिखते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस स्तर पर अदालत के समक्ष दी गई जानकारी यह नहीं दिखाती है कि प्रश्न पत्र को (शेष पेज 9)

एयर इंडिया ने इजराइल की उड़ानें आठ तक स्थगित की पीटीआई। नई दिल्ली

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच एयर इंडिया ने शुक्रवार को तेल अवीव के लिए उड़ानें आठ अगस्त तक स्थगित करने की घोषणा की। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन राष्ट्रीय राजधानी से इजराइली शहर के लिए सप्ताह में पांच उड़ानें संचालित करती है।

एयरलाइन ने एक बयान में कहा, पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में मौजूदा स्थिति को देखते हुए, हमने तेल अवीव से आने-जाने वाली अपनी उड़ानों के निर्धारित संचालन को तत्काल प्रभाव से आठ अगस्त 2024 तक स्थगित कर दिया है। एयरलाइन ने यह भी कहा कि वह इस अवधि के दौरान तेल अवीव से आने-जाने के लिए टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को सहायता प्रदान कर रही है तथा यात्रा पुनर्निर्धारण और रद्दीकरण शुल्क पर एक बार की छूट दे रही है। एयर इंडिया ने बृहस्पतिवार को अपनी तेल अवीव की उड़ान रद्द कर दी थी। इजराइल और हमला सहित विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष के कारण पश्चिम एशिया में तनाव के हालात हैं। इस वर्ष की शुरूआत में भी, पश्चिम एशिया में तनाव के कारण एयर इंडिया ने अलग-अलग समय पर तेल अवीव के लिए उड़ानें कुछ समय के लिए स्थगित कर दी थीं।



आशा किरण में हुई मौतों की जांच के आदेश

एलजी ने मुख्य सचिव को सभी आश्रयगृहों पर श्वेत पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया

सौम्या शुक्ला। नई दिल्ली

आशा किरण आश्रय गृह में मानसिक रूप से दिव्यांग कैदियों की मौतों में अचानक वृद्धि के बीच, केवल जुलाई में एक दर्जन से अधिक मौतें हुईं, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शुक्रवार को मुख्य सचिव को सभी आश्रय गृहों के संचालन पर एक श्वेत पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। दिल्ली सरकार तीन सप्ताह में प्रशासक के खिलाफ तुरंत कार्रवाई शुरू करेगी, जबकि मंत्री आतिशी ने

राजस्व विभाग को मजिस्ट्रेट जांच शुरू करने और 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। आशा किरण 'मानसिक रूप से दिव्यांगों' के लिए दिल्ली सरकार द्वारा संचालित सुविधा है और इसके समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आती है। राजकुमार आनंद के इस्तीफे के बाद विभाग फिलहाल बिना मुखिया के है। फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसी भी मंत्री को विभाग का प्रभार (शेष पेज 9)

वायनाड के 13 गांवों समेत पश्चिम घाट के 56 हजार किमी के लिए मसौदा अधिसूचना जारी पीटीआई। नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने केरल के भूस्खलन प्रभावित वायनाड के 13 गांवों समेत छह रायों में फैले पश्चिमी घाट के 56,800 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) घोषित करने के लिए पांचवां मसौदा अधिसूचना जारी की है तथा 60 दिन के भीतर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। यह अधिसूचना 31 जुलाई को जारी की गई थी।

मसौदा अधिसूचना में केरल के 9,993.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील घोषित करने का प्रस्ताव है, जिसमें भूस्खलन प्रभावित जिले के दो तालुका के 13 गांव शामिल हैं। अधिसूचना में प्रस्तावित ईएसए में गुजरात में 449 वर्ग किमी, महाराष्ट्र में 17,340 वर्ग किमी, गोवा में 1,461 वर्ग किमी, कर्नाटक में 20,668 वर्ग किमी, तमिलनाडु में 6,914 वर्ग किमी और केरल में 9,993.7 वर्ग किमी क्षेत्र शामिल हैं। मसौदा अधिसूचना में रेत खनन समेत सभी तरह की खनन गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया गया है। इसमें कहा गया है कि मौजूदा खदानों को अंतिम अधिसूचना जारी होने की तारीख से पांच वर्षों के भीतर या मौजूदा खनन पट्टे को समाप्त कर, जो भी पहले हो चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया जाएगा।

दुश्मनों ने गला दबाकर जिंदा गाड़ा, कुत्तों ने बचाई जान



पायनियर समाचार सेवा। आगरा/नई दिल्ली

आगरा में तीस के आसपास की उम्र के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि भूमि विवाद के सिलसिले में चार लोगों ने उसे पीटा, गला घोंटा और जिंदा दफना दिया, लेकिन बाद में आगरा कुत्तों द्वारा जमीन खोदने के बाद चमत्कारिक रूप से वह बच गया। आगरा पुलिस ने कहा कि एक शिकायत के आधार पर चार लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 109 (हत्या का प्रयास), 115 (स्वेच्छ से चोट पहुंचाना) और 351 (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पीड़ित रूप किशोर ने दावा किया कि 18 जुलाई को आगरा के अरटोनी इलाके में अंकित, गौरव, करण और आकाश नाम के चार लोगों ने उन पर हमला किया था। आरोपियों ने उसका भी गला घोंटा दिया और फिर उसे मरा समझकर अपने खेत में दफना दिया। किशोर ने

दावा किया कि वह इस इसलिए बच गया क्योंकि आगरा कुत्तों ने उस जगह को खोद डाला जहां उसे दफनाया गया था और उसके शरीर को नोंचने लगे, जिससे उसे होश आ गया। उसके बाद, किशोर ने कहा कि वह पास के एक गांव चला गया, जहां स्थानीय लोगों उसे अस्पताल ले गए। फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। किशोर की मां के मुताबिक आरोपी उसके बेटे की जबरन घर से ले गए और बेरहमी से मारपीट कर उसका गला घोंटा दिया। इसके बाद उन्होंने किशोर को अपने खेत में एक गड्ढे में दफना दिया।

सिकंदरा पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (उसएचओ) नीरज शर्मा ने कहा कि चारों आरोपी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले में केस दर्ज कराने वाली रूप की मां रामवती ने कहा, (शेष पेज 9)

दिल्ली में इमारत गिरी, तीन की मौत एनडीआरएफ व दमकल कर्मियों ने चार घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला, एक की हालत गंभीर पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

जहांगीरपुरी औद्योगिक क्षेत्र में मंगलवार दोपहर एक इमारत भूस्खलन गिर गई। मलबे में दबने से एक महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गई। मरने वालों की पहचान फूलवती, मनोज के रूप में हुई है। एनडीआरएफ और दमकल कर्मियों ने चार घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल भर्ती कराया। घायलों में एक की हालत गंभीर है। इन लोगों की पहचान, निर्मला, हरिशंकर, ठामर दास और जर्सीन के रूप में हुई है। दिल्ली नगर निगम ने कहा कि बचाव व राहत कार्य समाप्त हो गया है। मलबे में अब किसी के दबे होने की आशंका नहीं है।



दिल्ली के जहांगीरपुरी में इमारत के गिरने के बाद राहत और बचाव कार्य चल रहा है। फोटो रंजन डिमरी

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जहांगीरपुरी इलाके में शुक्रवार दोपहर के वक्त सनसनी फैल गई जब औद्योगिक क्षेत्र की ई ब्लॉक स्थित फैक्ट्री का आगे का हिस्सा भांभरा कर गिर गया। इस इमारत का आगे का हिस्सा काफी समय से जर्जर हालत में था। 1 साल पहले ही इसका मरम्मत कराया गया था बावजूद इसके इस फैक्ट्री में तीनों फ्लोर, भूमिगत, प्रथम और द्वितीय पर अलग-अलग काम किया जा रहा था जिसमें गट्टे की फैक्ट्री, कपड़े की फैक्ट्री और गैस चूल्हे के बांडी बनाने का काम चल

रहा था। साथ ही साथ आगे के हिस्से में मरम्मत का काम चल रहा था। इसी दौरान अगला हिस्सा भांभरा कर गिरा और वहां काम कर रहे करीब 6 से 7 लोग इस मालवा के नीचे दब गए। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस और दमकल को दी। सभी छह लोगों को एंबुलेंस की मदद से पहले बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले जाया गया। यहां तीन लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। वहीं दो ने इलाज के दौरान दम

तोड़ दिया, जबकि एक की एलएनजेपी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। महावीर शैली ओबेरॉय ने बताया कि हादसे में कुल तीन लोगों की मौत हुई है। इस घटना के नीचे दब इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। आसपास के लोगों का कहना है कि इमारत जर्जर और कमजोर हालत में थी तो इस बिजडिंग में काम को क्यों नहीं रोका गया। इस घटना के जिम्मेदार विभाग और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

52 साल बाद भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में दी आस्ट्रेलिया को मात

पीटीआई। पेरिस

कप्तान हरमनप्रीत सिंह के दो गोल और पी आर श्रीजेश की अदभुत गोलकीपिंग के दम पर भारत ने 52 साल बाद ओलंपिक में आस्ट्रेलिया को हराते हुए आखिरी ग्रुप मैच में इस दिग्गज प्रतिद्वंद्वी पर 3-2 से जीत दर्ज की। भारत ने आखिरी बार पुरुष हॉकी में ओलंपिक में आस्ट्रेलिया को 1972 म्युनिख खेलों में हराया था। वहीं सिडनी ओलंपिक 2000 में आस्ट्रेलिया से 2-2 से ग्रुप मैच ड्रा रहा था। आस्ट्रेलिया ने तोक्यो ओलंपिक 2021 में ग्रुप मैच में भारत पर 7-1 से जीत दर्ज की थी।

तोक्यो ओलंपिक के आखिरी पदक विजेता भारत के लिए जहां श्रीजेश ने सही मायने में दीवार की तरह काम करते हुए असंख्य गोल बचाए तो हर मैच में गोल करते आए हरमनप्रीत ने उस सिलसिले को बरकरार रखा। वहीं पहली बार ओलंपिक खेल रहे डिफेंडर जर्मनप्रीत सिंह और फॉरवर्ड मुखिया के हैं। फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसी भी मंत्री को विभाग का प्रभार (शेष पेज 9)



पेरिस में ओलंपिक मैच के दौरान जीत दर्ज करने के बाद खुश दिख रहे भारतीय खिलाड़ी, दूसरी तरफ आस्ट्रेलिया के यानस केन बाएं से तीसरे तथा साथी खिलाड़ी जेक हार्वी के चेहरे साफ झलकी जा रही हैं।



पेरिस में ओलंपिक मैच के दौरान जीत दर्ज करने के बाद खुश दिख रहे भारतीय खिलाड़ी, दूसरी तरफ आस्ट्रेलिया के यानस केन बाएं से तीसरे तथा साथी खिलाड़ी जेक हार्वी के चेहरे साफ झलकी जा रही हैं।

के उन जखों पर मरहम जरूर लगा होगा जो दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल

2010 के फाइनल में 8-0 और बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल फाइनल में 7

0 से मिली हार के बाद मिले थे। इस मैच से पहले ओलंपिक में भारत ने

आस्ट्रेलिया के खिलाफ 11 मैचों में से सिर्फ तीन (1960 रोम क्वार्टर

फाइनल, 1964 तोक्यो सेमीफाइनल और 1972 म्युनिख ग्रुप मैच) मैच जीते थे जबकि आस्ट्रेलिया ने छह जीते और दो ड्रां खेलें थे। भारतीय टीम पूल चरण में तीन जीत, एक ड्रां और एक हार के साथ बेल्जियम के बाद दूसरे स्थान पर रही और क्वार्टर फाइनल में उसका सामना पूल ए की तीसरे नंबर की टीम से होगा। भारतीय टीम ने पहले क्वार्टर से ही काफी आक्रामक खेल दिखाते हुए शुरूआती 15 मिनट में 2-0 की बढ़त बना ली। भारत को पांचवें मिनट में ही गोल करने का मौका मिला जब जर्मनप्रीत ने बाएं फ्लैंक से सुखजीत को गेंद सौंपी लेकिन वह उसे पकड़

नहीं पाए। आस्ट्रेलिया को 11वें मिनट में पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला जिस पर जेरेमी हैवर्ड का शॉट बाहर से निकल गया। इसके अगले मिनट भारत ने जवाबी हमला बोला और बेल्जियम के खिलाफ पिछले मैच में गोल करने वाले अभिषेक ने तूफानी शॉट पर गेंद सोधे गोल के भीतर डाल दी। आस्ट्रेलिया के गोलकीपर एंड्रयू चार्टर को समझने का समय ही नहीं मिला। भारत ने अगले मिनट पर मिले पेनल्टी कॉर्नर पर हरमनप्रीत के शानदार गोल से बढ़त दुगुनी कर ली। हरमनप्रीत का पेरिस ओलंपिक में यह पांचवां गोल था। पहले क्वार्टर में भारत 2-0 से (शेष पेज 9)

बम-बम भोले के जयकारों से गूंज उठे शिवालय

● नोएडा में सुबह से मंदिरों में जलामिषेक, पुलिस सुरक्षा के बीच कतार में लगे शिव भक्त

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

नोएडा के शिवालय में भगवान शिव का जलामिषेक किया जा रहा है। मंदिरों के कपाट सुबह 4 बजे खोल दिए गए। सुबह आरती के बाद पहले कांडिडियों ने जलामिषेक किया।

इसके बाद कतार में लगाकर श्रद्धालुओं ने जलामिषेक किया। इस मौके पर मंदिरों के बाहर भारी पुलिस बल भी तैनात है। मंदिरों में अत्यवस्था न हो इसके लिए बैरिकेड लगाई गई। मंदिरों के बाहर भी पूजा सामग्री और प्रसाद की दुकानें भी लगाई गईं। सेक्टर-19 स्थित सनातन धर्म मंदिर के पुजारी हरेन्द्र नाथ दुबे ने बताया कि जलामिषेक किया जा रहा है। सुबह



मंदिर में आरती की गई इसके बाद पहले कांडिडियों ने फिर श्रद्धालुओं ने जलामिषेक किया।

पूरे दिन जलामिषेक के बाद शाम को मंदिर में शाम साढ़े सात बजे आरती और उसके बाद रात में भी कांडिडिये जलामिषेक करेंगे। पंडित प्रकाश जोशी ने बताया कि सावन

शिवरात्रि पर चार प्रहर पूजा का मुहूर्त है। उन्होंने बताया कि सावन शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की पूजा रात में होती है। लेकिन इस वर्ष शिवरात्रि दो और तीन अगस्त दोनों दिन मनाई जाएगी। वहीं, आम श्रद्धालुओं को लिए दिन में दो अगस्त को दोपहर 12 बजकर 06 बजे से 12 बजकर 49

दूधेश्वर मंदिर पर 24 घंटे जलामिषेक

गाजियाबाद। शहर के प्राचीन दूधेश्वरनाथ महादेव मंदिर पर 24 घंटे जलामिषेक चल रहा है। दूधेश्वरनाथ महादेव मंदिर के प्रमुख महंत नारायण गिरि ने बताया- इस बार करीब 10 लाख से ज्यादा कांडिडियों के जलामिषेक करने की उम्मीद है। जैसे-जैसे कांडिडिए पहुंच रहे हैं, वे हाजिरी का जल लगातार चढ़ा रहे हैं। दो अगस्त को दोपहर 3:36 बजे तक त्रयोदशी का जल चढ़ाया। इसके बाद से तीन अगस्त को दोपहर तीन बजे तक चतुर्दशी/शिवरात्रि का जल चढ़ाया जाएगा। ज्यादातर पैदल कांडिडिए अपने-अपने शिवालयों पर पहुंच चुके हैं। शुक्रवार को सड़कों पर सिर्फ वहीं कांडिडिए होंगे, जो समय का टारगेट लेकर हरिद्वार से डेक कांडिडि लाते हैं। माना जा रहा है कि शाम के वक्त कुछ रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कांडिडिया का वजह से पुलिस ने ज्यादातर प्रमुख रास्ते बैरिकेडिंग करके बंद किए हुए थे।

सेक्टर-2 लाल मंदिर, सेक्टर-40 शिव शक्ति मंदिर, सेक्टर-56 लक्ष्मी नारायण में बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। यहां सुबह से ही शिव भक्तों द्वारा जलामिषेक किया जा रहा है। इस मौके पर मंदिरों के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं कांडिडि शिविर से मंदिर तक जाने वाले कांडिडियों के लिए लेन तय की गई है।

ताकि रास्ते में कोई परेशानी न हो। लोनी कोतवाली के कोतवाल प्रवीण कुमार सिंह ने मानवता एवं संबन्धशीलता का परिचय देते हुए जहां कांडिडि लेकर आने वाले भोलों की सेवा करते हुए उनकी महम मूट्टी की वही उन्होंने व उनके सहयोगियों ने भोलों के ऊपर पुष्पपर्षा करके उनका हाल-चाल भी जाना। इस क्रम में सिंह ने कांडिडियों को प्रसाद भी खिलाया।

ट्राली पलटने से दो युवकों की मौत

● 20 लोग गंभीर रूप से जखमी, कांडिडि लेने ब्रजघाट जा रहे थे सभी

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

गाजियाबाद के मोदीनगर में हापुड़ गडमुकेश्वर मार्ग पर बाबूगढ़ खानी के पास देर रात डेढ़ बजे के आसपास ट्रैक्टर में लगी दो ट्राली पलटने से निवाड़ी थानाक्षेत्र के गांव डबाना निवासी दो युवकों की मौत हो गई।

सड़क हादसे में 20 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी लोग कांडिडि लेकर गांव डबाना से ब्रजघाट जा रहे थे। हादसे के बाद गांव में मातम का माहौल बना हुआ है। निवाड़ी थानाक्षेत्र के गांव डबाना निवासी 50 से अधिक युवक ट्रैक्टर ट्राली से कांडिडि लेने के लिए गुरुवार रात को जिला हापुड़ के ब्रजघाट जा रहे थे। ट्रैक्टर

में एक साथ तीन ट्राली जोड़ रखी थी। ट्रैक्टर को अमित कुमार चला रहे थे। बताया जा रहा है कि देर रात दो बजे के आसपास जब वह हापुड़ गडमुकेश्वर मार्ग पर बाबूगढ़ के पास पहुंचे तो अचानक ट्रैक्टर के आगे कोई वाहन आ गया। जैसे चालक ने ट्रैक्टर में ब्रेक लगाए तो अचानक ब्रेकाबू होकर पीछे लगी दो ट्राली पलट गई।

ट्राली पलटने से उस पर सवार युवक नीचे दब गए। हादसे के बाद वहां पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को ट्राली के नीचे निकालकर स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे में गांव डबाना निवासी 19 वर्षीय चिराग चौधरी और 21 वर्षीय सोरभ चौधरी को मृतक घोषित कर दिया गया। हादसे में गांव डबाना निवासी सोनू, लोकेन्द्र, रविन्द्र, सुबोध, जगत, मोनू, ब्रजपाल, रविन्द्र, बिजेन्द्र, सौदू, बहादुर, हतित, प्रदीप, अनुज, अमित कुमार सहित 20 से अधिक घायल हो गए। पांच की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद गांव में मातम का माहौल बना हुआ है।

नोएडा में थार से स्टंट करते हुए बनाई रील

नोएडा। नोएडा में हूटर लगी थार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कार में बैठक लोगों ने इसका वीडियो बनाया और वायरल कर दिया।

ट्रैफिक पुलिस ने कार के नंबर के आधार पर 26 हजार का चालान किया। वहीं थार कार की तलाशी का रही है। ये वीडियो नोएडा के सेक्टर-62 का है। थार में पुलिस का सायरन लगा है। वीडियो 11 सेकेंड का है।

रोड पर कभी हाई तो कभी लो स्पीड में थार को चला रहा है। इसके अलावा लाइट भी ब्लिं कर रहा है। सेक्टर-62 की इस रोड पर हैवी ट्रैफिक भी है। जिससे आसपास निकल रहे वाहनों को काफी परेशानी हो रही है। सोशल मीडिया के इंस्टा और प्लेटफार्म पर वीडियो आने के बाद किसी ने पुलिस को एक्स पर टैग करके कारवाही की मांग की।

डीएनडी आज रात 11 बजे से रहेगा बंद

● महारानी बाग जंक्शन से जोड़ने का काम होगा

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा छह लेन एक्सप्रेस कंट्रोल हाईवे को शनिवार को दिल्ली महारानी बाग जंक्शन से जोड़ने का काम होगा। इस कारण शनिवार रात 11 बजे से रविवार सुबह पांच बजे तक डीएनडी होकर आश्रम की ओर जाने वाली सड़क बंद रहेगी।



बता दे नोएडा को दिल्ली से डीएनडी जोड़ता यह लेन एक्सप्रेस कंट्रोल हाईवे को शनिवार को दिल्ली महारानी बाग जंक्शन से जोड़ने का काम होगा। इस कारण शनिवार रात 11 बजे से रविवार सुबह पांच बजे तक डीएनडी होकर आश्रम की ओर जाने वाली सड़क बंद रहेगी। इसके अलावा भी नोएडा के अन्य एंटी पाइंट का प्रयोग वाहन चालक कर सकते हैं। लेकिन जो रास्ता डीएनडी से आश्रम की ओर जाएगा वो पूर्णतः बंद रहेगा। डीएनडी दिल्ली को सीधे नोएडा से जोड़ता है। ये रोड नोएडा में एमपी-1 को जोड़ती है। रोजाना इस रोड पर 1 लाख से ज्यादा दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली आते जाते हैं। ऐसे में ये लाइफ लाइन भी रैड लाइट, अक्षर धाम, सराय काले खां दिल्ली बाईर जा यातायात का लोड बढ़ेगा।

इंडियन ओवरसीज बैंक

मोर्चा एनक्लेव शाखा
केयू-8, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034, ईमेल: iob2260@iob.in

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों के नियम 8(6) के प्रावधानों के तहत)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि इंडियन ओवरसीज बैंक के पास बंधक प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां, जिस पर इंडियन ओवरसीज बैंक के अधिकृत प्राधिकारी ने कब्जा कर लिया है, की बिक्री "जैसा है जहाँ है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ भी है वही है" के आधार पर निम्नलिखित विवरणों के अनुसार की जायेगी:

क्र. सं.	कर्जदार का नाम	इंडियन ओवरसीज बैंक की कब्जा राशि तिथिक 30.06.2024 तक	अचल सम्पत्ति का विवरण	कच्चे का प्रकार	आरंभिक मूल्य	नीलामी की तिथि
1.	श्री. अमित प्रकाश (उपकारकर्ता/बचकाली) पत्नी (अभिनेता) जी 237, ब्लॉक-डी, ईस्ट एक्सप्रेस, फेज-2 विहारो सुभेधान नगर दिल्ली-110086	₹. 19,78,653.85 (रुपये)	उपरोक्त लॉक अप/बचकाली इमारत सात से चौदहवीं मंजिल पर (सह-आपसी) प्लॉट नं. 17, प्लॉट नं. 18, प्लॉट नं. 19, प्लॉट नं. 20, प्लॉट नं. 21, प्लॉट नं. 22, प्लॉट नं. 23, प्लॉट नं. 24, प्लॉट नं. 25, प्लॉट नं. 26, प्लॉट नं. 27, प्लॉट नं. 28, प्लॉट नं. 29, प्लॉट नं. 30, प्लॉट नं. 31, प्लॉट नं. 32, प्लॉट नं. 33, प्लॉट नं. 34, प्लॉट नं. 35, प्लॉट नं. 36, प्लॉट नं. 37, प्लॉट नं. 38, प्लॉट नं. 39, प्लॉट नं. 40, प्लॉट नं. 41, प्लॉट नं. 42, प्लॉट नं. 43, प्लॉट नं. 44, प्लॉट नं. 45, प्लॉट नं. 46, प्लॉट नं. 47, प्लॉट नं. 48, प्लॉट नं. 49, प्लॉट नं. 50, प्लॉट नं. 51, प्लॉट नं. 52, प्लॉट नं. 53, प्लॉट नं. 54, प्लॉट नं. 55, प्लॉट नं. 56, प्लॉट नं. 57, प्लॉट नं. 58, प्लॉट नं. 59, प्लॉट नं. 60, प्लॉट नं. 61, प्लॉट नं. 62, प्लॉट नं. 63, प्लॉट नं. 64, प्लॉट नं. 65, प्लॉट नं. 66, प्लॉट नं. 67, प्लॉट नं. 68, प्लॉट नं. 69, प्लॉट नं. 70, प्लॉट नं. 71, प्लॉट नं. 72, प्लॉट नं. 73, प्लॉट नं. 74, प्लॉट नं. 75, प्लॉट नं. 76, प्लॉट नं. 77, प्लॉट नं. 78, प्लॉट नं. 79, प्लॉट नं. 80, प्लॉट नं. 81, प्लॉट नं. 82, प्लॉट नं. 83, प्लॉट नं. 84, प्लॉट नं. 85, प्लॉट नं. 86, प्लॉट नं. 87, प्लॉट नं. 88, प्लॉट नं. 89, प्लॉट नं. 90, प्लॉट नं. 91, प्लॉट नं. 92, प्लॉट नं. 93, प्लॉट नं. 94, प्लॉट नं. 95, प्लॉट नं. 96, प्लॉट नं. 97, प्लॉट नं. 98, प्लॉट नं. 99, प्लॉट नं. 100, प्लॉट नं. 101, प्लॉट नं. 102, प्लॉट नं. 103, प्लॉट नं. 104, प्लॉट नं. 105, प्लॉट नं. 106, प्लॉट नं. 107, प्लॉट नं. 108, प्लॉट नं. 109, प्लॉट नं. 110, प्लॉट नं. 111, प्लॉट नं. 112, प्लॉट नं. 113, प्लॉट नं. 114, प्लॉट नं. 115, प्लॉट नं. 116, प्लॉट नं. 117, प्लॉट नं. 118, प्लॉट नं. 119, प्लॉट नं. 120, प्लॉट नं. 121, प्लॉट नं. 122, प्लॉट नं. 123, प्लॉट नं. 124, प्लॉट नं. 125, प्लॉट नं. 126, प्लॉट नं. 127, प्लॉट नं. 128, प्लॉट नं. 129, प्लॉट नं. 130, प्लॉट नं. 131, प्लॉट नं. 132, प्लॉट नं. 133, प्लॉट नं. 134, प्लॉट नं. 135, प्लॉट नं. 136, प्लॉट नं. 137, प्लॉट नं. 138, प्लॉट नं. 139, प्लॉट नं. 140, प्लॉट नं. 141, प्लॉट नं. 142, प्लॉट नं. 143, प्लॉट नं. 144, प्लॉट नं. 145, प्लॉट नं. 146, प्लॉट नं. 147, प्लॉट नं. 148, प्लॉट नं. 149, प्लॉट नं. 150, प्लॉट नं. 151, प्लॉट नं. 152, प्लॉट नं. 153, प्लॉट नं. 154, प्लॉट नं. 155, प्लॉट नं. 156, प्लॉट नं. 157, प्लॉट नं. 158, प्लॉट नं. 159, प्लॉट नं. 160, प्लॉट नं. 161, प्लॉट नं. 162, प्लॉट नं. 163, प्लॉट नं. 164, प्लॉट नं. 165, प्लॉट नं. 166, प्लॉट नं. 167, प्लॉट नं. 168, प्लॉट नं. 169, प्लॉट नं. 170, प्लॉट नं. 171, प्लॉट नं. 172, प्लॉट नं. 173, प्लॉट नं. 174, प्लॉट नं. 175, प्लॉट नं. 176, प्लॉट नं. 177, प्लॉट नं. 178, प्लॉट नं. 179, प्लॉट नं. 180, प्लॉट नं. 181, प्लॉट नं. 182, प्लॉट नं. 183, प्लॉट नं. 184, प्लॉट नं. 185, प्लॉट नं. 186, प्लॉट नं. 187, प्लॉट नं. 188, प्लॉट नं. 189, प्लॉट नं. 190, प्लॉट नं. 191, प्लॉट नं. 192, प्लॉट नं. 193, प्लॉट नं. 194, प्लॉट नं. 195, प्लॉट नं. 196, प्लॉट नं. 197, प्लॉट नं. 198, प्लॉट नं. 199, प्लॉट नं. 200, प्लॉट नं. 201, प्लॉट नं. 202, प्लॉट नं. 203, प्लॉट नं. 204, प्लॉट नं. 205, प्लॉट नं. 206, प्लॉट नं. 207, प्लॉट नं. 208, प्लॉट नं. 209, प्लॉट नं. 210, प्लॉट नं. 211, प्लॉट नं. 212, प्लॉट नं. 213, प्लॉट नं. 214, प्लॉट नं. 215, प्लॉट नं. 216, प्लॉट नं. 217, प्लॉट नं. 218, प्लॉट नं. 219, प्लॉट नं. 220, प्लॉट नं. 221, प्लॉट नं. 222, प्लॉट नं. 223, प्लॉट नं. 224, प्लॉट नं. 225, प्लॉट नं. 226, प्लॉट नं. 227, प्लॉट नं. 228, प्लॉट नं. 229, प्लॉट नं. 230, प्लॉट नं. 231, प्लॉट नं. 232, प्लॉट नं. 233, प्लॉट नं. 234, प्लॉट नं. 235, प्लॉट नं. 236, प्लॉट नं. 237, प्लॉट नं. 238, प्लॉट नं. 239, प्लॉट नं. 240, प्लॉट नं. 241, प्लॉट नं. 242, प्लॉट नं. 243, प्लॉट नं. 244, प्लॉट नं. 245, प्लॉट नं. 246, प्लॉट नं. 247, प्लॉट नं. 248, प्लॉट नं. 249, प्लॉट नं. 250, प्लॉट नं. 251, प्लॉट नं. 252, प्लॉट नं. 253, प्लॉट नं. 254, प्लॉट नं. 255, प्लॉट नं. 256, प्लॉट नं. 257, प्लॉट नं. 258, प्लॉट नं. 259, प्लॉट नं. 260, प्लॉट नं. 261, प्लॉट नं. 262, प्लॉट नं. 263, प्लॉट नं. 264, प्लॉट नं. 265, प्लॉट नं. 266, प्लॉट नं. 267, प्लॉट नं. 268, प्लॉट नं. 269, प्लॉट नं. 270, प्लॉट नं. 271, प्लॉट नं. 272, प्लॉट नं. 273, प्लॉट नं. 274, प्लॉट नं. 275, प्लॉट नं. 276, प्लॉट नं. 277, प्लॉट नं. 278, प्लॉट नं. 279, प्लॉट नं. 280, प्लॉट नं. 281, प्लॉट नं. 282, प्लॉट नं. 283, प्लॉट नं. 284, प्लॉट नं. 285, प्लॉट नं. 286, प्लॉट नं. 287, प्लॉट नं. 288, प्लॉट नं. 289, प्लॉट नं. 290, प्लॉट नं. 291, प्लॉट नं. 292, प्लॉट नं. 293, प्लॉट नं. 294, प्लॉट नं. 295, प्लॉट नं. 296, प्लॉट नं. 297, प्लॉट नं. 298, प्लॉट नं. 299, प्लॉट नं. 300, प्लॉट नं. 301, प्लॉट नं. 302, प्लॉट नं. 303, प्लॉट नं. 304, प्लॉट नं. 305, प्लॉट नं. 306, प्लॉट नं. 307, प्लॉट नं. 308, प्लॉट नं. 309, प्लॉट नं. 310, प्लॉट नं. 311, प्लॉट नं. 312, प्लॉट नं. 313, प्लॉट नं. 314, प्लॉट नं. 315, प्लॉट नं. 316, प्लॉट नं. 317, प्लॉट नं. 318, प्लॉट नं. 319, प्लॉट नं. 320, प्लॉट नं. 321, प्लॉट नं. 322, प्लॉट नं. 323, प्लॉट नं. 324, प्लॉट नं. 325, प्लॉट नं. 326, प्लॉट नं. 327, प्लॉट नं. 328, प्लॉट नं. 329, प्लॉट नं. 330, प्लॉट नं. 331, प्लॉट नं. 332, प्लॉट नं. 333, प्लॉट नं. 334, प्लॉट नं. 335, प्लॉट नं. 336, प्लॉट नं. 337, प्लॉट नं. 338, प्लॉट नं. 339, प्लॉट नं. 340, प्लॉट नं. 341, प्लॉट नं. 342, प्लॉट नं. 343, प्लॉट नं. 344, प्लॉट नं. 345, प्लॉट नं. 346, प्लॉट नं. 347, प्लॉट नं. 348, प्लॉट नं. 349, प्लॉट नं. 350, प्लॉट नं. 351, प्लॉट नं. 352, प्लॉट नं. 353, प्लॉट नं. 354, प्लॉट नं. 355, प्लॉट नं. 356, प्लॉट नं. 357, प्लॉट नं. 358, प्लॉट नं. 359, प्लॉट नं. 360, प्लॉट नं. 361, प्लॉट नं. 362, प्लॉट नं. 363, प्लॉट नं. 364, प्लॉट नं. 365, प्लॉट नं. 366, प्लॉट नं. 367, प्लॉट नं. 368, प्लॉट नं. 369, प्लॉट नं. 370, प्लॉट नं. 371, प्लॉट नं. 372, प्लॉट नं. 373, प्लॉट नं. 374, प्लॉट नं. 375, प्लॉट नं. 376, प्लॉट नं. 377, प्लॉट नं. 378, प्लॉट नं. 379, प्लॉट नं. 380, प्लॉट नं. 381, प्लॉट नं. 382, प्लॉट नं. 383, प्लॉट नं. 384, प्लॉट नं. 385, प्लॉट नं. 386, प्लॉट नं. 387, प्लॉट नं. 388, प्लॉट नं. 389, प्लॉट नं. 390, प्लॉट नं. 391, प्लॉट नं. 392, प्लॉट नं. 393, प्लॉट नं. 394, प्लॉट नं. 395, प्लॉट नं. 396, प्लॉट नं. 397, प्लॉट नं. 398, प्लॉट नं. 399, प्लॉट नं. 400, प्लॉट नं. 401, प्लॉट नं. 402, प्लॉट नं. 403, प्लॉट नं. 404, प्लॉट नं. 405, प्लॉट नं. 406, प्लॉट नं. 407, प्लॉट नं. 408, प्लॉट नं. 409, प्लॉट नं. 410, प्लॉट नं. 411, प्लॉट नं. 412, प्लॉट नं. 413, प्लॉट नं. 414, प्लॉट नं. 415, प्लॉट नं. 416, प्लॉट नं. 417, प्लॉट नं. 418, प्लॉट नं. 419, प्लॉट नं. 420, प्लॉट नं. 421, प्लॉट नं. 422, प्लॉट नं. 423, प्लॉट नं. 424, प्लॉट नं. 425, प्लॉट नं. 426, प्लॉट नं. 427, प्लॉट नं. 428, प्लॉट नं. 429, प्लॉट नं. 430, प्लॉट नं. 431, प्लॉट नं. 432, प्लॉट नं. 433, प्लॉट नं. 434, प्लॉट नं. 435, प्लॉट नं. 436, प्लॉट नं. 437, प्लॉट नं. 438, प्लॉट नं. 439, प्लॉट नं. 440, प्लॉट नं. 441, प्लॉट नं. 442, प्लॉट नं. 443, प्लॉट नं. 444, प्लॉट नं. 445, प्लॉट नं. 446, प्लॉट नं. 447, प्लॉट नं. 448, प्लॉट नं. 449, प्लॉट नं. 450, प्लॉट नं. 451, प्लॉट नं. 452, प्लॉट नं. 453, प्लॉट नं. 454, प्लॉट नं. 455, प्लॉट नं. 456, प्लॉट नं. 457, प्लॉट नं. 458, प्लॉट नं. 459, प्लॉट नं. 460, प्लॉट नं. 461, प्लॉट नं. 462, प्लॉट नं. 463, प्लॉट नं. 464, प्लॉट नं. 465, प्लॉट नं. 466, प्लॉट नं. 467, प्लॉट नं. 468, प्लॉट नं. 469, प्लॉट नं. 470, प्लॉट नं. 471, प्लॉट नं. 472, प्लॉट नं. 473, प्लॉट नं. 474, प्लॉट नं. 475, प्लॉट नं. 476, प्लॉट नं. 477, प्लॉट नं. 478, प्लॉट नं. 479, प्लॉट नं. 480, प्लॉट नं. 481, प्लॉट नं. 482, प्लॉट नं. 483, प्लॉट नं. 484, प्लॉट नं. 485, प्लॉट नं. 486, प्लॉट नं. 487, प्लॉट नं. 488, प्लॉट नं. 489, प्लॉट नं. 490, प्लॉट नं. 491, प्लॉट नं. 492, प्लॉट नं. 493, प्लॉट नं. 494, प्लॉट नं. 495, प्लॉट नं. 496, प्लॉट नं. 497, प्लॉट नं. 498, प्लॉट नं. 499, प्लॉट नं. 500, प्लॉट नं. 501, प्लॉट नं. 502, प्लॉट नं. 503, प्लॉट नं. 504, प्लॉट नं. 505, प्लॉट नं. 506, प्लॉट नं. 507, प्लॉट नं. 508, प्लॉट नं. 509, प्लॉट नं. 510, प्लॉट नं. 511, प्लॉट नं. 512, प्लॉट नं. 513, प्लॉट नं. 514, प्लॉट नं. 515, प्लॉट नं. 516, प्लॉट नं. 517, प्लॉट नं. 518, प्लॉट नं. 519, प्लॉट नं. 520, प्लॉट नं. 521, प्लॉट नं. 522, प्लॉट नं. 523, प्लॉट नं. 524, प्लॉट नं. 525, प्लॉट नं. 526, प्लॉट नं. 527, प्लॉट नं. 528, प्लॉट नं. 529, प्लॉट नं. 530, प्लॉट नं. 531, प्लॉट नं. 532, प्लॉट नं. 533, प्लॉट नं. 534, प्लॉट नं. 535, प्लॉट नं. 536, प्लॉट नं. 537, प्लॉट नं. 538, प्लॉट नं. 539, प्लॉट नं. 540, प्लॉट नं. 541, प्लॉट नं. 542, प्लॉट नं. 543, प्लॉट नं. 544, प्लॉट नं. 545, प्लॉट नं. 546, प्लॉट नं. 547, प्लॉट नं. 548, प्लॉट नं. 549, प्लॉट नं. 550, प्लॉट नं. 551, प्लॉट नं. 552, प्लॉट नं. 553, प्लॉट नं. 554, प्लॉट नं. 555, प्लॉट नं. 556, प्लॉट नं. 557, प्लॉट नं. 558, प्लॉट नं. 559, प्लॉट नं. 560, प्लॉट नं. 561, प्लॉट नं. 562, प्लॉट नं. 563, प्लॉट नं. 564, प्लॉट नं. 565, प्लॉट नं. 566, प्लॉट नं. 567, प्लॉट नं. 568, प्लॉट नं. 569, प्लॉट नं. 570, प्लॉट नं. 571, प्लॉट नं. 572, प्लॉट नं. 573, प्लॉट नं. 574, प्लॉट नं. 575, प्लॉट नं. 576, प्लॉट नं. 577, प्लॉट नं. 578, प्लॉट नं. 579, प्लॉट नं. 580, प्लॉट नं. 581, प्लॉट नं. 582, प्लॉट नं. 583, प्लॉट नं. 584, प्लॉट नं. 585, प्लॉट नं. 586, प्लॉट नं. 587, प्लॉट नं. 588, प्लॉट नं. 589, प्लॉट नं. 590, प्लॉट नं. 591, प्लॉट नं. 592, प्लॉट नं. 593, प्लॉट नं. 594, प्लॉट नं. 595, प्लॉट नं. 596, प्लॉट नं. 597, प्लॉट नं. 598, प्लॉट नं. 599, प्लॉट नं. 600, प्लॉट नं. 601, प्लॉट नं. 602, प्लॉट नं. 603, प्लॉट नं. 604, प्लॉट नं. 605, प्लॉट नं. 606, प्लॉट नं. 607, प्लॉट नं. 608, प्लॉट नं. 609, प्लॉट नं. 610, प्लॉट नं. 611, प्लॉट नं. 612, प्लॉट नं. 613, प्लॉट नं. 614, प्लॉट नं. 615, प्लॉट नं. 616, प्लॉट नं. 617, प्लॉट नं. 618, प्लॉट नं. 619, प्लॉट नं. 620, प्लॉट नं. 621, प्लॉट नं. 622, प्लॉट नं. 623, प्लॉट नं. 624, प्लॉट नं. 625, प्लॉट नं. 626, प्लॉट नं. 627, प्लॉट नं. 628, प्लॉट नं. 629, प्लॉट नं. 630, प्लॉट नं. 631, प्लॉट नं. 632, प्लॉट नं. 633, प्लॉट नं. 634, प्लॉट नं. 635, प्लॉट नं. 636, प्लॉट नं. 637, प्लॉट नं. 638, प्लॉट नं. 639, प्लॉट नं. 640, प्लॉट नं. 641, प्लॉट नं. 642, प्लॉट नं. 643, प्लॉट नं. 644, प्लॉट नं. 645, प्लॉट नं. 646, प्लॉट नं. 647, प्लॉट नं. 648, प्लॉट नं. 649, प्लॉट नं. 650, प्लॉट नं. 651, प्लॉट नं. 652, प्लॉट नं. 653, प्लॉट नं. 654, प्लॉट नं. 655, प्लॉट नं. 656, प्लॉट नं. 657, प्लॉट नं. 658, प्लॉट नं. 659, प्लॉट नं. 660, प्लॉट नं. 661, प्लॉट नं. 662, प्लॉट नं. 663, प्लॉट नं. 664, प्लॉट नं. 665, प्लॉट नं. 666, प्लॉट नं. 667, प्लॉट नं. 668, प्लॉट नं. 669, प्लॉट नं. 670, प्लॉट नं. 671, प्लॉट नं. 672, प्लॉट नं. 673, प्लॉट नं. 674, प्लॉट नं. 675, प्लॉट नं. 676, प्लॉट नं. 677, प्लॉट नं. 678, प्लॉट नं. 679, प्लॉट नं.			

खोड़ा कॉलोनी हादसे पर आरोप प्रत्यारोप तेज

जिस नाले में डूबने में मां-बेटे की मौत हुई वह एमसीडी के अंतर्गत आता है : एलजी

करीब 1000 मीटर नाले की न तो गाद निकाली गई है और न ही उसे ढका गया



पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

तो गाद निकाली गई है और न ही उसे ढका गया है। उपराज्यपाल कार्यालय के अनुसार इस नाले की कुल लंबाई 1350 मीटर है। 1000 मीटर नाला दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो उसको 17 अप्रैल 2023 को सौंपा गया था वह भी तब जब दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी के नियंत्रण में थी। नाले के कुल 350 मीटर का क्षेत्र, दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है। डीडीए ने अपने हिस्से में आने वाले नाले से गाद निकालने का काम हाल ही में किया है, जिसके बाद इस पूरे हिस्से को आरसीसी के स्लैब से ढक दिया गया है। कूड़े के प्रवाह को रोकने के लिए, डीडीए ने नाले के एमसीडी-डीडीए जंक्शन पर स्टील स्क्रीन भी लगाई थी। स्थानीय लोगों के अनुसार यह दुखद घटना परसों शाम को घटी, जिसमें गोल्डन पैलेस के सामने एक मां और एक बच्चे की नाले में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। उनके शव एमसीडी और डीडीए ड्रेन के जंक्शन प्वाइंट पर बरामद किए गए, जहां कचरा प्रवाह को रोकने के लिए डीडीए द्वारा स्टील स्क्रीन लगाई गई थी। यह प्वाइंट गोल्डन पैलेस से लगभग 500 मीटर नीचे की ओर है। दिल्ली पुलिस ने मां-बच्चे के शवों को अस्पताल पहुंचाया। एमसीडी के अधिकार क्षेत्र के 1000 मीटर लंबे नाला न तो ढका हुआ है और न ही नाले से गाद निकाली गई है।

यह कहना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आम आदमी पार्टी और उसके नेता लोगों की मौत से जुड़ी त्रासदियों के बावजूद भी आरोप-प्रत्यारोप में शामिल हैं। 10 वर्षों की निष्क्रियता, विकास की कमी और दिल्ली में हर स्तर पर नागरिक, बुनियादी ढांचे की बदतर स्थिति, जिसका विज्ञापनों और बयानों के माध्यम से प्रचार किया गया था, की सच्चाई अब दिल्ली वालों को दिखाई देने लगी है। यह स्पष्ट है कि दोष और जवाबदेही से बचने के लिए उन्होंने अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए बहाने तलाशने का अपना पुराना खेल शुरू कर दिया है।

उपराज्यपाल विनय कुमार सम्बन्धी ने आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं व मंत्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी विफलताओं और जिम्मेदारियों को स्वीकार करें और सुधारात्मक उपाय करें। उनके रिकॉर्ड और स्वभाव को देखते हुए उनसे माफी की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

मालीवाल मारपीट मामले में बिभव कुमार की याचिका खारिज

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार को उस याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल पर मुआवजी आवास पर कथित हमले के सिलसिले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा, याचिका खारिज की जाती है। कुमार वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। आरोप है कि उन्होंने 13 मई को केजरीवाल के सरकारी आवास पर मालीवाल पर

हमला किया था। उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। कुमार ने याचिका में अपनी गिरफ्तारी को अवैध और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए (पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का नोटिस) के प्रावधानों का घोर उल्लंघन तथा कानून के विरुद्ध घोषित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।

दिल्ली पुलिस ने याचिका का विरोध किया था और कहा कि कुमार को जल्दबाजी में गिरफ्तार नहीं किया गया था, उन्हें कानून के अनुसार हिरासत में लिया गया था। कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत

पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान करें उपराज्यपाल : प्रियंका कक्कड़



नई दिल्ली। आम आदमी

पार्टी ने मयूर विहार फेस तीन की दुखद घटना के बाद भाजपा और उपराज्यपाल पर तीखा ह मला बोला है। आप की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि डीडीए की लापरवाही के चलते खुले नाले में गिरने से मां-बेटे की जान चली गई। एलजी और भाजपा के सांसद पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गए।

राजेंद्र नगर की घटना के बाद तो एलजी वहां राजनीति करने गए थे लेकिन छात्रों ने नारेबाजी कर उनको वापस भेज दिया था। आप की मांग है कि एलजी पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की घोषणा करें और नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दें। प्रियंका कक्कड़ ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में इस दुखद घटना पर भाजपा

डी-सिल्टिंग की शिकायत सीबीआई में कराई दर्ज : सचदेवा

नई दिल्ली। प्रदेश भाजपा ने नालों की डी-सिल्टिंग की शिकायत सीबीआई में दर्ज कराई है। शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया है कि बारिश होने पर सड़कों पर पानी जमा होना सामान्य है, लेकिन इस साल दिल्ली में 15 से 30 मिनट की बारिश के बाद भी सड़कों पर घंटों जलभराव हो जाता है।



अध्यक्ष

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने गत गुरुवार को डी-सिल्टिंग घोटाले पर सवाल उठाए थे और बताया कि पार्टी द्वारा गठित एक आंतरिक टीम जिसमें विधानसभा के उप नेता मोहन सिंह बिष्ट और नगर निगम में विपक्ष के नेता सरदार राजा इकबाल सिंह शामिल हैं, ने स्थिति का अध्ययन किया और समझा कि 27 जून तक मंत्री

आतिशो और सौरभ भारद्वाज के साथ मेयर डॉ. शेली ओबेरॉय यह दावा कर रहे थे कि नालों और सीवरों की 90 से 95 फीसदी सफाई हो चुकी है, लेकिन 28 जून की पहली बारिश और उसके बाद की बारिश ने दिखाया कि कोई सफाई नहीं हुई है क्योंकि दिल्ली कुछ ही मिनटों में झील में तब्दील हो जाती है। कल पार्टी ने डी-सिल्टिंग घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की थी और आज पार्टी नेताओं ने शिकायत दर्ज कराई। बिष्ट और बृजेश राय ने कहा कि 10 मिनट की बारिश में दिल्ली को डूबते देखना शर्मनाक है और रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार के विभागों ने कोई भी नाले की गाद समर्पित लैंडफिल साइट पर नहीं भेजी है।

पुलिस के जल्दी याई में लगी आग

नई दिल्ली। वजीरवाद इलाके में स्थित दिल्ली पुलिस के एक जल्दी याई में शुक्रवार को आग लग गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सात दमकल वाहनों को मौके पर भेजा गया है। मालखाने में आग लगने से आसमान में धुएं का गुब्बारा छा गया।

धुआं फैलने के चलते दूर-दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आग की वीथियों ओरहटे मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है।

गोकुलपुरी रोडरेज मामले में महिला को गोली मारने वाला मुठभेड़ में गिरफ्तार

● आरोपी मजीद चौधरी पर तीन अपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं, छह वर्ष की सजा भी काट चुका है



पुलिस मुठभेड़ में घायल आरोपी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी में रोड रेज के दौरान महिला की हत्या के मामले दिल्ली में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी।

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी माजिद चौधरी के दोनों पैर में गोली लगी। चौधरी पर तीन अपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। वह पहले भी छह वर्ष की सजा भी काट चुका है। माजिद के कब्जे से एक 7.65 एएमएम की पिस्तौल, जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। इसके अलावा गांधी नगर के पुराने सीलमपुर इलाके से चोरी की गई एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पुलिस उपायुक्त जॉय टिर्की के मुताबिक उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद के रहने वाले माजिद चौधरी का नाम तीन अपराधिक मामलों में दर्ज है। वर्ष 2015 में

साहिबाबाद में हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और वह छह साल जेल में रहा। वह 2021 में जेल से बाहर आया। उसे 2022 में गाजियाबाद के ही शालीमार गार्डन में हत्या के प्रयास के मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। उसने पांच महीने जेल में बिताए। इसके बाद वह जमानत पर बाहर आया और 2022 में शालीमार गार्डन में हत्या के प्रयास के एक अन्य मामले में तीसरी बार गिरफ्तार कर लिया गया। उसके अपराधिक रिकार्ड की जांच की जा रही है। मालूम हो कि 31 जुलाई को गोकुलपुरी इलाके में हुई रोड रेज की

घटना में गोली लगने से सिमरनजीत कौर की मौत हुई थी। वह अपने पिता हीरा सिंह के साथ मौजूद थी और जा रही थी। वारदात से पहले गोकुलपुरी प्लाईओवर के पास दोपहिया वाहन सवार एक व्यक्ति के साथ हीरा सिंह की कहासुनी हो गई थी क्योंकि उनके वाहन एक-दूसरे से टकराने वाले थे। इसके बाद, एक व्यक्ति ने प्लाई ओवर पर एक गोली चलाई, जो सिमरनजीत के गर्दन के पास जा लगी। उसे जौटीवी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

सर्दियों में प्रदूषण से निपटने की तैयारी शुरू

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

● पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पर्यावरण विभाग, डीपीसीसी और विकास विभाग के अधिकारियों के साथ की उच्चस्तरीय बैठक

आम आदमी पार्टी की सरकार ने सर्दी के मौसम में प्रदूषण को नियंत्रित करने की तैयारी शुरू कर दी है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने संबंधित विभागों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। राय ने बताया कि 21 अगस्त को पर्यावरण विशेषज्ञों के साथ सेव एनवायरनमेंट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। एक्सपर्ट्स की राय के आधार पर बिंदू एक्शन प्लान बनाया जाएगा। इस वर्ष जन भागीदारी के द्वारा प्रदूषण को नियंत्रित करना सरकार का मुख्य उद्देश्य रहेगा। गोपाल राय ने बताया कि बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण सुझाव आए, जिनमें मुख्य तौर पर कुछ फोकस बिंदु चिह्नित किए गए हैं। जिसको केंद्र बिंदु बनाकर काम किया जाएगा। जैसे धूल प्रदूषण, वाहनों से होने वाले प्रदूषण, पारली की समस्या है, जगह-जगह जलाए जाने वाला कूड़ा है। सर्दियों के मौसम में हर इलाके में जगह-जगह कूड़ा जलाया जाता है।

सिख दंगा में टाइलर के खिलाफ 16 को तय हो सकता है आरोप

नई दिल्ली। अदालत 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश गुरुद्वारा के सामने तीन व्यक्तियों की कथित हत्या से संबंधित मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइलर के खिलाफ आरोप तय करने के बारे में अपना आदेश 16 अगस्त को पारित कर सकती है। यह आदेश शुक्रवार को आने वाला था, लेकिन इसे टाल दिया गया, क्योंकि विशेष सीबीआई न्यायाधीश राकेश सियाल छुट्टी पर थे। न्यायाधीश ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुनिश्चित रख लिया था। एक गवाह ने पहले आरोपपत्र में कहा था कि टाइलर एक नवंबर 1984 को गुरुद्वारा के सामने एक सफेद एंबेसडर कार से बाहर निकले और भीड़ को यह कहकर उकसाया कि सिखों को मार डालो, उन्होंने हमारी मां को मार डाला है, जिसके कारण तीन लोगों की हत्या हुई। पिछले साल अगस्त में एक सत्र अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की जमानत राशि पर टाइलर को अग्रिम

संक्षिप्त समाचार

स्वाधीनता संग्राम में लोक की भूमिका पर संगोष्ठी
नई दिल्ली। इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय, दिल्ली और भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय स्वाधीनता संग्राम में लोक की भूमिका विषय पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में मुख्य अध्यक्ष दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिणी दिल्ली परिसर के निदेशक प्रो. श्रीप्रकाश सिंह, मुख्य अतिथि दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग की अध्यक्ष प्रो. वरिष्ठ आलोचक प्रो. ओमप्रकाश सिंह, आईसीएचआर के उप निदेशक डॉ. नौशाद अली उपस्थित रहे। निदेशक प्रो. श्रीप्रकाश सिंह ने कहा भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अनेक महान सेनानियों ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। आज उन्के बलिदान और त्याग को स्मरण कर भारतीयता को जागृत करने की आवश्यकता है और इसमें लोक साहित्य बहुत अधिक माध्यम का कार्य करता है। कार्यक्रम में राजीव रंजन, प्राचार्या प्रो. पूनम कुमरिया, बुद्धा चन्द्रशेखर, प्रो. संध्या सिंह, प्रो. संतोषा कुमार, परवीन रानी, प्रो. महेन्द्रपाल शर्मा, प्रो. पूनम कुमरिया ने अपने विचार रखे।

इंटरनेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम आयोजित



नई दिल्ली। उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में उपभोक्ताओं को बिजली सफाई करने वाली पावर यूटिलिटी टाटा पावर-डीडीएल ने सेनेगलनेशनल इलेक्ट्रिसिटी एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए बैस्ट प्रैक्टिसेज इन स्मार्ट मीटरिंग पर एक विस्तृत ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया। प्रोग्राम का आयोजन बिजली वितरण के विभिन्न क्षेत्रों में, कंपनी की क्षमता निर्माण के विजन के अनुरूप किया गया था। गजानन एस काले, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, टाटा पावर-डीडीएल ने कहा, हमें स्मार्ट मीटरिंग के क्षेत्र में अपनी निपुणता शेर करते हुए खुशी है। स्मार्ट मीटरिंग टेकनोलॉजी ने पावर सेक्टर को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। यूटिलिटी की जरूरी जानकारी और कोशिश प्रदान कर, हम अधिक सस्टेनेबिल तथा एफिशिएंट पावर इकोसिस्टम का निर्माण करने में योगदान करेंगे।

नगर निगम ने 25 बेसमेंट सील किए, 17 मालिकों को भेजा नोटिस

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

नगर निगम ने राजधानी के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से कोचिंग सेंटर, कार्यालय या अन्य वाणिज्यिक संस्थाओं के तौर पर संचालित हो रहे 25 बेसमेंट को 28 जुलाई से 31 जुलाई के बीच सील कर दिया।

नगर निगम ने इस अवधि के दौरान 17 मकान मालिकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। इसमें बताया गया कि मध्य दिल्ली के राजेंद्र नगर, पश्चिमी दिल्ली के पटेल नगर और रणजीत नगर इलाकों में स्थित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आंकड़ों के मुताबिक,

● राजेंद्र नगर हादसे के बाद सख्ती

ओल्ड राजेंद्र नगर में बड़ा बाजार मार्ग पर 18 बेसमेंट सील किए गए हैं। इसमें बताया ग2399ी कि इन तीन क्षेत्रों में कुल 15 संपत्तियों पर कार्रवाई की गई, जिनमें से सात अकेले ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित हैं। एमसीडी ने इस अवधि के दौरान लगभग 185 संपत्तियों का निरीक्षण किया है। नगर निगम ने कहा कि कानून का उल्लंघन कर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे बेसमेंट को सील कर दिया गया है।

आशा किरण में मौतों को लेकर भाजपा का प्रदर्शन

● कर्मचारी को वेतन नहीं, आश्रम में फैली है अव्यवस्था: विजेन्द्र गुप्ता

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने रोहिणी स्थित आशा किरण आश्रय गृह में लड़कियों की मौत के मामले में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की अलोचना की और आश्रय गृह में अनियमितता और लापरवाही का आरोप लगाया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने रोहिणी स्थित आशा किरण आश्रय गृह में मौतों के लिए आप सरकार को जिम्मेदार ठहराया और दिल्ली की मंत्री आतिशी



पत्रकारों के सवालों को जवाब देते विधायक विजेन्द्र गुप्ता।

से घटना की जिम्मेदारी लेने की मांग की। भाजपा विधायक विजेन्द्र गुप्ता और अन्य पार्टी नेताओं ने आश्रय गृह का दौरा करने की कोशिश की और जब उनके लिए आश्रय गृह के द्वार नहीं खोले गए, तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। गुप्ता ने आरोप लगाया, यहां पूरी तरह अव्यवस्था है। कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है और यहां



शिवरात्रि के अवसर पर राजधानी के मंदिरों में बम-बम भोले के जयकारों के बीच शिवलिंग पर जल चढ़ते भक्त। फोटो: रंजन डिमरी

यूपीएससी उम्मीदवारों के नाम पर बनेंगे पुस्तकालय: मेयर

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

महापौर शैली ओबेरॉय ने प्रस्ताव दिया है कि पिछले महीने एक हादसे में मारे गए सिविल सेवा अभ्यर्थियों के नाम पर 4 पुस्तकालय स्थापित किए जाएं। राजेंद्र नगर इलाके में 27 जुलाई को एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से सिविल सेवा की तैयारी कर रहे तीन विद्यार्थी डूब गए थे जबकि एक सप्ताह पहले मुखर्जी नगर में एक अन्य छात्र की कर्त लगने से मौत हो गई थी। हालांकि, इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि इन पुस्तकालयों का नाम क्या होगा। शैली ओबेरॉय द्वारा दिल्ली नगर निगम आयुक्त को लिखे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि इनका निर्माण दिल्ली में चार स्थानों - राजेंद्र नगर, मुखर्जी

गुप्ता ने कहा, इन मौतों के पीछे की वजह सरकार की लापरवाही है। वे घटना को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और जवाब देने से इंकार कर रहे हैं। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया कि आशा किरण आश्रय गृह को वंचित और शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों का खयाल रखना है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही और चूक की वजह से मौत हो रही है। उन्होंने कहा, हमने आशा किरण के प्रबंधन से मौतों के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन आश्रय गृह का द्वार तक नहीं खोला गया। इस बीच, एमसीडीब्ल्यू ने आश्रय गृह का दौरा करने के लिए एक टीम तैनात की। आश्रय गृह के दौरे के बाद एमसीडीब्ल्यू प्रमुख रेखा शर्मा ने पत्रकार वार्ता कर घटना के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया।

नगर, पटेल नगर और बेर सराय - में मृतक छात्रों के नाम पर एमसीडी द्वारा किया जा सकता है। ये क्षेत्र सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग हब हैं और बड़ी संख्या में छात्र इन इलाकों में छात्रावासों और पीजी आवासों में रहते हैं। वृहस्पतिवार को एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार को लिखे पत्र में महापौर ने कहा कि राजेंद्र नगर में कुछ दिन पहले हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद, दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बहुरत से छात्रों ने सार्वजनिक और सरकारी पुस्तकालयों की कमी का मुद्दा उठाया है। एमसीडी पुस्तकालयों की स्थापना का प्रस्ताव रखा कि छात्रों ने पुस्तकालयों की मांग उठाई है क्योंकि बहुत से छात्र भारी सटस्पता शुल्क का भुगतान नहीं कर सकते।

वायनाड त्रासदी पर्यावरणीय चेतावनी

वायनाड त्रासदी पर्यावरणीय चेतावनी अनदेखा करने के खतरनाक नतीजे प्रदर्शित करती है। लेकिन भारत में दुर्भाग्य से त्योहारों से लेकर त्रासदी तक हर चीज के 'राजनीतिकरण' की बुरी आदत विकसित हुई है और इसका प्रयोग विरोधियों के खिलाफ अवसर के रूप में किया जाता है। केरल के वायनाड में त्रासद भूस्खलन से 170 से अधिक लोगों की जानें गई हैं, लेकिन इसका भी राजनीतिक प्रयोग हो रहा है। इसने राज्य और केन्द्र सरकार के नेताओं के बीच गर्मागर्म बहस को जन्म दिया है। इस त्रासदी में जीवन और संपत्ति का भारी विनाश हुआ है और इसने आपदा के लिए तैयारी तथा पर्यावरणीय अनदेखी जैसे मुद्दों को सामने ला दिया है। भूस्खलन के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य सरकार को जल्दी चेतावनी मिल गई थी, पर वह आवश्यक बचाव के उपाय करने में विफल रही। उन्होंने लापरवाही के लिए राज्य सरकार की आलोचना करते हुए संकेत किया कि यदि समय पर कार्रवाई की गई होती तो अनेक लोगों को जीवन बचाया जा सकता था। इस पर केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन ने फौरन शाह के दावों को खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने सभी उपलब्ध चेतावनियों पर कार्रवाई की और उसने संभावित प्राकृतिक आपदा का प्रभाव कम करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए थे। विजयन ने जोर दिया कि भूस्खलन की अभूतपूर्व विकरालता शीघ्र चेतावनियों के अनुमान से बहुत अधिक थी और राज्य के आपदा प्रबंधन बलों ने अथक रूप से स्थिति से निपटने के प्रयास किए। इस टकराव से कुछ हासिल नहीं हुआ। इससे न घायल लोगों को राहत मिली और न भविष्य में ऐसी घटनाओं को



रोकने के लिए किसी कार्ययोजना पर विचार हुआ। लेकिन इस प्रकार की बयानबाजी से केन्द्र और राज्य सरकारों ने स्वयं को 'क्लीन चिट' देने का प्रयास जरूर किया।

यह त्रासदी आपदा प्रबंधन की चुनौतियों को उजागर करते हुए राज्य और केन्द्र सरकारों के बीच समन्वित प्रयासों की आवश्यकता रेखांकित करती है। वायनाड त्रासदी ने पर्यावरण संरक्षण तथा प्रकृति की अनदेखी पर व्यापक विमर्श की आवश्यकता भी उजागर की है। केरल सरकार इस बात की दोषी है कि उसने 'पश्चिमी घाटों' पर बेलगाम विकास की अनुमति दी है, जबकि यह देश का एक सर्वाधिक संवेदनशील परिस्थितिकी तंत्र है। बार-बार आने वाली विभीषिकाओं के बावजूद केरल सरकार 'विकास' के नाम पर गैर-टिकाऊ गतिविधियां जारी रखे हैं। इसके कारण भूमि प्रयोग बदलने से घना वृक्षाच्छादन नष्ट हुआ है। इसने सदाबहार जलधाराओं व नदियों को मौसमी बना दिया है तथा मानसून के मौसम में बाढ़ आने का खतरा बढ़ा है। वायनाड भूस्खलन पर्यावरणीय संकेतों की अनदेखी करने के खतरनाक परिणामों की चेतावनी है। निर्वनीकरण व अनियोजित निर्माण ने वायनाड जैसे क्षेत्रों में प्राकृतिक विभीषिकाओं का खतरा पैदा कर दिया है। वायनाड भूस्खलन आपदा प्रबंधन में जवाबदेही तथा सक्रिय कदमों का महत्व भी उजागर करता है। ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से यह हमारे पर्यावरण के सम्मान और देखभाल की आवश्यकता उजागर करता है। जंगल मिट्टी को स्थिर रखने तथा जल-चक्र को नियमित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका आपदा प्रबंधन में। निर्वनीकरण से परिस्थितिकी तंत्र बाधित होते हैं जिनसे भूस्खलन जैसी घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। वायनाड त्रासदी सरकारों, समुदायों और आम जनता का आह्वान करती है कि वे हम सबका अस्तित्व बनाए रखने के लिए पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता प्रदान करें।

कौशल व रोजगार को प्राथमिकता

युवा सशक्तीकरण के लिए सरकार ने तीन परिवर्तनकारी योजनाओं की घोषणा की है। इनका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में कौशल का विकास करना है।



दिनेश सूद
(लेखक, कौशल संवर्धन क्षेत्र से संबद्ध हैं)

केंद्रीय बजट की नौ सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रोजगार एवं कौशल विकास को बढ़ावा देना है। इस दृष्टिकोण से कौशल विकास के लिए तीन योजनाओं की घोषणा की गई है। पहली योजना में उच्च कौशल संवर्धन पाठ्यक्रमों के लिए अधिकतम कर्ज प्रदान करना है। इसके लिए संशोधित 'आदर्श कौशल कर्ज योजना' लाई गई है जिसमें प्रति वर्ष 1.5 प्रतिशत के ब्याज पर 1.5 लाख से लेकर 7.5 लाख रुपये तक कर्ज का प्राविधान किया गया है। इस योजना से युवाओं के सशक्तीकरण की उम्मीद है। इससे उनको उत्कृष्ट स्तर के कौशल पाठ्यक्रमों तक पहुंच बढ़ाई जाएगी। इससे योग्य छात्रों के सामने आने वाली वित्तीय बाधाओं काफ़ी सीमा तक हटाने तथा उम्मीदवारों को भविष्योन्मुखी और उद्योगों में वांछित कौशल प्रदान करने में सहायता मिलेगी। इससे भविष्य के लिए तैयार और सशक्त कार्यबल तैयार होगा।

कौशल संवर्धन कर्ज बाजार में गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों-एनबीएफसी व माइक्रो-फाइनेंस संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए कौशल विकास एवं रोजगार मंत्रालय-एमएसडीई ने योजना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। इस योजना में एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस संस्थानों तथा छोटे फाइनेंस बैंकों को शामिल कर गारंटी की आधार पर कर्जों की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत कर्ज का 75 प्रतिशत हर साल 25,000 उम्मीदवारों को 7.5 लाख तक का कर्ज बिना किसी गारंटी के दिया जाएगा। इसका अर्थ है कि सरकार अपनी ओर से ऐसे कर्जों की गारंटी लेगी। सरकार ने यह तथ्य स्वीकार किया है कि बिना जीवन कौशल कर्ज योजना से सरकार के अनेक नौजवान तथा इच्छुक उम्मीदवारों को आवश्यक वित्तीय समर्थन नहीं मिल पाता है जिसके कारण वे अपना कौशल संवर्धन तथा कौशल प्रशिक्षण नहीं प्राप्त कर पाते हैं।



सहज प्रवाह सुनिश्चित करने तथा कम आय वाले नौजवानों को विशेष कौशल पाठ्यक्रमों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एमएसडीई ने पहले जुलाई, 2015 में क्रेडिट गारंटी फंड योजना शुरू की थी, लेकिन यह योजना अपनी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी।

पिछले दशक में इस योजना के अंतर्गत पैसे का कम प्रयोग कर्ज का 1.5 लाख रुपये तक सीमित आकार था, हालांकि मुद्रास्फीति के कारण पाठ्यक्रमों का खर्च और फीस बढ़ी थी। इसके कारण बहुत से अधिक खर्च वाले पाठ्यक्रमों को योजना से बाहर रखा पड़ा था। इसके साथ ही सरकार-प्रायोजित योजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए निजी बैंकों में इच्छाशक्ति जगाना जरूरी था। 31 मार्च, 2024 तक पिछले दशक में इस योजना के अंतर्गत 10,077 कर्ज लेने वालों को केवल 115.75 करोड़ रुपये कर्ज ही दिया जा सका था। लेकिन नई माडल कौशल कर्ज योजना से सरकार की इस मुद्दे के प्रति अडिग प्रतिबद्धता प्रकट होती है जिसका उद्देश्य तेज गति से होने वाले तकनीकी परिवर्तनों को देखते हुए उच्च कौशल वाला कार्यबल तैयार करना है।

वर्तमान समय में मांग किए जाने वाले प्रासांगिक कौशल को प्राप्त करने का खर्च काफी अधिक है। तथाकथित कुशल कार्यबल का केवल 5 प्रतिशत ही औपचारिक रूप से प्रशिक्षित है। इससे

कौशल की कमी व्यापक रूप से सामने आती है जिसे तत्काल दूर किया जाना चाहिए। हालांकि, हर साल स्कूलों में 26.5 करोड़ बच्चे प्रवेश लेते हैं, पर उच्च शिक्षा तक पहुंचने पर उनकी संख्या घट कर केवल 4.3 करोड़ रह जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-एनईपी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा पास करने वाले अतिरिक्त पांच करोड़ बच्चों को उच्च शिक्षा के दायरे में लाया जाना चाहिए। इसके लिए न केवल प्रत्येक व्यक्ति की कौशल शिक्षा का तक पहुंच होनी चाहिए, बल्कि ग्रामीण भारत के छात्रों की बड़ी संख्या को इसके दायरे में लाना होगा।

इस कमी को दूर करने के लिए आदर्श कौशल कर्ज योजना न केवल एक समाधान है, बल्कि यह आवश्यकता और तात्कालिक कदम है। कौशल अर्थव्यवस्था लगातार बाजार-संचालित होती जा रही है जिनमें नए युग के शिक्षण को कौशल विकास परिस्थितिकी से जोड़ा जाता है। शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के नौजवान कौशल संवर्धन एवं आजीविका में सुधार के अवसरों की पहचान करते हैं। ऐसे में आदर्श कौशल कर्ज योजना जैसी पहल अपने दरवाजे अनेक कौशल पाठ्यक्रमों के लिए खोलती है जिसमें स्वास्थ्यरक्षा, सौंदर्य-बेहतर, आईटी, एआई-डेटा साइंस, क्लाउड प्रयोग, डिजिटल मार्केटिंग, अतिथि सत्कार क्षेत्र, एनीमेशन, गेमिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग तथा ड्रोन टेक्नोलॉजी शामिल हैं। उद्योगों

की बदलती गतिशीलता से संचालित ये पाठ्यक्रम बड़ी संख्या में नौकरियों के अवसर प्रदान करते हैं तथा वैश्विक स्तर पर नौकरियों की संभावनाएं खोलते हैं। इससे नौजवानों को भविष्य के दरवाजे खोलने तथा अंतरराष्ट्रीय कैरियर विकल्प खोजने में सहायता मिलती है।

दूसरी योजना का लक्ष्य अगले पांच साल में 20 लाख नौजवानों का कौशल संवर्धन करना है। कुल 60,000 करोड़ रुपये के आबंटन वाली इस योजना का लक्ष्य इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों-आईटीआई का 'हब एंड स्पोक' व्यवस्था के अंतर्गत उच्चिकरण करना है जिससे उन्मुखीकरण में सुधार होगा। यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका लक्ष्य नौजवानों को विशिष्ट-उद्योग कौशल से समृद्ध कर उन्को ज्यदा रोजगारों के उपयुक्त बनाना है। इसके लिए पाठ्यक्रम की विषयवस्तु व डिजाइन को उद्योगों की कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप उच्चिकृत करना होगा। उदाहरण के लिए, उभरते आईटी क्षेत्र को साइबर सुरक्षा या डेटा विश्लेषण कौशल की आवश्यकता है जिनको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। बजट में शामिल तीसरी योजना का उद्देश्य युवाओं को समग्र रूप से कौशल प्रदान करना है ताकि नौजवानों को सर्वोच्च 500 कंपनियों में इंटरशिप के अवसर मिल सकें। इस प्रकार की पहली योजना में अगले पांच साल में एक करोड़

नौजवानों को शामिल किया जाएगा। यह नौजवानों में बेरोजगारी समस्या का समाधान करने में गेमचेंजर हो सकती है। इस इंटरशिप योजना का खोजी दृष्टिकोण और संभावित प्रभाव इसे युवा जनसंख्या को भावी रोजगार दिलाने में प्रकाश की किरण जैसा है। इससे युवा बेरोजगारी दरों में काफी कमी आने की उम्मीद है। लेकिन इंटरशिप करना कठिन है क्योंकि इससे निराशा और हताशा का दुष्क्र पैंदा हो सकता है। एमबीए, इंजीनियरिंग, आदि पेशेवर डिग्री वाले छात्रों को स्नातक के बाद अच्छी नौकरियां व इंटरशिप प्राप्त करने में आसानी होगी। लेकिन यह परिदृश्य उन स्नातकों के लिए ज्यदा कठिन होगा और उनको नौकरियों के अयोग्य बनाएगा जो मानविकी विषयों से स्नातक होंगे और उनके पास बाजार के उपयुक्त तत्काल कोई कौशल उपलब्ध नहीं होगा।

प्रमुख कंपनियों में विभिन्न विषयों में शिक्षित युवा स्नातकों को इंटरशिप प्रदान करने वाली यह योजना एक 'गेम चेंजर' के साबित हो सकती है। लेकिन इसके लिए योजना का समुचित व प्रभावी क्रियाव्यवन बहुत जरूरी होगा। इसके लिए बड़ी कंपनियों को मजबूत इच्छाशक्ति दिखानी होगी और सरकार को इसके लिए उनको प्रेरित करना होगा। शाब्द भविष्य में सरकार इस योजना का दायरा बढ़ाने और कंपनियों के लिए इंटरशिप देना अनिवार्य रूप से कर विचार कर सकती है। कम से कम यह एक आकार से बड़ी कंपनियों के लिए अनिवार्य किया जा सकता है। सरकार इस उद्देश्य से कुछ विशिष्ट मानक भी निर्धारित कर सकती है।

कंपनियां अपने कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड-सीएसआर के अंतर्गत हर साल निश्चित संख्या में इंटरने लेने की व्यवस्था कर सकती हैं। इस फंड से वे इंटरशिप के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की फंडिंग कर सकती हैं। ये फंड कंपनियों की पहल पर पर्यावरणीय व सामाजिक बेहतर के लिए खर्च किए जाते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली इंटरशिप से नौजवानों में नौकरियां प्राप्त करने की क्षमता बढ़ेगी। इस दौरान प्राप्त अपने सटीक अनुभव के आधार पर वे रोजगार प्राप्त करने में सफल होंगे। लेकिन रोजगार व नौकरी योग्य कौशल प्रदान करने में योजना का क्रियाव्यवन, प्रभावशीलता व जवाबदेही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी।

भारत का संतुलनकारी राजनय

“
भारत सरकार पिछले महीने राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी की बैठक के बारे में अमेरिका और यूरोपीय चिंताओं को दूर करने की कोशिश कर रही है।”



कुमारीदीप बनर्जी
(लेखक नीति विश्लेषक हैं)

एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश में, भारत सरकार पिछले महीने राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी की बैठक के बारे में अमेरिका और यूरोपीय चिंताओं को दूर करने की कोशिश कर रही है, जब कई नेता नाटो शिखर सम्मेलन के लिए वाशिंगटन में एकत्रित थे। राष्ट्रपति पुतिन ने मास्को में पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए एक अतिरिक्त कदम उठाया, जो भारत के साथ दीर्घकालिक साझेदारी के बारे में अमेरिका को एक मजबूत संदेश देता है।

अमेरिका में वरिष्ठ अधिकारियों ने पीएम मोदी की मास्को यात्रा में शामिल दिखावे पर गहरी चिंता व्यक्त की, जबकि

उन्होंने दोहराया कि कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल नहीं हुआ। रूस के साथ द्विपक्षीय संबंध एक कठिन रस्सी हैं, जिस पर भारत पिछले दशकों में अमेरिका के साथ अपने बढ़ते जुड़ाव के बावजूद सावधानी से चलने में कामयाब रहा है। इसलिए, इस सप्ताह टोक्यो में क्राइड विदेश मंत्रियों का सम्मेलन, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्ष एंथनी ब्लिंकन से मुलाकात की, महत्वपूर्ण था। संयुक्त बयान में स्पष्ट शब्दों में यूक्रेन में रूस की कार्रवाई की निंदा की गई, शायद पहली बार इस तरह के बहुपक्षीय आधिकारिक संचार में शामिल हुआ।

संयुक्त बयान में कहा गया, हम यूक्रेन में चल रहे युद्ध और उसके भयानक और दुःखद मानवीय परिणामों पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। हम अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप व्यापक, न्यायसंगत और स्थायी शांति की आवश्यकता को दोहराते हैं, जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान सहित संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और



सिद्धांतों के अनुरूप हो। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठकों और बाद में सार्वजनिक संदेशों में भी युद्ध के मैदान से दूर यूक्रेन संकट की स्थायी समाधान खोजने की आवश्यकता न्यायसंगत और स्थायी शांति की आवश्यकता को दोहराते हैं, जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान सहित संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और

सिद्धांतों के अनुरूप हो। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठकों और बाद में सार्वजनिक संदेशों में भी युद्ध के मैदान से दूर यूक्रेन संकट की स्थायी समाधान खोजने की आवश्यकता न्यायसंगत और स्थायी शांति की आवश्यकता को दोहराते हैं, जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान सहित संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और

पीएम भू-राजनीतिक गतिशीलता को संतुलित करने और भारत और यूरोप के संबंधों को फिर से स्थापित करने के लिए अगस्त में यूक्रेन की यात्रा कर सकते हैं। इस बीच, क्राइड विदेश मंत्रियों की बैठक में गाजा संकट और लाल सागर क्षेत्र में इसके फैलाव पर ध्यान केंद्रित करना जारी रहा, जिससे लोगों के जीवन पर असर पड़ रहा है और माल ढुलाई की लागत बढ़ रही है।

विदेश मंत्रियों ने संयुक्त रूप से संवाद किया, हम सभी पक्षों से अंतरराष्ट्रीय कानून, जिसमें अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून भी शामिल है, का पालन करने का आग्रह करते हैं। हम यूएनएससी संकल्प का स्वागत करते हैं और सभी संबंधित पक्षों से सभी बंधकों को रिहाई और तत्काल युद्धविराम की दिशा में तुरंत और लगातार काम करने का आग्रह करते हैं।

हम सभी पक्षों से सहायता कर्मियों सहित नागरिकों के जीवन की रक्षा करने और मानवीय राहत के नेजी से परिवहन की सुविधा के लिए हर संभव कदम

उठाने का आह्वान करते हैं। हम इंडो-पैसिफिक सहित अन्य देशों को भी प्रोत्साहित करते हैं कि वे जमीन पर गंभीर मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाएं। हम इस बात पर जोर देते हैं कि गाजा पट्टी के भविष्य की बहाली और पुनर्निर्माण को अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा समर्थन दिया जाना चाहिए। हम दो-राज्य समाधान के हिस्से के रूप में इजरायल की वैध सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एक संतुल्य व्यवहार्य और स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमें इजरायल और फिलिस्तीनियों दोनों को न्यायपूर्ण, स्थायी और सुरक्षित शांति में रहने में सक्षम बनाना है।

भारत इस साल होने वाले क्राइड नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, हालांकि, नवंबर में होने वाले महत्वपूर्ण अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव इस समय के प्रमुख निर्धारक होंगे। राष्ट्रपति बिडेन जिन्होंने अतीत में ज्यदातर क्राइड कथा को आकार दिया है, वे चार के इस समूह पर एक स्थायी छाप छोड़ना चाहेंगे।

आप की बात

कोटे के भीतर कोटा

सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी आरक्षण में उपश्रेणियां बनाने, यानी कोटे के भीतर कोटा बनाने की अनुमति रण्यों को दे दी ताकि इन वर्गों में अधिक पिछड़ी जातियों को लाभ मिले। यह फैसला आरक्षण व्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव डालेगा। सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ में 6:1 के बहुमत से दिए गए फैसले से जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी ने असहमति व्यक्त करते हुए रण्यों को यह अधिकार देना गुलत माना। एससी-एसटी में भी ओबीसी की तरह क्रीमी लेयर लागू करने और आरक्षण को एक पीढ़ी तक सीमित करने जैसे अलग-अलग सुझाव दर्ज भी बहुमत से फैसला देने वाले न्यायाधीशों द्वारा दर्ज कराए

गए। क्रीमी लेयर व आरक्षण एक पीढ़ी तक सीमित करने जैसे सुझावों को तत्काल लागू किया जाना चाहिए। आरक्षण का यही सबसे बड़ा पहलू है कि आजादी के बाद से ही आरक्षण का फायदा उठाने वाले अब भी आरक्षण को यथावत जारी रखना चाहते हैं। इसी वजह से आरक्षण का 75 प्रतिशत से अधिक फायदा आरक्षित वर्गों के ही गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है। हालांकि, वोटबैंक राजनीति के चलते अब भी अधिक संख्या वाली दलित जातियों को पहले की तरह अधिक लाभ मिलने तथा कम संख्या वाली दलित जातियों को वंचित रहने की आशंका बनी हुई है।

सुभाष बुडवान वाला, रतलाम

कमला हैरिस को बढ़त

एक जनमत सर्वेक्षण के अनुसार, डेमोक्रेटिक अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस ने सात स्विंग राज्यों में से छह में रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बढ़त हासिल की है। कमला हैरिस का नाम सामने आने के बाद से ट्रंप एक तरह से बचाव की मुद्रा में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि हैरिस पहले स्वयं को भारतीय मूल की महिला के रूप में पेश करती थीं, पर अब वे अश्वेत के रूप में सामने आ रही हैं। कमला हैरिस ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ट्रंप को जो कुछ कहना हो, हमारे सामने कहें और राष्ट्रीय बहस में हिस्सा लें। मजेदार बात है कि जो ट्रंप पहले बाइडेन को बहस के लिए चुनती देते थे, अब इससे कन्नी काट रहे हैं। उनको अहसास हो गया है कि भावी प्रथम अमेरिकी अश्वेत महिला के रूप में कमला हैरिस का पलड़ा उनसे लगातार भारी होता जा रहा है। रिपब्लिकन पार्टी की गर्भपात-विरोधी और आप्रवासी-विरोधी नीतियों के कारण अमेरिकी जनता का वही वर्ग और ज्यदा मजबूती के साथ कमला हैरिस के साथ आ रहा है जिसने जो बाइडेन को विजय दिलाई थी।

- जग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

आरक्षण की सीमा

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पंकज मिथल का विचार है कि आरक्षण केवल पहली पीढ़ी तक ही मिलाया जाए। अगर कोई पहली पीढ़ी आरक्षण लेकर उच्च स्तर पर पहुंच गई है तो उसको इसका हकदार नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह बात एससी-एसटी आरक्षण के कोटे में कोटा पर सुप्रीम कोर्ट में जजों के पेनल में हिस्सा लेने के दौरान कही। उनकी बात सही और तार्किक भी है। जिन्हें वोटबैंक आरक्षण का लाभ मिल चुका है और वे व उनका परिवार उसे पाकर सक्षम हो चुका है और यह लाभ अब उनकी ही जाति के दूसरे वंचित लोगों को मिला चाहिए। ऐसा न होने पर सक्षम लोग ही अपने लोगों को नुकसान

पहुंचाते हैं। आरक्षण नीति में कुछ ऐसे परिवर्तन होने चाहिए जिसमें अधिक से अधिक लोगों को आरक्षण का लाभ देकर सक्षम बनाया जा सके। संविधान निर्माता डा. भीमराव आंबेडकर ने भी आरक्षण के जरिये अधिक से अधिक लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने की बात कही थी। उन्होंने कुछ मामलों में आरक्षण 10 वर्षों तक रखने का सुझाव दिया था। लेकिन अब आरक्षण में इसकी सीमा और बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। यह स्थिति समाज कल्याण के बजाय निहित स्वार्थों को बढ़ावा देगी।

-शकुन्ता महेश नेनावा, इंदौर

योगी का कठोर कदम

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुछ अराजक युवाओं द्वारा स्कूटर सवार व्यक्ति व महिला पर गंदा पानी फेंकने और महिला के साथ छेड़खानी करने की घटना सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कठोर कदम उठाया है। उन्होंने क्षेत्र के डीसीपी, एडिशनल डीसीपी और एसपी का ट्रांसफर करने के साथ थाना इंचार्ज और पुलिस चौकी के सभी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। कैमरों में दिखने वाले सभी अराजक व बेलगाम युवाओं को गिरफ्तार किया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री और यूपी पुलिस प्रशासन

की सहायता की जानी चाहिए। यूपी पुलिस की कार्रवाई अपनी जिम्मेदारी न निभाने वाले पुलिस कर्मियों तथा अराजक शहरी युवाओं के लिए सबक है। योगी आदित्यनाथ का यह कठोर कदम उन विपक्षी राजनेताओं के लिए भी सबक है जो युवाओं को बहका कर प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब कर मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार की छवि खराब करना चाहते हैं। विपक्षी दलों को ऐसी घटना हरकतों से बचना चाहिए, नहीं तो 2027 में उनका फिर पूरी तरह सफाया हो जाएगा।

-वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली
पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

गांवों के ओपन जिम साकार करेंगे 'कैच देम यंग' का सपना

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

खेलों में भी उत्तर प्रदेश सिरमौर बने। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की मंशा है। इसके लिए सबसे प्रभावी फॉर्मूला है, 'कैच देम यंग'। मसलन बचपन से होनहार प्रतिभाओं को पहचानकर उनको उसी तरह की बुनियादी सुविधाएं, प्रशिक्षण और एक्सपोजर दिलाया। इसमें गांव गांव में खुलने वाले ओपन जिम की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसीलिए अनुपूरक बजट में भी सरकार में ग्रामीण क्षेत्रों में ओपन जिम खोलने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ओपन जिम में ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाएं निखरेंगीं वहीं सरकार द्वारा संचालित खिलाड़ों इंडिया सेंटर और सभी सुविधाओं से आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज में इंटरनेशनल स्तर के कोच के प्रशिक्षण से इनको और निखारा जाएगा। सरकार एक जिला एक खेल (वन डिस्ट्रिक्ट्स,वन स्पोर्ट्स) पर भी गंभीरता से काम कर रही है।

अनुपूरक बजट में भी जिम के लिए किया गया 100 करोड़ का प्रावधान



उल्लेखनीय है कि हर जिले में कुछ खास खेल अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित होते हैं। संबंधित जिले में उन खेलों को खास प्रोत्साहन देने और उसी अनुसार बेहतरीन बुनियादी

सुविधाएं और प्रशिक्षण देने की भी योजना है। मेरठ में युद्ध स्तर पर बन रही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी योगी सरकार की खेल प्रतिभाओं को निखारने में मील का पत्थर बनेगी। सच तो यह

है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खेलों के प्रति निजी रुचि के कारण पिछले सात वर्षों में खेल जगत का पूरा परिदृश्य ही बदल गया है। आज प्रदेश में कानपुर, लखनऊ,

वाराणसी, गाजियाबाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम हैं। कानपुर और लखनऊ में तो लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच भी होते हैं। बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड) द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश का एकमात्र स्टेडियम होगा। कुछ दिनों पहले गोरखपुर में भी इंटरनेशनल स्तर के क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की घोषणा मुख्यमंत्री कर चुके हैं।

युवा खिलाड़ी नामचीन खिलाड़ियों से प्रेरणा ले सकें इसलिए उनका भी सम्मान किया जा रहा है। हाकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यान चंद के नाम से बन रही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के बाद मुख्यमंत्री ने अनुपूरक बजट में बाराबंकी स्थित पद्म श्री बाबू केडी सिंह के बाराबंकी स्थित पैतृक निवास को संग्रहालय घोषित करना भी एक ऐसा ही प्रयास है। इस बाबत सरकार ने अनुपूरक

बजट में 19.34 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। गोरखपुर के रामगढ़ झील में नौकायन प्रतियोगिता के लिए पूरी सुविधा मौजूद है। राष्ट्रीय स्तर की एक सफल प्रतियोगिता वहां हो भी चुकी है। खेला इंडिया के तहत उत्तर प्रदेश इंटर यूनिवर्सिटी गेम, नोएडा में मोटो जीपी के तहत पहली बार इंटरनेशनल बाइक रेस का आयोजन इस बात का सबूत है कि उत्तर प्रदेश में खेल संबंधी सुविधाओं के विस्तार के साथ यहां का पूरा परिदृश्य बदल चुका है। बदलाव की यह प्रक्रिया लगातार जारी है। इसके नतीजे भी दूरगामी और बहुआयामी होंगे।

मसलन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों से हास्पिटलिटि और इससे संबंधित सेक्टर्स को लाभ होगा। खेल सामग्री की मांग बढ़ने से संबंधित इंडस्ट्री को भी लाभ होगा। स्थानीय स्तर पर रोजी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। युवाओं में जीत का जन्म और अनुशासन का बढ़ना बोनस होगा।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन



पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पवित्र श्रावण मास की शिवरात्रि के पावन अवसर पर शुक्रवार को काशी स्थित बाबा विश्वनाथ धाम में देवाधिदेव महादेव भगवान शिव जी के ज्योतिर्लिंग का दर्शन-पूजन व जलाभिषेक किया व बाबा विश्वनाथ से समस्त देश व प्रदेशवासियों के सर्वकल्याण की प्रार्थना की। उन्होंने वाराणसी में काशी के कोतवाल बाबा कोल भैरव के दर्शन व पूजन भी किया। उप मुख्यमंत्री मौर्य ने उसके बाद वाराणसी स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बिहारी लाल शर्मा से शिष्टाचार भेंट की और शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

एससी, एसटी व ओबीसी के प्रति कांग्रेस-बीजेपी का रवैया नही रहा सुधारवादी: मायावती

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

आरक्षण पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रतिक्रिया देते हुए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में सब कैटेगरी बनाने के फैसले का विरोध किया है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल पूछा है कि सरकार ने इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले आरक्षण पर गुरवार को दिए फैसले में कहा था कि एससी-एसटी की सूची में सब कैटेगरी बनाने को लेकर कोई संवैधानिक रोक नहीं है। शुक्रवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि



सामाजिक उर्पीड़न की तुलना में राजनीतिक उर्पीड़न कुछ भी नहीं। क्या देश के खासकर करोड़ों दलितों और आदिवासियों का जीवन द्वेष व भेदभाव-मुक्त आत्म-सम्मान व स्वाभिमान का हो पाया है। अगर नहीं तो फिर जाति के आधार पर तोड़े व पछाड़े गए इन वर्गों के बीच आरक्षण का बंटवारा कितना उचित? आगे उन्होंने लिखा कि देश के एससी, एसटी और ओबीसी बहुजनों के प्रति कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों और सरकारों का रवैया उदारवादी रहा है सुधारवादी नहीं। वे इनके सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति के पक्षधर नहीं बना इन लोगों के आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालकर इसकी सुरक्षा जरूर की गई होती।

बाढ़ से 1,57, 444 किसानों की फसलें हुई प्रभावित, पोर्टल पर डाटा किया गया फीड

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

अन्नदाता किसानों की आय में वृद्धि के साथ ही किसी आपदा में उन्हे होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भी योगी सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश में बाढ़ की वजह से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए योगी सरकार ने अब तक 150 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी की गई है। यह धनराशि क्षतिग्रस्त फसलों को मुआवजा देने के लिए जिलों की डिमांड पर जारी की गई है। वहीं अब तक सवा लाख से अधिक किसानों को उनकी क्षतिग्रस्त फसलों के लिए 71 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा दिया जा चुका है। इसमें सबसे अधिक लखौमपुर खीरी के 70 हजार से अधिक किसानों को 47 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।

राहत आयुक्त जीएस नवीन ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी

योगी सरकार बाढ़ प्रभावित इलाकों को जारी कर चुकी है अब तक 150 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि

आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के बाढ़ग्रस्त इलाकों में लगातार क्षतिग्रस्त फसलों का सर्वे किया जा रहा है, ताकि किसानों को समय से मुआवजा दिया जा सके। उन्होंने बताया कि नेपाल और पहाड़ी क्षेत्रों से छोड़े गये पानी से प्रदेश के 18 जिलों की 82126.50 हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई। वहीं सर्वे के दौरान वास्तविक क्षतिग्रस्त फसल 29,243.74 हेक्टेयर पायी गयी। बता दें कि सरकार की ओर से बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और बाढ़ से क्षतिग्रस्त 33 प्रतिशत से अधिक फसल के नुकसान पर ही मुआवजा दिया जाता है। राहत आयुक्त ने बताया कि बाढ़ से

1,57,444 किसानों की फसल प्रभावित हुई जबकि लेखपाल द्वारा अब तक 1,56,952 किसानों को सहायता धनराशि देने के लिए पोर्टल पर फीड किया जा चुका है। इसके सापेक्ष अब तक 1,25,521 किसानों को 71.01 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। वहीं बचे हुए किसानों की फीडिंग का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। सबसे अधिक लखौमपुर के 88546 किसानों की फसल बाढ़ से प्रभावित हुई है। इसके सापेक्ष भुगतान के लिए अब तक 88544 किसानों की फीडिंग पोर्टल पर की जा चुकी है।

वहीं 70,691 किसानों को 47 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इसी तरह सिद्धार्थनगर 19805 किसानों की फसल बाढ़ से प्रभावित हुई है। सभी किसानों की फीडिंग पोर्टल पर की जा चुकी है जबकि 15478 किसानों को 7.70 करोड़ का भुगतान किया जा चुकी है।

गरीबों को बेघर करने का षडयंत्र रच रही सरकार

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार गरीबों की जमीनों को छीनकर उन्हें बेघर करने का षडयंत्र रच रही है। भाजपा सरकार गरीब विरोधी है। समाजवादी पार्टी और समस्त विपक्ष के विरोध के बाद भी सत्ता के अहंकार में चूर भाजपा सरकार नजूल जमीन विधेयक बीजेपी के कुछ लोगों के फायदे के लिए लायी है। ये लोग अपने आसपास की गरीब जनता की जमीनें हड़पना चाहते हैं। सात साल से सरकार में रहकर बजट की लूट करने के बाद भी सत्रा में बैठे लोगों का पेट नहीं भरा है। अब ये नया कानून बनाकर जमीनों लूटना चाहते हैं।



मानती है। जबसे भाजपा आई है, तब से जनता रोजी-रोटी-रोजगार के लिए भटक रही है, और अब भाजपाई मकान भी छीनना चाहते हैं। कुछ लोगों के पास दो जगह का विकल्प है, पर हर एक उनके जैसा नहीं है। बसे बसाये घर उखाड़कर भाजपा वालों को क्या मिलेगा। क्या भू-माफियाओं के लिए भाजपा जनता को बेघर कर देगी? अखिलेश यादव ने कहा कि अगर भाजपा की लगता है कि उनका ये फँसला सही तो हम उन्हें को चोट पर कहते हैं, अगर हिम्मत है तो इसे पूरे देश में लागू करके दिखाएँ क्योंकि नजूल लैंड केवल यूपी में ही नहीं पूरे देश में है। समाजवादी पार्टी की यही मांग है कि अमानवीय 'नजूल ज़मीन

बिल' हमेशा के लिए वापस हो। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ये बिल अपने निजी फायदे के लिए लाकर गरीबों की जमीनों हड़पना चाहते हैं। इस बिल का जनहित और विकास से कोई वास्ता नहीं है। गोरखपुर में नजूल के अर्न्तगत आने वाली बेशकौमती जमीनों पर सीएम की नज़र है। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी जी ने सोचा कि सत्ता के फायदा उठाकर उन जमीनों पर कब्जाकर लिया जाए इसलिए ये बिल लाया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की पहले गोरखपुर, अयोध्या फिर लखनऊ और धीरे-धीरे पूरे यूपी की बेशकौमती नजूल भूमि पर कुलुप्ति है और गरीब जनता पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। ये जमीनों जनता से छीन कर बिल्डर्स, उद्योगपतियों को देने की साजिश है चूँकि लोकतन्त्र तमाम भाजपाई दिग्गजों की कोठियां, मकान, प्रतिष्ठान, बंगले भी नजूल में आ रहे हैं इसीलिए भाजपा के अंदर भी उसका विरोध हो रहा है।

बीआरडी मेडिकल कॉलेज को आज 55 करोड़ रुपए की सौगात देंगे सीएम योगी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/ गोरखपुर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज को 55 करोड़ रुपयों से अधिक के विकास कार्यों और सुविधाओं की सौगात देंगे। मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में दोपहर बाद 3.30 बजे से प्रस्तावित कार्यक्रम में सीएम योगी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के साथ ही जनहित में विभिन्न नई सुविधाओं का शुभारंभ करेंगे। लोकार्पण, शिलान्यास और सुविधाओं के शुभारंभ समारोह के मंच से मुख्यमंत्री स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण के तहत एमबीबीएस और पैरामेडिकल छात्रों को 483 टैबलेट-स्मार्टफोन का वितरण भी करेंगे।

बाबा राघव दास (बीआरडी) मेडिकल कॉलेज के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों जिन प्रमुख सुविधाओं का शुभारंभ होगा उनमें 7 करोड़ 17 लाख रुपये की लागत से सीटी स्कैन मशीन और 11.25 लाख रुपये की लागत वाली लिथोट्रिप्सी मशीन का लोकार्पण प्रमुख है। इसके अलावा सीएम जेनेटिक मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स आर्थोपेडिक्स ओपीडी तथा मिस्क बैंक का भी शुभारंभ करेंगे। मेडिकल कॉलेज में मुख्यमंत्री द्वारा माइक्रोबायोलॉजी विभाग में सैमल कलेक्शन सेन्टर की स्थापना, पैथालॉजी विभाग में फुली आटोमेटिक टिशु प्रोसेसर, फुली आटोमेटिक यूरिन एनालाइजर, 5 पार्ट सिमेक्स सीबीसी एनलाइजर तथा न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी का हारमोन ट्यूमर मेकर

डिडक्शन की एलाइनिटी मशीन की स्थापना का शुभारंभ और आर्टिफिसी पैमल के रेंज की वृद्धि कार्य का शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही वह फार्मसी कालेज के विस्तार निर्माण कार्य का लोकार्पण करेंगे। इस पर 8 करोड़ 5 लाख रुपये की लागत आई है। सीएम योगी मेडिकल कॉलेज में 6 करोड़ 12 लाख रुपये की लागत से स्थापित बर्न यूनिट, 2 करोड़ 68 लाख रुपये की लागत से स्थापित नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट लैब और 98 लाख रुपये से बनी स्टेडियम की चहारदीवारी का लोकार्पण करने के अलावा सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल में कार्यरत उपचारिकाओं के लिए 100 सीटेड मैरिड छात्रावास के निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। इस छात्रावास के निर्माण पर 30 करोड़ 31 लाख रुपये की लागत आएगी।

रालोद के जिलाध्यक्ष 31 अक्टूबर तक घोषित होंगे

लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष रामाश्री राय की अध्यक्षता में प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय अध्यक्षों की एक बैठक आयोजित की गयी। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव संगठन त्रिलोक त्यागी मौजूद रहे। बैठक में किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलजीत सिंह बिट्टू उपस्थित रहे। बैठक को सम्बोधित करते हुये राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने संगठन विस्तार पर चर्चा करते हुए सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्षों व क्षेत्रीय अध्यक्षों को निर्देशित किया कि सभी प्रकोष्ठों 31 अगस्त तक क्षेत्रीय अकांटी एवं 31 अक्टूबर तक जिलाध्यक्ष घोषित कर दिये जाय, 15 सितंबर से समीक्षा को शुरुआत होगी। प्रदेश अध्यक्ष रामाश्री राय ने कहा कि संगठन किसी भी राजनैतिक दल की रीढ़ होती है एवं संगठन की मजबूती पर ही राजनैतिक दल की सफलता निर्भर करती है।

वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी से भी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मास्टर प्लान तैयार

सरकार 10 सेक्टरों के जरिए साधेगी देश की सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले राज्य का लक्ष्य

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

अनुपूरक बजट के बाद प्रदेश को इस साल ऐतिहासिक साढ़े सात लाख करोड़ के बजट की सौगात देने के बाद अब योगी सरकार का लक्ष्य अगले चार कुछ साल में सूबे को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्य के रूप में स्थापित करने का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए 'दस का दम' लगाने पर जोर देते हुए विस्तार से कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये हैं। एक दिन पहले ही सदन में प्रदेश के अनुपूरक बजट पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी के लिए 10 सेक्टर में कार्य किये जाने की चर्चा की थी। प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के बड़े लक्ष्य को साधने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन 10 सेक्टरों पर

विशेष जोर देने के निर्देश सभी अधिकारियों को पहले ही दे दिये हैं। बीते फरवरी माह में आयोजित हुए ग्रांड्स ब्रेकिंग सेमिनार (जीबीसी) के जरिए प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश धरातल पर उतरने से योगी बड़ गया है। प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए योगी सरकार ने पूरी ताकत झोंकते हुए 10 सेक्टरों को चिह्नित किया है। इसमें प्रदेश के आर्थिक विकास से जुड़े सभी महत्वपूर्ण विभागों के बीच समन्वय कायम करते हुए कार्य करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं। जिन 10 सेक्टर पर मुख्यमंत्री ने सबसे अधिक फोकस करने के निर्देश दिये हैं उनमें कानून व्यवस्था, कृषि उत्पादन, सामाजिक सुरक्षा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास,

हासिल करने वाली योगी सरकार ने अब आगामी तीन साल के लिए बड़े लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर दिया है। प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के विशाल लक्ष्य के लिए योगी सरकार के पास बड़ा आधार भी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश का सकल जन्म घरेलू उत्पाद में उल्लेखनीय बढ़ोतरी के रूप में देखा जा सकता है, जोकि बीते वित्तीय वर्ष 2023-24 में 25.48 लाख करोड़ रुपए रहा है। जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह 22.58 लाख करोड़ रुपए था। वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 8 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। राज्य सरकार के विगत सात वर्षों के नियोजित प्रयासों के परिणामस्वरूप इसमें और वृद्धि की संभावना है। इसके अलावा देश में सबसे उर्वर भूमि, प्रचुर जल संसाधन, युवा आबादी, देश का

इंज 10 सेक्टर पर है फोकस कानून व्यवस्था, कृषि उत्पादन, सामाजिक सुरक्षा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, नगरीय विकास, ग्राम्य विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन एवं संस्कृति और राजस्व संग्रह को लेकर अगले तीन साल तक मिशन मोड में कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। इन प्रत्येक सेक्टर की जिम्मेदारी एक-एक कैबिनेट मंत्री को दी गई है, जिन्हे अपर मुख्य सचिव स्तर के अनुभवी अधिकारी संधालेंगे। मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक सेक्टर के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार की जाए। साथ ही कार्ययोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं मॉनीटरिंग होगा। योगी सरकार अपना 7 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। बीते 7 वर्षों में प्रदेश के इन्फ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था, यातायात कनेक्टिविटी और रोजगार के मोर्चे पर उल्लेखनीय सफलता

सबसे बड़ा उपभोक्ता और श्रम बाजार होने के साथ ही उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 8 प्रतिशत का योगदान देता है। यही नहीं देश की कुल 12 प्रतिशत कृषि भूमि और खाद्यान उत्पादन में यूपी करीब 20 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शब्दों में भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने में एक अहम रोल निभाने जा रहा है।

यूपी में मनरेगा श्रमिकों के लिए सरकार का खुला खजाना

केंद्र से 3600 करोड़ से भी ज्यादा धनराशि की गई जारी सामग्री मट ने भी मिले 1,100 करोड़

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि मनरेगा श्रमिकों के पारिश्रमिक का भुगतान शीघ्र ही किया जायेगा, उनके प्रयासों से भारत सरकार द्वारा पर्याप्त धनराशि उत्तर प्रदेश के लिए जारी की गयी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के मजदूरों और निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता एजेंसियों के लिए एक राहत भरी खबर है। इन लोगों के बकाये का अब बहुत जल्द ही भुगतान होगा। सरकार ने उत्तर प्रदेश मनरेगा के लिए अपना खजाना खोल दिया है। श्रमांश, सामग्री और प्रशासनिक मद की बात करें, तो केंद्र सरकार से करीब 3,667 करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि जारी कर दी गई है। इसमें श्रमांश की बात करें, तो करीब 2,517 करोड़ रुपए जारी किये गये हैं, सामग्री मद में 1,100 करोड़ की धनराशि जारी कर दी गई है, इसके अलावा प्रशासनिक मद हेतु भी करीब 50.41 करोड़ की धनराशि केंद्र ने जारी की है। जारी धनराशि से बकायेदारी भी दूर होगी। अब बहुत जल्द ही श्रमिकों और निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता एजेंसियों तक यह धनराशि पहुंचेगी।

जारी धनराशि से जहां मजदूरों को उनका श्रमांश मिलेगा, वहीं

मनरेगा में निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता एजेंसियों को भी उनका बकाया भुगतान किया जा सकेगा। इस धनराशि के मिलने से मनरेगा कार्यों में भी तेजी आएगी। ऐसे में आपूर्तिकर्ता एजेंसियों के साथ-साथ मजदूर भी पूरी ऊर्जा के साथ मनरेगा कार्यों में अपना योगदान देंगे।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार श्रमिकों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लगातार काम कर रही है। श्रमिकों की मजदूरी उनके खाते में समय से पहुंचे, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। मनरेगा के लिए जारी धनराशि के लिए केंद्र सरकार का भी श्रमिकों की ओर से आभार भी जाता है। आपको बताते चलें कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 26 करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष अब तक प्रदेश द्वारा 13.50 करोड़ से ज्यादा मानव दिवस सृजित कर लिये गये हैं।

ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने बताया कि मनरेगा योजना के लिए मांग के अनुरूप केंद्र द्वारा श्रमांश, सामग्री एवं प्रशासनिक मद हेतु करीब 3,667 करोड़, मजदूरों के लिए करीब 2,517 करोड़, सामग्री मद में 1,100 करोड़, और प्रशासनिक मद हेतु भी करीब 50.41 करोड़ की धनराशि केंद्र ने जारी की है। जारी धनराशि से बकायेदारी भी दूर होगी। अब बहुत जल्द ही श्रमिकों और निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता एजेंसियों तक पहुंचेगी।

लगातार तीसरे दिन मेरठ व बागपत में शिवमठों पर हुई पुष्प वर्षा



पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/मेरठ/बागपत

योगी सरकार के निर्देश पर लगातार तीसरे दिन शुक्रवार को मेरठ और बागपत में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। गुरुवार को मेरठ में जहां डीएम और एसएसपी ने हेलीकॉप्टर से शिव भक्तों पर फूल बरसाए थे तो वहीं शुक्रवार को श्रावण शिवरात्रि के पावन अवसर पर मेरठ मंडल की मंडलायुक्त सेवला कुमारी जे और आईजी नचिकेता झा ने मेरठ में बाबा औचंडनाथ मंदिर और बागपत में पुरु महादेव मंदिर में कांवड़ियों से पुष्प वर्षा की गई थी। बुधवार को भी मेरठ में कांवड़ियों पर बुलडोजर से पुष्प वर्षा की गई थी। युवा वर्ग के साथ समूचे कांवड़ यात्रा मार्ग पर योगी सरकार के द्वारा की गई व्यवस्था पर कांवड़ियों ने खुशी जताई और सीएम योगी का धन्यवाद भी दिया।

और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होते देख कांवड़िये खुशी से झूम उठे और बोल बम बोल बम के नारे लगाने लगे। इससे पूर्व गुरुवार को मेरठ के डीएम दीपक मीणा और एसएसपी विपिन ताड़ा ने भी मेरठ के ऐतिहासिक औचंडनाथ मंदिर, दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग, पल्लवपुरम, पावन अवसर पर मेरठ मंडल के हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की थी। बुधवार को भी मेरठ में कांवड़ियों पर बुलडोजर से पुष्प वर्षा की गई थी। युवा वर्ग के साथ समूचे कांवड़ यात्रा मार्ग पर योगी सरकार के द्वारा की गई व्यवस्था पर कांवड़ियों ने खुशी जताई और सीएम योगी का धन्यवाद भी दिया।

प्रदेश के सभी प्रमुख मार्गों के किनारे 1001 ढाबों पर पर्यटकों को मिलेंगी मनपसंद सुविधाएं

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) और राज्य राजमार्ग (एसएच) सहित अन्य प्रमुख मार्गों के किनारे स्थित 1001 ढाबों की सूची बनाई है। यहां विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी। पर्यटन विभाग की ओर से 25 से 30 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा, ढाबों का बड़ी कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन कराया जाएगा। ताकि, पर्यटकों को इन कंपनियों के प्रोडक्ट भी ढाबों पर आसानी से मिल सकें। ढाबों पर काम करने वाले कर्मचारियों को अच्छे आतिथ्य-सत्कार के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

यह जानकारी पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि पर्यटन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश तेजी से विकास करने वाला राज्य है। यहां वर्ष 2023 में 48 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने भ्रमण किया था। प्रतिदिन देश-दुनिया से लाखों लोग अयोध्या, काशी, मथुरा, बौद्ध स्थल सहित अन्य स्थानों पर पहुंच रहे हैं। राज्य में पर्यटन स्थलों और पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। विभाग का प्रयास है कि पर्यटकों को गंतव्य स्थल तक पहुंचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। पर्यटक कहीं घूमने जा रहे हैं तो

पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन विभाग की नई रणनीति ढाबों की तैयार की गई सूची

सफर में ऐसे स्थल की आवश्यकता होगी, जहां आराम करने के साथ-साथ खाने-पीने सहित अन्य सुविधाएं गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध हों। पर्यटन विभाग इसी जरूरत को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में एनएच, एसएच सहित अन्य प्रमुख मार्गों पर स्थित ढाबों को बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित करने की तैयारी है। काम करने वाले कर्मचारियों को कि पूरे प्रदेश के 1001 ढाबों की सूची तैयार की गई है। पर्यटन विभाग में उनका पंजीकरण किया जा रहा है। इसके बाद ढाबा संचालकों द्वारा सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के तहत कुल खर्च का 25 से 30 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा, यहां काम करने वाले कर्मचारियों को एमकेआईटीएम द्वारा साफ-सफाई और आतिथ्य-सत्कार की ट्रेनिंग दी जाएगी। कर्मियों को बताया जाएगा कि, जो भी पर्यटक यहां आते हैं वह हमारे अतिथि हैं। अतिथि को भगवान का दर्जा दिया गया है। इसलिए उनके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए।

कांवड़ यात्रा ले जा रहे युवक की हादसे में मौत दो गंभीर रूप से घायल



● पुलिस अधीक्षक ने किया घटनास्थल का दौरा

मोहम्मदी खीरी। सीतापुर के महोली से मोटरसाइकिल पर सवार होकर छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ के लिए कावड़ यात्रा लेकर निकले एक युवक की पिकअप से टकरा में घटना स्थल पर मौत हो गई है वहीं पीछे बैठे दो लोगों

के गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस उपाध्यक्ष दलबल के साथ मौके पर पहुंचे तथा उसके उपरान्त पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक ने परिवार वालों से वार्ता की, तथा शव को मोहम्मदी सीएचसी पहुंचाया जहां से पोस्टमार्टम हेतु लखीमपुर भेजा गया, प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि चौकी अमीरनगर के अंतर्गत विपरीत दिशा से आ रहे पिकअप से मोटरसाइकिल

सवार आकाश कश्यप पुत्र राजकुमार 22 वर्ष की मौके पर मौत हो गई वहीं पीछे बैठे शिवा व रितिक कश्यप गंभीर रूप से घायल हो गए मटका आकाश का पंचनामा वर्कर पोस्टमार्टम के लिए लखीमपुर भेजा गया है दोनों घायलों को समुचित इलाज के लिए मोहम्मदी से लखीमपुर रेफर किया गया है, तीनों सीतापुर के महोली के निवासी हैं पिकअप को कब्जे में ले लिया है।

बेतवा नदी के स्लैब मरम्मत का कार्य झूल रहा है लोनिवि व सेतु निगम के बीच

● मरम्मत नहीं हुई तो कमी भी हो सकता है बड़ी घटना,एसई ने कहा कि करेंगे बातचीत

हमीरपुर। सरीला तहसील के बेतवा नदी में बना जलालपुर पथरखु गांव के पुल की खुली स्लैब की मरम्मत का कार्य लोनिवि व सेतु निगम के मध्य इधर उभर झूल रहा है दोनों विभाग के अभियंता इसके लिये एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लिहाजा दो दिन से मरम्मत न होने से कभी कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। तहसील सरीला के जलालपुर गांव के पास बेतवा नदी पर बने पुल की स्लैब के सरिया निकल आने से आने वाले वाहनों के लिए तो खतरा उत्पन्न हो ही गया है साथ ही पुल के भी दरकने की आशंका बढ़ गई है यह पुल करीब पंद्रह साल पहले सेतु निगम ने निर्माण कराया था। पुल की



लंबाई एक किलोमीटर से अधिक है। करोड़ों रुपये की लागत से यह पुल बनाया गया था। पुल की जगह जगह स्लैब खुलने लगी है। पुल की स्लैब पिछले साल भी खुल गयी थी मगर किसी तरह जद्दोजहाद के बाद सेतुनिगम ने मरम्मत करा दी थी। इधर दो दिन पहले पुल की स्लैब फिर से खुल गयी है। लोनिवि निर्माण खंड दो के सहायक अभियंता राधेश्याम गुप्ता का कहना है कि पुल की मरम्मत का काम सेतुनिगम द्वारा कराया जायेगा। लोनिवि के अधिशासी अभियंता ने दो मर्तवा पत्र भी सेतु निगम को लिखा है। जोरकर कहा कि मरम्मत का काम सेतु निगम ही करायेंगे। सेतु निगम के परियोजना प्रबंधक आम्नाब रसूल का कहना है कि उनका काम पुल बनाकर संबंधित विभाग को हैंडओवर करना है।

एआरपी के गोली मारने में आरोपी शिक्षक गिरफ्तार



एमर्जेंसी से 2022 में खरीदा था महिलाओं का बिग

आरोपी में 18 अक्टूबर 2022 को महिलाओं का बिग एमर्जेंसी से 3,999 में खरीदा था। जिसकी फैन डिटेल्स भी पुलिस को आरोपी के मोबाइल से मिली है। आरोपी ने यूट्यूब पर पुलिस कैसे चेक करती है लोकेशन यह भी 12 जुलाई को खोजा था। पुलिस से मोबाइल में रिकार्ड बरामद किया है। खुलासे के लिए चार टीमों का गठन किया गया था। आरोपी की गिरफ्तारी साक्ष्यों के आधार पर की गयी। पुलिस अभिरक्षा में आरोपी ने अपने जुम में इकबाल किया है।

2 साल से बना रह था योजना एसपी आलोक प्रियदर्शी ने

सीडीओ ने की काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस कार्यक्रम के संबंध में बैठक

कानपुर देहात। डीएम आलोक सिंह के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी एन. की अध्यक्षता में काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस से संबंधित कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में बैठक मुख्य विकास अधिकारी कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि ऐतिहासिक घटना काकोरी ट्रेन एक्शन के शताब्दी समारोह अंतर्गत कार्यक्रम आयोजन के संबंध में शासन से दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं।



सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाए। काकोरी ट्रेन एक्शन कार्यक्रम में अंतर्गत कार्यक्रमां जैसे भाषण, पेंटिंग, लोगो डिजाइन, निबंध प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाय।

जूनियर शिक्षकों का स्कूल हेल्थ एवं वैलनेस प्रशिक्षण

पुखराया, कानपुर देहात। आयुष्मान भारत के अंतर्गत विकासखंड अमरीधा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमरीधा में आयोजित पांच दिवसीय स्कूल हेल्थ एवं वैलनेस प्रशिक्षण संपन्न हुआ। जिसके पांचवें दिन शुरुकार को मास्टर ट्रेनर दिनेश बाबू ने किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किशोरावस्था में बच्चे असहज महसूस करते हैं। प्रशिक्षण में यह भी बताया गया कि प्रत्येक जूनियर एवं प्राथमिक विद्यालय से दो हेल्थ एवं वैलनेस एम्बेसडर प्रशिक्षित किए जाएंगे। प्रशिक्षित एम्बेसडर अपने विद्यालय के प्रत्येक कक्षा से दो मैसेंजर एक बालक और बालिका को नियुक्ति करेंगे। सप्ताह में एक बार स्वास्थ्य संबंधी गतिविधि कराई जाएगी। बताया गया कि बच्चों को भूगर्भण से बचाएं। बच्चे सोशल मीडिया एवं इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग करें। कम से कम प्रयोग करें योग और व्यायाम के माध्यम से बच्चों के अंदर स्वस्थ जीवन की शैली को बढ़ाने का प्रयास किया



प्रशिक्षार्थी शिक्षक एवं प्रशिक्षक

जाए। मास्टर ट्रेनर डॉक्टर गिरिराज सिंह ने बताया गया कि बच्चों के अंदर व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाए। उन्हें प्रेरित किया जाए कि जंक फूड का सेवन न करें। बच्चों को बैलेंस डाइट के बारे में बताया जाए। जिससे बच्चे स्वस्थ और निरोगी हो सकें। परिषदीय विद्यालयों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जाने वाली आयरन फेलिक एसिड की गोली बच्चों को सासाह में एक बार अनिवार्य रूप से खिलाई जाए। और अलका शर्मा, सटीप कुमार मोहम्मद साबिर ए अब्दुल वाजिद अंसारी उपस्थित रहे।

किसान अब 10 अगस्त तक करा सकते हैं फसलों का बीमा

लखीमपुर खीरी। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) की अंतिम तिथि बढ़कर 10 अगस्त कर दी है। पहले यह तिथि 31 जुलाई थी। अब जिले के ऋणी एवम गैर ऋणी किसान भाई 10 अगस्त तक फसलों का बीमा करा सकते हैं। यह जानकारी सीडीओ ने दी। सीडीओ ने किसान भाइयों से अनुरोध करते हुए कहा कि अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुये योजना का लाभ लें। ऋणी किसान अपने बैंक शाखा से संपर्क कर यह सुनिश्चित कर लें कि बैंक शाखा द्वारा उनकी फसल का बीमा किया गया है अथवा नहीं। बैंक शाखा को सूचित कर दे तथा गैर ऋणी कृषक आधार काई, स्व प्रमाणित फसल बुवाई का घोषणा पत्र, खतौनी की नकल, पासबुक की छायाप्रति (आईएफएससी कोड) के साथ कामन सर्विस सेंटर, बैंक शाखा से फसल पर देय प्रीमियम अंश को जमा करते हुये अधिसूचित फसल धान, मक्का, मूंगफली एवं उर्द आदि का बीमा करा सकते हैं।

सीज डंपो से हो रही मौरंग की चोरी, प्रशासन को नहीं लग पाती मजक

फतेहपुर। खखेरू थाना क्षेत्र के अंतर्गत कई स्थानों पर सीज पड़े मौरंग के डंपो से आए दिन मौरंग चोरी हो रही है। जिसकी भनक प्रशासन को भी नहीं लग पाती है। जिससे खनन माफियाओं के हाईले बुलंद हैं और रात भर चोरी का सिलसिला चलता है। बताते चले कि बारिश के मौसम में मौरंग खदानों के बंद होने से पहले मौरंग माफियाओं द्वारा बड़ी मात्रा में जगह-जगह मौरंग के डंप लगाए जाते हैं। जिनका खनन विभाग की ओर से चालान व कार्रवाई की जाती है। तहसील क्षेत्र के कबरे, घरवासीपुर, मोईउडीनपुर मोड़ समेत अन्य स्थानों पर लगे मौरंग डंपों पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए उन्हें सीज कर दिया था। सूत्रों के अनुसार सीज मौरंग को भी माफिया नहीं छोड़ रहे हैं और प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में वाहन सहित जेसीबी मौरंग डंप स्थल पहुंच जाते हैं और रात भर मौरंग चोरी का सिलसिला जारी रहता है। शायद अब तक खनन समेत पुलिस विभाग को इनकी भनक नहीं लग सकी है।

जिलाधिकारी ने खरीफ गोष्ठी व तिलहन मेले का किया शुभारंभ

● मिलेट्स, तिलहन व दलहन फसलों के मिनीकट व मृदा स्वास्थ्य कार्ड का करारा वितरण

फतेहपुर। शुरुकार को प्रेक्षागृह सभागार में जनपद स्तरीय खरीफगोष्ठी के साथ कृषि सूचना तंत्र के सुदृढीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद स्तरीय किसान मेला, त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के अंतर्गत खरीफ गोष्ठी व नेशनल मिशन आन एडिडविल आयल योजना के अंतर्गत खरीफ तिलहन मेले का आयोजन किया गया। डीएम के अलावा सीडीओ, अपर जिलाधिकारी न्यायिक, उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी, भूमि संरक्षण अधिकारी, भूमि संरक्षण अधिकारी ईईसी सहित तमाम अधिकारियों व प्रगतिशील किसानों ने हिस्सा लिया। गोष्ठी में

विभिन्न विभागों द्वारा स्टाल लगाए गए। डीएम ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उप कृषि निदेशक राम मिलन सिंह परिहार ने संचालन करते हुए कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर अधिकारियों का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। डीएम ने कृषकों से सीधा संवाद स्थापित करते हुए अग्रगत कराया कि फसल क्राप कैलेंडर को कृषकों की मांग के अनुसार 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक शासन द्वारा विस्तार कर दिया गया है। कृषकों की उर्वरक की अधिक मांग के दृष्टिगत जनपद में अधिक केले के उत्पादन को देखते हुए केले की फसलों के क्षेत्रफल में जोड़कर शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। जिससे कृषकों की मांग के अनुसार गत वर्ष की अपेक्षा वर्तमान वर्ष में अधिक उर्वरक जनपद को उपलब्ध होगा। डीएम ने विद्युत समस्या के निदान हेतु अग्रगत कराया कि 11 केवी नया फीडर तैयार किया जा रहा है। जो तीन माह में बनकर तैयार हो जाएगा।

कीचड़ युक्त गलियों से निकलना हुआ दुश्वार

● ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन डीएम से की विकास कार्यों की मांग ● गंगागंज गुरौली में गौशाला में गायों की स्थिति हुई दयनीय, भूख प्यास से हो रही बीमार

गुरसहायगंज (कन्नौज)। गंगागंज गुरौली स्थित गौशाला में भूख प्यास तड़प रही गायों का बुरा हाल है। वही सिंगपुर में विकास कार्यों के अभाव में कीचड़ युक्त गलियों से ग्रामीणों का निकलना दुश्वार हो गया है। विकास कार्यों के नाम पर प्रधानों एवं सचिवों द्वारा गोलमाल का आरोप ग्रामीणों द्वारा लगाया गया है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर जिला प्रशासन से जांच करवाए जाने एवं विकास कार्य करवाने की मांग की है। विडंबना है कि प्रदेश सरकार गौशालाओं में गायों की सुरक्षा हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम एवं योजनाएं चला रही है। समय-समय पर अधिकारियों को गाइडलाइन भी दी



गौशाला में बीमार पड़ी गाय, कीचड़ युक्त पानी से निकलते एवं प्रदर्शन करते ग्रामीण।

जाती है। इसके बावजूद भी अधिकारी एवं जिम्मेदार ध्यान नहीं देते हैं। क्षेत्र के ग्राम गंगागंज दुर्गली स्थित गौशाला में लगभग एक दर्जन पालतू गायों में एक गाय गंभीर रूप से घायल है और दूसरी गाय गाय भी बीमार होकर तड़प रही है। केयटटेकर मौके से गाथव उसके स्थान पर उसका उसका बच्चा गौशाला की सफाई कर रहा था। चारा के स्थान पर सूखा भूसा भी नहीं था। पूंछे जाने पर सचिव विमल दुबे ने कहा कि निरीक्षण किया जा चुका है। गायों का इलाज चल रहा है उभर ताराग्राम ब्लाक के ग्राम सिंगपुर में विकास कार्यों से सफाई के अभाव में गलियां कीचड़ पानी से भरी है। कीचड़ युक्त गलियों से निकलना ग्रामीणों की मजबूरी है। ग्राम

जिला अस्पताल पहुंचे पूर्व केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जनरल सर्जरी वार्ड सहित ओपीडी व ब्लड बैंक का किया निरीक्षण

लखीमपुर खीरी। जिला अस्पताल एमसीएच विंग ओयल में दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी करने पूर्व केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी शुरुकार को अस्पताल पहुंचे। जहां उन्होंने अल्ट्रा साउण्ड रूम, एक्सरे रूम व पैथोलॉजी सहित जनरल सर्जरी वार्ड, ओपीडी व ब्लड बैंक का भ्रमण कर मरीजों से मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी करी। इस दौरान सीएमओ डॉ सन्तोष गुप्ता, सीएमएस डॉ आरके कोली व सीएमएस एमसीएच विंग डॉ ज्योति मेहरोजा भी मौजूद रहें। शुरुकार को करीब 11 बजे पूर्व केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी जिला अस्पताल पहुंचे, जहां सीएमएस डॉ ज्योति मेहरोजा द्वारा बुके देकर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद वह सीधे एक्स रे व अल्ट्रासाउण्ड कक्ष में पहुंचे। जहां पर बैठे हुये मरीजों से उन्होंने मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी की, उन्होंने एक महिला

उनके तीमारदारों से बात की और दवाओं के बारे में पूंछा जिस पर सभी ने अस्पताल से ही दवाएं मिलने की बात कही। यहां की व्यवस्थाएं देखी, मरीजों के लगी मच्छरदानी के बारे में पूंछा जिस पर सीएमओ डॉ सन्तोष गुप्ता ने बताया कि डेंगू से पीड़ित मरीज को अगर मच्छर काटे और वह मच्छर दुबारा किसी सामान्य व्यक्ति को काट ले तो उसे भी डेंगू होने का खतरा बढ़ जाता है, इसीलिए इन मरीजों के लिए अलग वार्ड है और इन्हें मच्छरदानी में रखा जाता है।

उनके तीमारदारों से बात की और दवाओं के बारे में पूंछा जिस पर सभी ने अस्पताल से ही दवाएं मिलने की बात कही। यहां की व्यवस्थाएं देखी, मरीजों के लगी मच्छरदानी के बारे में पूंछा जिस पर सीएमओ डॉ सन्तोष गुप्ता ने बताया कि डेंगू से पीड़ित मरीज को अगर मच्छर काटे और वह मच्छर दुबारा किसी सामान्य व्यक्ति को काट ले तो उसे भी डेंगू होने का खतरा बढ़ जाता है, इसीलिए इन मरीजों के लिए अलग वार्ड है और इन्हें मच्छरदानी में रखा जाता है।

पुलिस ने अंतर्जनपदीय गिरोह के चार बदमाशों को दबोचा

कन्नौज। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनन्द के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं क्षेत्राधिकारी छिब्रामऊ ओमकार नाथ शर्मा के पर्यवेक्षण मे थाना छिब्रामऊ पुलिस द्वारा घरो का ताला तोड़कर चोरी करने वाले अंतर्जनपदीय गिरोह के चार शांतिर अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार कर चोरी हुए जेवरत व हजारां रुपये की नगदी बरामद की। शुरुकार को पुलिस कार्यालय में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनन्द ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुये बताया कि विगत 27 जुलाई को अरविन्द कुमार दुबे निवासी मोहल्ला नयी वस्ती भैनपुरा थाना छिब्रामऊ ने अज्ञात चोरों द्वारा घर का ताला तोड़कर पांच लाख रुपये के जेवरत, 54,600 की नगदी 12 कारतूस 12 बोर, कपड़े व अन्य सामान चोरी कर लिये थे। अज्ञात चोर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में व साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण अजीत जाटव पुत्र धनपाल जाटव निवासी ग्राम भारपुर थाना छिब्रामऊ, शीलेश यादव पुत्र



चोरी की घटना का खुलासा करते एसपी व छिब्रामऊ सीओ।

कालीचरन यादव निवासी गढी मदारी थाना पचोखरा मिरोजवाब, सुरील जाटव पुत्र लखू सिंह निवासी ग्राम किनावर थाना विख्या मैनुपुरी, दीपक जाटव पुत्र स्व. रामनरेश निवासी हलपुरा थाना द्वाहार मैनुपुरी को छिब्रामऊ फरुखाबाद मार्ग पर स्थित इण्डियन आयल पेट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से अरविन्द कुमार दुबे (रिटायर्ड सैनिक) के घर से चोरी किये गये जेवरत व नगदी तथा 12 कारतूस 12 बोर व घटना में प्रयुक्त औजार व एक

तमंचा 315 बोर व एक कारतूस बरामद हुआ। धारा 317(2) बोअनएस की बढोत्तरी की गयी अभियुक्तगण ने करीब एक 5 माह पूर्व चौकी सिन्दरपुर थाना छिब्रामऊ क्षेत्र के ग्राम शहजहाँपुर में पंचायत घर से चोरी की घटना को अंजाम दिया था जिसके सम्बन्ध में थाना छिब्रामऊ पर मुकदमा पंजीकृत है। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढोत्तरी कर अजीत जाटव व शीलेश यादव को न्यायालय के समक्ष भेजा गया।

निःशुल्क लगवाएं स्मार्ट मीटर गलत बिलों से पाएं छुटकारा

फतेहपुर। दोआबा के बिजली उपभोक्ताओं को अब स्मार्ट मीटर से बिजली आपूर्ति देने की तैयारी तेजी पर है। पूरे जिले के बिजली उपभोक्ताओं के घरों में लगे डिजिटल मीटर को पहले हटवाया जा रहा है। इसके बाद स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को मीटर रीडिंग की गड़बड़ी और गलत बिलों से छुटकारा मिल जाएगा, वहीं अधिकारी किसी भी मीटर का ऑनलाइन जायजा भी ले सकेंगे।

काफ़ी हद तक घंटेगा। अभी तक डिजिटल मीटर से बिजली आपूर्ति दी जा रही है। इससे मीटर से छेड़छाड़ कर बिजली चोरी, रीडिंग स्टोर करने के मामले थमने का नाम नहीं ले रही है। इस समस्या से निजात पाने को अब उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर से आपूर्ति देने की तैयारी तेजी पर है। इसकी कवायद शुरू हो गई है, सभी डिजिटल मीटर को हटवाया जाएगा, जिसके स्थान पर स्मार्ट मीटर से आपूर्ति मिलेगी।

जिला अस्पताल पहुंचे पूर्व केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जनरल सर्जरी वार्ड सहित ओपीडी व ब्लड बैंक का किया निरीक्षण

लखीमपुर खीरी। जिला अस्पताल एमसीएच विंग ओयल में दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी करने पूर्व केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी शुरुकार को अस्पताल पहुंचे। जहां उन्होंने अल्ट्रा साउण्ड रूम, एक्सरे रूम व पैथोलॉजी सहित जनरल सर्जरी वार्ड, ओपीडी व ब्लड बैंक का भ्रमण कर मरीजों से मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी करी। इस दौरान सीएमओ डॉ सन्तोष गुप्ता, सीएमएस डॉ आरके कोली व सीएमएस एमसीएच विंग डॉ ज्योति मेहरोजा भी मौजूद रहें। शुरुकार को करीब 11 बजे पूर्व केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी जिला अस्पताल पहुंचे, जहां सीएमएस डॉ ज्योति मेहरोजा द्वारा बुके देकर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद वह सीधे एक्स रे व अल्ट्रासाउण्ड कक्ष में पहुंचे। जहां पर बैठे हुये मरीजों से उन्होंने मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी की, उन्होंने एक महिला



उनके तीमारदारों से बात की और दवाओं के बारे में पूंछा जिस पर सभी ने अस्पताल से ही दवाएं मिलने की बात कही। यहां की व्यवस्थाएं देखी, मरीजों के लगी मच्छरदानी के बारे में पूंछा जिस पर सीएमओ डॉ सन्तोष गुप्ता ने बताया कि डेंगू से पीड़ित मरीज को अगर मच्छर काटे और वह मच्छर दुबारा किसी सामान्य व्यक्ति को काट ले तो उसे भी डेंगू होने का खतरा बढ़ जाता है, इसीलिए इन मरीजों के लिए अलग वार्ड है और इन्हें मच्छरदानी में रखा जाता है।

देश में निर्माण होने पर जनहित याचिकाएं क्यों दायर की जाती हैं: शीर्ष अदालत हैरान

नई दिल्ली। विकास और पारिस्थितिकी संतुलन को महत्वपूर्ण बताते हुए उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को इस बात पर हैरानी जताई कि जब राजमार्ग जैसी ढांचगत परियोजनाएं शुरू की जाती हैं तो जनहित याचिकाएं (पीआईएल) क्यों दायर की जाती हैं? शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी गोवा में तिनैथा-वास्को डी गामा मार्ग के वास्को डी गामा-कुलेम खंड पर रेलवे पटरियों के दोहरीकरण से जुड़े निर्माण कार्य पर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान की। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा, हम केवल यह सोच रहे हैं कि ऐसा केवल इस देश में ही क्यों होता है कि जब आप हिमाचल प्रदेश में सड़क बनाना शुरू करते हैं, तो जनहित याचिकाएं आ जाती हैं। जब आप राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाना

शुरू करते हैं, तो जनहित याचिकाएं आ जाती हैं। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा, आप हमें एक भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बताएं जहां रेलवे की सुविधा नहीं है। पीठ ने कहा, आरम्भ पर्वत पर जाएं और वे आपको ट्रेन में बर्फ के बीच से ले जाएंगे।

शीर्ष अदालत बंबई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ के अगस्त 2022 के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने रेलवे पटरी के दोहरीकरण के निर्माण से संबंधित एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में आरोप लगाया था कि निर्माण कार्य वर्ष 2011 के तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना, गोवा सिंचाई अधिनियम-1973, गोवा पंचायत राज अधिनियम-1994 और

गोवा शहर एवं नगर नियोजन कानून के तहत पूर्व अनुमति प्राप्त करने के वैधानिक आदेश का उल्लंघन करके किया जा रहा था। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह परियोजना गोवा में रेलवे नेटवर्क को मजबूत करेगी और सड़क परिवहन पर बोझ को कम करने में मदद करेगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने अनियोजित विकास के खतरों पर प्रकाश डालते हुए केरल के वायनाड जिले की हालिया घटना का जिक्र किया जो 195 लोगों को जान ले ली। गोवा में रेलवे लाइन परियोजना पर पीठ ने कहा कि विशेषज्ञ हैं जो हर चीज की जांच करेंगे।

वकील ने कहा कि रेलवे लाइन पारिस्थितिकीय रूप से नाजुक क्षेत्र से होकर गुजरती है और याचिका को विकास विरोधी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। पीठ ने कहा, विकास और पारिस्थितिकी संतुलन साथ-साथ

चलने चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई भी अंधाधुंध विकास की इजाजत नहीं दे सकता। आखिरकार हम कानून के शासन द्वारा शासित हैं। पीठ ने वकील से कहा कि किसी बात को लेकर कोई अस्तित्वहीन या धामक आशंका नहीं होनी चाहिए। जब वकील ने तर्क दिया कि गोवा की तटरेखा पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र है तो पीठ ने कहा, आपका अंतिम तर्क यह है कि वहां रेलवे लाइन नहीं होनी चाहिए... जब शानदार वाहनों में लोग वहां जाते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होती। उनके पास आलीशान बंगले हैं, उनके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं है। शीर्ष अदालत ने इसके बाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया।

उच्च न्यायालय ने घाटल लोकसभा सीट के सभी कागजात, सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया

कोलकाता (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय के शुक्रवार को निर्देश दिया कि परिषद बंगाल के घाटल लोकसभा क्षेत्र में चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज और सीसीटीवी फुटेज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार हिरण्मय चट्टोपाध्याय द्वारा दायर चुनाव याचिका के निपटारे तक सुरक्षित रखे जाएं। घाटल से तुगमूल कांग्रेस के दीपक अधिकारी को विजेता घोषित किया गया, जहां 25 मई को चुनाव हुए थे। अदालत ने निर्देश दिया कि चुनाव याचिका पर निर्णय होने तक, घाटल निर्वाचन क्षेत्र में हुए चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज, उपकरण, सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (डीवीआर) को ऐसे दस्तावेजों के संरक्षक प्राधिकारी द्वारा संरक्षित रखा जाए। न्यायमूर्ति बिवास पटनायक ने उच्च न्यायालय के संबंधित रजिस्ट्रार को इस आदेश की एक प्रति मुख्य

निर्वाचन आयुक्त को देने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के फॉरेंसिक ऑडिट के लिए याचिकाकर्ता के वकील के अनुरोध पर छह सितंबर को आगली सुनवाई में फैसला किया जाएगा।

भाजपा के हिरण्मय चट्टोपाध्याय और तुगमूल के दीपक अधिकारी दोनों ही फिल्म अभिनेता हैं और फिल्म जगत में क्रमशः हिरण और देव के नाम से चर्चित हैं। चट्टोपाध्याय के वकील विलवदल भट्टाचार्य ने कहा कि याचिका में कथित भ्रष्ट आचरण के आधार पर चुनाव प्रक्रिया को चुनौती दी गई है।

उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों में सीसीटीवी फुटेज, ईवीएम और डीवीआर सहित रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए आदेश देने का अनुरोध किया। न्यायमूर्ति पटनायक ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया।

ट्रांसजेंडर के रक्तदान पर रोक लगाने संबंधी निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें ट्रांसजेंडर, समलैंगिक और यौनकर्मियों को रक्तदान करने से रोकने वाले दिशानिर्देशों को चुनौती दी गई है। प्रधान न्यायाधीश डी वॉलें चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने किंग्स सक्कर, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन और राष्ट्रीय रक्तदान परिषद को नोटिस जारी किए। शीर्ष अदालत कार्यकर्ता शरीफ डी रंगेकर द्वारा 2017 के दिशानिर्देशों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दिशा निर्देश में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने वाले पुरुषों (एमएसएम) और महिला यौनकर्मियों को रक्तदाता बनने से बाहर रखा गया है। वर्ष 2017 के दिशानिर्देश एचआईवी और हेपेटाइटिस संक्रमण या ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिस्सिबल इंफेक्शन (टीडीआई) के जोखिम के कारण इन्हें रक्तदाता बनने से स्थाई रूप से रोकते हैं।

एशियानेट न्यूज नेटवर्क के खिलाफ दिव्या स्पंदना के मानहानि के मामले को रद्द करने से इनकार

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अभिनेत्री-राजनेता दिव्या स्पंदना द्वारा एशियानेट न्यूज नेटवर्क और पत्रकार विश्वेश भट के खिलाफ दायर मानहानि का मामला रद्द करने से इनकार कर दिया। स्पंदना ने एशियानेट न्यूज और अन्य के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग कांड में कन्नड़ फिल्म अभिनेत्रियों की कथित सलिपता की खबर प्रसारित की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि समाचार प्रसारित होने के दौरान शिकायतकर्ता का नाम बार-बार लिया गया तथा उनके फोटो और वीडियो दिखाए गए।

स्पंदना द्वारा दायर शिकायत में विशेष रूप से कहा गया है कि समाचार को इस तरह से प्रसारित किया जा रहा था, जैसे शिकायतकर्ता स्वयं कथित क्रिकेट सट्टेबाजी या स्पॉट फिक्सिंग कांड में शामिल हो। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़



और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया। अदालत उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

पीठ ने कहा, उनका (स्पंदना का) बार-बार बुलेटिन में उल्लेख किया गया है, हम आदेश को कैसे रद्द कर सकते हैं? हम इस पर विचार नहीं कर सकते। शीर्ष अदालत एशियानेट न्यूज नेटवर्क और अन्य द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी।

शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन: न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा से स्थिति को और खराब न करने को कहा

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा सरकारों से कहा कि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सहित अन्य मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से संपर्क करने के लिए एक स्वतंत्र समिति गठित करने के वास्ते कुछ तटस्थ व्यक्तियों के नाम सुझाएं। न्यायालय ने कहा कि किसी को भी स्थिति को बिगाड़ना नहीं चाहिए। न्यायालय ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को अपनी शिकायतें व्यक्त करने का अधिकार है और वह सभी पक्षों को शामिल करते हुए वादाचिती को एक सहज शुरुआत चाहता है।

शीर्ष अदालत पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें राज्य सरकार को एक स्पष्टाह के भीतर अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड हटाने के लिए कहा

दहेज हत्या मामले में पति को दस साल और सास व ससुर को सात-सात साल की सजा

बलिया। बलिया की एक स्थानीय अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में बृहस्पतिवार को मुत्का के पति, सास और ससुर को दोषी करार देते हुए उन्हें क्रमशः दस साल औरसात - सात साल के कारावास की सजा सुनाई। पुलिस अधीक्षक विक्रान्त वीर ने शुक्रवार को बताया कि अग्र जिला जज रवि किरण सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पति धर्मेन्द्र वर्मा , ससुर बेरन प्रसाद वर्मा और सास मंजू देवी को दोषी करार देते हुए पति को दस साल और सास व ससुर को सात - सात साल के कारावास और प्रत्येक को तीन - तीन हजार रूपए के अर्थदंड को सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि बिहार राज्य के बस्सर जिले के काली नगर सोहनी के रहने वाले कृष्ण सिंह ने अपनी पुत्री शशि कला को शादी गत फरवरी 2012 में फेफना थाना क्षेत्र के कोपवा बहादुरपुर गांव के धर्मेन्द्र वर्मा के साथ की थी।

अंतरिम आदेश का अनुरोध किया, क्योंकि इस महीने के अंत में लाभार्थियों को राशि वितरित की जाएगी। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ ने अनुरोध को खारिज करते हुए कहा कि याचिका पर नियमित प्रक्रिया के अनुसार सुनवाई की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय ने कहा, नियमित प्रक्रिया की प्रणाली को निरर्थक न बनाएं। कहीं तोड़फोड़ की कारवाई हो रही है या किसी को फांसी पर लटकया जा रहा हो..तब अत्यावश्यक कार्यवाही होती है।

उच्च न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार, जनहित याचिका पर पांच अगस्त को सुनवाई होने की संभावना है। याचिकाकर्ता नवीद अब्दुल सईद मुल्ला ने दावा किया कि संबंधित सरकारी योजना के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करदाताओंराजकोष पर

अतिरिक्त बोझ डाला जाता है, क्योंकि करों को अवसंरचना विकास के लिए एकत्र किया जाता है, न कि बेतुकी नकद योजनाओं के लिए।

उन्होंने कहा, ऐसी नकद लाभ योजनाएं, आगामी राज्य विधानसभा चुनावों में मौजूदा गठबंधन सरकार में शामिल दलों को ओर से किसी खास वर्ग के मतदाताओं को किसी विशेष उम्मीदवार के पक्ष में वोट के लिए रिश्तत या उपहार देने के समान हैं। याचिका में कहा गया कि ऐसी योजना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के विरुद्ध है और भ्रष्ट आचरण के समान है। याचिका में दावा किया गया कि महिलाओं के लिए इस योजना पर लगभग 4,600 करोड़ रूपए खर्च होंगे और यह महाराष्ट्र पर बहुत बड़ा बोझ है, जिस पर पहले से ही 7.8 लाख करोड़ रूपए का कर्ज है, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने अधिविश्वास, जाटू-टोना उन्मूलन के लिए व्दम उठाने संबंधी याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने अधंविश्वास, जाटू-टोना और इसी तरह की अन्य प्रशाओं के उन्मूलन के लिए केंद्र और राज्यों को उचित कदम उठाने के निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि अधंविश्वास को खत्म करने का उपाय शिक्षा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि समालों में संसद को हस्तक्षेप करना चाहिए। पीठ ने कहा, हम यह आदेश कैसे जारी कर सकते हैं कि वैज्ञानिक सोच विकसित करने और अधंविश्वास को खत्म करने के लिए कदम उठाए जाएं। संविधान निर्माताओं ने यह सब राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया था। पीठ द्वारा मामले पर सुनवाई से इनकार करने के बाद याचिकाकर्ता अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने याचिका वापस ले ली।

ओडिशा की अदालत ने हत्याकाण्ड में 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

बेहामपुर (ओडिशा)। ओडिशा के गजपति जिले की एक अदालत ने करीब 15 वर्ष पहले एक व्यक्ति की हत्या के मामले में 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) प्रदीप कुमार सामल ने बृहस्पतिवार को कुल 16 आरोपियों को 12 मार्च 2009 को होली के दिन पुरानी रंजिश के कारण सिबा नागाबांस का परलाखेमूंडी के घासी साही स्थित उसके आवास पर बुरी तरह पिटाई करने के मामले में दोषी ठहरया। पिटाई से उसकी मौत हो गई थी। लोक अभियोजक ब्रुंदावन नायक ने बताया कि दो आरोपियों को हत्या ही मौत हो चुकी है, जबकि 14 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। नायक ने बताया कि अदालत ने दोनों पर 10-10 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। नायक ने बताया कि आरोपियों ने होली खेलने के बाद गहरी नींद में सो रहे सामल के घर में घुसकर उस पर हमला कर दिया था। छह दिन बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसी दिन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नौ अगस्त 2010 को पुलिस ने आरोपपत्र दायर किया था और आरोपी जमानत पर थे।

जरांगे के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट रद्द

पुणे। पुणे की एक अदालत ने कथित धोखाधड़ी के एक मामले में आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) शुक्रवार को रद्द कर दिया। जरांगे 23 जुलाई को अदालत में पेश नहीं हुए थे जिसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) की अदालत ने 2013 के धोखाधड़ी के एक मामले में जरांगे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। आरक्षण कार्यकर्ता शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) के समक्ष पेश हुए, वहीं उनके वकील हर्षद निंबालकर ने एक अर्जी दाखिल करके गैर जमानती वारंट रद्द करने का अनुरोध किया। अदालत ने अर्जी स्वीकार कर ली और जरांगे के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को रद्द कर दिया। जरांगे और दो अन्य के खिलाफ 2013 में भारतीय दंड संहिता की धारा 420(धोखाधड़ी) और 406 (अपराधिक विश्वासघात) के तहत मामला दर्ज किया गया था। (धोखाधड़ी) और 406 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत मामला दर्ज किया गया था। जरांगे और सह-आरोपी ने 2012 में शिकायतकर्ता से संपर्क किया था। यह व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज पर नाटक का काम करता था और उन लोगों ने उसे जालना जिले में शंभुराजे के छह शो करने और उसे 30 लाख रूपए की पेशकश की थी। मामले के अनुसार 16 लाख रूपए का भुगतान तो कर दिया गया लेकिन बाकी पैसे को लेकर कुछ विवाद हुआ जिसके बाद शिकायत दर्ज की गई। इसके बाद अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने का आदेश दिया।

अदालत ने क्वेचिंग सेंटर में अभ्यर्थियों की मौत के लेक्व पुलिस, एमसीडी के फटकार लगाई

नई दिल्ली।दिल्ली उच्च न्यायालय ने यहां राजेंद्र नगर में स्थित एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे तीन अभ्यर्थियों की मौत होने की घटना पर शुक्रवार को पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को फटकार लगाई और कहा कि वह यह समझ नहीं पा रही है कि विद्यार्थी बाहर कैसे नहीं आ सके। पीठ ने सवाल किया कि एमसीडी अधिकारियों ने क्षेत्र में बरसाती नालों के ठीक ठंा से काम नहीं करते के बारे में आयुक्त को सूचित क्यों नहीं किया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गोंडेला की पीठ ने कहा कि एमसीडी अधिकारियों को इसकी कोई प्रकटाह नहीं है और यह एक सामान्य बात हो गई। अदालत ने पुलिस पर फटकार करते हुए कहा, जिस तरह से आपने वाहन चालक को वहां कार चलाने के लिए गिरफ्तार किया, गनीमत है कि आपने बेसमेंट में घुसने वाले बारिश के पानी का चालान नहीं करा।

पेज 1 का शेष कोचिंग सेंटर...

चालक मनुज कथुरिया पर आरोप था कि वह 27 जुलाई को अपना वाहन लेकर जलमगन सड़क से गुजरे थे जिससे पानी तीन मंजिला इमारत के गेट से टकराया और इससे गेट टूट गया जहां कोचिंग सेंटर स्थित था। आरोप था कि इससे इमारत के बेसमेंट में पानी भर गया जिसमें डूबने से तीन विद्यार्थियों की मौत हो गई। अदालत ने छात्रों के डूबने की घटना को लेकर पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को फटकार लगाते हुए कहा कि वह यह समझ पाने में असमर्थ है कि छात्र बाहर कैसे नहीं आ सके। अदालत ने साथ ही यह भी जानना चाहा कि क्या दरवाजे अवरुद्ध थे या सीढ़ियां संकरी थीं। पीठ ने कहा कि प्रशासनिक तौर पर दिल्ली में कई प्राधिकारी हैं जो केवल जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डाल रहे हैं और इसके अलावा कुछ कर नहीं रहे हैं। इसने कहा कि आम धारणा यह है कि नगर निगम के अधिकारी अक्षम हैं। पीठ ने कहा कि दिल्ली में भौतिक बुनियादी ढांचा करीब 75 साल पुराना है और यह न केवल अपर्याप्त है, बल्कि इसका रखरखाव भी ठीक से नहीं किया जाता। अदालत में

मौजूद एमसीडी आयुक्त द्वारा यह बताया जाने पर कि इलाके में बरसाती नालों से पानी की निकासी ठीक ढंग से नहीं हो रही थी, पीठ ने सवाल किया कि अधिकारियों ने एमसीडी प्रमुख को इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। पीठ ने राजेंद्र नगर क्षेत्र में अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण को हटाने का भी आदेश दिया, जिसमें बरसाती नालों और सीवेज नालों पर किया गया अतिक्रमण भी शामिल है। इसने कहा कि एमसीडी अधिकारियों को इसकी कोई परवाह नहीं है और यह एक आम बात हो गई है। अदालत ने कहा कि दिल्ली की आबादी बढ़ने के साथ ही शहर को एक मजबूत व्यवस्था की जरूरत है और विभिन्न स्विसडी योजनाओं के कारण राष्ट्रीय राजधानी में पलायन भी बढ़ रहा है। पीठ ने कहा कि दिल्ली के प्रशासनिक, वित्तीय और भौतिक बुनियादी ढांचे पर फिर से विचार करने का समय आ गया है। पीठ ने इस मुद्दे से निपटने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इस बीच, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने राजेंद्र नगर में स्थित कोचिंग सेंटर में हुई मौतों के विरोध में अपना प्रदर्शन शुक्रवार को छठे दिन भी जारी रखा। वहीं, प्रदर्शन स्थल पर कई छात्र पहाई करते देखे गए।सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे गौतम ने कहा, हम अपना विरोध जारी रखेंगे, लेकिन हमारे लिए पहाई भी महत्वपूर्ण

है। इसलिए विरोध स्थल पर बैठे लोग अपनी अध्यक्षता समग्रि लेकर आए हैं। इस बीच, कम से कम चार यूपीएससी कोचिंग सेंटरों- वाजीम एंड रवि इंस्टिट्यूट, टूटिप आईएएस, नेक्स्ट आईएएस और श्रीराम आईएएस ने बेसमेंट घटना में जान घटाने वाले तीन विद्यार्थियों- श्रेया यादव, तान्या सोनी और नेविन डेलिनन के परिवारों को 10-10 लाख रूपए की सहायता राशि देने की पेशकश की। इन तीनों छात्रों को 27 जुलाई को ओरुड राजेंद्र नगर में राऊआईएएस स्टडी सेंकिल के बेसमेंट में बारिश का पानी भर जाने से मौत हो गई थी।

नीट-यूजी...

सोशल मीडिया या इंटरनेट का उपयोग करके व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था, या परिकृत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करके छात्रों को उत्तर बाधता जा रहे थे। पता लगाना कठिन साबित हो सकता है।पीठ ने कहा, हजारीबाग और पटना में लोक से लाभाभर्थी होने वाले छात्रों की पहचान की जा सकती है। सीबीआई जांच से इस स्तर पर उन छात्रों की संख्या का पता चलता है जो हजारीबाग और पटना में कदाचार के लाभाभर्थी हैं। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह है कदाचार या धोखाधड़ी के लाभाभर्थियों को ईमानदार छात्रों से अलग करना संभव है, इस मामले में,

के रूप में उनके पहले कार्यकाल के दौरान नीट लाए जाने से पहले चिकित्सा शिक्षा में भ्रष्टाचार व्याप्त था। उन्होंने जोर देकर कहा कि एनईटी से पहले, चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र गंभीर कदाचार से ग्रस्त था, जिसमें 8 करोड़ रुपये से 13 करोड़ रुपये तक की अत्यधिक कर्मच के लिए सहायकोत्तर सीटों की चिक्री भी शामिल थी।नड्डा ने कहा, मेडिकल शिक्षा एक व्यवसाय का अड्डा बन गई थी। जब में स्वास्थ्य मंत्री था और नीट ला रहा था तो पोस्ट ग्रेजुएशन की एक सीट 8 करोड़ रुपये में बेची गई थी और अगर आपको रेडियोलॉजी जैसे विषय का चयन करना था तो यह 12-13 करोड़ रुपये था।

आशा किरण...

नहीं सौंपा है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल अब तक 28 मानसिक रूप से बीमार कैदियों की मौत हो चुकी है। जुलाई में हुई कुल 14 मौतों में से 10 मौतें महीने के आखिरी हिस्से में हुईं, जिनमें एक 14 साल के लड़के की मौत भी शामिल है। शेल्टर कोम की मेडिकल केयर यूनिट के मुताबिक, ज्यादातर मृतकों को सांस लेने में दिक्कत और दस्त की शिकायत थी।एलजी ने दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी शेल्टर होम की स्थिति पर एक व्यापक जांच का आदेश दिया और एक सप्ताह के भीतर जिम्मेदारी तय करने वाली रिपोर्ट पेश की।

कॉर्नर मिला लेकिन हमनप्रीत गोल नहीं कर सके। तीसरे क्वार्टर में भारत को दूसरे ही मिन्ट में शेंटली कॉर्नर मिला लेकिन हमनप्रीत का पेंलट बचा लिया गया। भारतीय टीम ने वीडियो को अपने साथ ले गए।' 18 जुलाई को शाम वे उसे गांव के बाहर खेत की ओर ले गए और उसकी पिटाई की; फिर उसके गले में रस्सी भी शामिल थी।नड्डा ने कहा, मेडिकल ह्यूड ने मिट्टी छोदी।।मेरा बेटा बेहोश था, और जैसे ही कुत्ते ने उसे खींचना शुरू किया, वह होश में आ गया। बाद में हम उसे अस्पताल ले गए जहां वह ठीक हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आस्ट्रेलिया के वीडियो रेफरल पर उसे अमान्य चोथे ही मिन्ट में पेनल्टी कॉर्नर बनाया। इस पर गोवर्स ब्लैक के शॉट को श्रंजेश ने बड़ी वजुदाई से बचाया। अगले ही पल एक और पेनल्टी कॉर्नर पर भी यही कहानी रही लेकिन शॉट शार्प रोमांचक बना दिया।भारतीय डिफेंस ने आखिरी पांच मिन्ट जबरदस्त संयम का प्रदर्शन करते हुए आस्ट्रेलिया के नामचीन स्ट्राइकर्स को कोई मौका नहीं दिया।

जवाबदेही से बचने को राहुल उठा रहे हैं काल्पनिक मुद्दे: भाजपा

भाषा। नई दिल्ली

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राहुल गांधी की ओर से अपने खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी की तैयारी का दावा करने के लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि वायनाड से सांसद के रूप में अपनी जवाबदेही से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वह एक नई कहानी गढ़ रहे हैं। भाजपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रज्जीव चंद्रशेखर ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा कि हो सकता है कि राहुल गांधी से कहा गया हो कि लोग उनकी जवाबदेही के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक नया विमर्श गढ़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि गांधी ने वायनाड से जुड़े सवालों से बचने के लिए एक काल्पनिक मुद्दा उठाया है। उन्होंने



दावा किया कि लोग उनकी जवाबदेही के बारे में पूछ रहे हैं। विपक्ष के नेता के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा की सहयोगी जनता दल (यूनाइटेड) के नेता ललन सिंह ने कहा कि गांधी ने कुछ ऐसा किया होगा तभी उन्हें लग रहा है कि उनके खिलाफ इस प्रकार की कावाई हो सकती है।इन्होंने संवाददाताओं से कहा, अगर किसी ने कोई गलत नहीं किया है तो उसे कुछ क्यों होगा ? गांधी 2019 और 2024 के लोकसभा



चुनावों में वायनाड से चुने गए थे। साल 2024 के चुनाव में उन्होंने वायनाड के साथ-साथ रायबरेली से भी जीत दर्ज की थी। बाद में उन्होंने वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया और रायबरेली सीट बरकरार रखी।कांग्रेस ने घोषणा की है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी। दोनों भाई-बहन फिलहाल वायनाड के दौर पर हैं जहां वे प्रभावित परिवारों से मिल रहे हैं।राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच

मेरे खिलाफ ईडी की छापेमारी की तैयारी, खुले दिल से इंतजार कर रहा हूं: राहुल गांधी

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को दावा किया कि सदन में परक्यूड वाले माषण के बाद उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी की तैयारी हो रही है।उन्होंने यह भी कहा किवह ईडी के लोगों का खुले दिल से इंतजार कर रहे है तथा उन्हें वह अपनी तर्फ से चाय- बिस्कुट पेश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राहुल गांधी के इस दावे को लेकर कहा कि वायनाड से सांसद के रूप में अपनी जवाबदेही से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वह एक नई कहानी गढ़ रहे है। राहुल गांधी 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावो मे वायनाड से चुने गए थे। उन्होंने इस बात वायनाड के साथ ही रायबरेली से भी चुनाव लड़ा था और दोनों सीटो पर जीत दर्ज की थी। बाद मे उन्होंने वायनाड सीट छोड़ दी। कांग्रेस के घोषणा की है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर पोस्ट किया, जाहिर है कि 2 इन।

एक्स पर पोस्ट किया, जाहिर है कि 2 इन। को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण अच्छा नहीं लगा। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया है कि छापेमारी की तैयारी हो रही है। मैं ईडी का दिल खोलकर इंतजार कर रहा हूं। मेरी

राहुल को जाति बताए बिना गणना करने का फॉर्मूला बताना चाहिए : हिमंत

भाषा। जमशेदपुर

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शुक्रवार को सवाल उठाया कि अपनी जाति का खुलासा किए बिना जाति आधारित गणना कैसे संभव है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से कहा कि यदि उनके पास इस संबंध में कोई फॉर्मूला है, तो वह लोगों को बताएं। झारखंड में भूजपा के चुनाव सह प्रभारी शर्मा ने यहां मीडियाकार्मियों से बातचीत में दावा किया कि राहुल गांधी देश में जाति आधारित गणना की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जाति का खुलासा नहीं किया है। उन्होंने कहा, हम गांधी से यह जानना चाहेंगे कि अपनी जाति बताए बिना जाति आधारित गणना करने का फार्मूला क्या है। शर्मा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि राहुल गांधी

तर्फ से चाय और बिस्कुट। चंद्रशेखर ने कहा कि आपदा में 300 से अधिक लोगों की मौत सिर्फ त्रासदी नहीं बल्कि एक अपराध है। उन्होंने कहा कि मरने वालों में ज्यादातर गरीब हैं।

मोदी सरकार केंद्र-राज्य समन्वय को और अधिक सुगम बनाने की दिशा में काम कर रही: शाह

भाषा। नई दिल्ली

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय को और अधिक सुगम बनाने की दिशा में काम कर रही है। जिससे अधिक संख्या में लोगों तक सेवाएं और समाधान पहुंच सकें।केंद्रीय मंत्री ने यह टिप्पणी शुक्रवार को शुरू हुए राज्यपालों के दो दिवसीय सम्मेलन में की। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन और अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की।शाह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी पोस्ट में कहा, आज राष्ट्रपति भवन में



राज्यपालों के सम्मेलन में हिस्सा लिया। मोदी सरकार राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय को और भी अधिक सुलभ बनाने की दिशा में काम कर

रही है ताकि सेवाओं और समाधानों के साथ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा जा सके। गृहमंत्री ने कहा कि यह मंच न केवल राज्यों के

संबैधानिक प्रमुखों के लिए एक स्थान पर एकत्र होने का मौका देता बल्कि विचारों के आदान-प्रदान का मौका भी देता है।। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन में

गिरफ्तारी के बारे में उद्भव का आरोप झूठा है: शिंदे

छत्रपति संभाजीनगर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को यहां कहा कि शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्भव ठाकरे का यह आरोप झूठ है कि उन्हें और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार किया जा सकता है। राज्य सरकार को लाडूकी बहिन योजना का उद्घाटन करने के लिए सिल्लोड में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ठाकरे इस मामले में निम्न स्तरीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठाकरे ने बुधवार को दावा किया था कि राकोंपा (शारनचंद्र पवार) नेता एवं राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने हाल में कहा था कि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख और उनके बेटे को गिरफ्तार करने की योजना बना रहे हैं। फडणवीस राज्य का गृह विभाग भी संभालते हैं। ठाकरे ने फडणवीस को चुनौती देते हुए कहा था, सब कुछ सहन करने के बाद अब मैं दूढ़ निश्चय के साथ खड़ा हूं। या तो आप वहां होंगे या मैं। मुख्यमंत्री ने मराठी समाचार चैनल एबीपी माझा से बात करते हुए कहा, उद्भव और आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी का मुद्दा एक फर्जी कहानी है। ठाकरे निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं।।

कर्नाटक में पुत्तूर बाईपास रोड पर भूस्खलन, राष्ट्रीय राजमार्ग 275 पर यातायात बाधित

भाषा। मंगलूर

कर्नाटक के मंगलूरु में पुत्तूर बाईपास रोड पर भूस्खलन होने से यातायात बाधित हो गया। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुत्तूर बाईपास रोड को बंटवाक-मैसूरु रोड और राष्ट्रीय राजमार्ग 275 के नाम से भी जाना जाता है।अधिकारियों ने स्थानीय लोगों के हवाले से बताया कि पुत्तूर बाईपास रोड पर शुक्रवार तड़के करीब तीन बजे भूस्खलन हुआ, जिसके बाद मैसूरु और मंगलूरु जाने वाले वाहनों में जो प्रतिस्पर्धा देखी गुजरना पड़ा रहा है।पुलिस के अनुसार, भूस्खलन होने के कारण वहां अभी तक किसी व्यक्ति या वाहन के फंसे भी कोई सूचना नहीं है।

भूस्खलन स्थल के दोनों तरफ अवरोधक लगा दिए गए हैं, जिससे पुत्तूर शहर से गुजरने वाले यातायात के मार्ग में बदलाव हुआ है। घटनास्थल पर कई श्रमिक और उत्खनन मशीन भेजकर सुबह आठ बजे मलबा हटाने का काम शुरू किया। कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र ने तटीय तथा आंतरिक तटीय क्षेत्रों में और अधिक बारिश की संभावना जताई है, जिससे प्रभावित हिस्सों में मलबा हटाने के काम में बाधा उत्पन्न हो सकती है। अधिकारियों ने बताया कि भूस्खलन की एक अन्य घटना सुबह 4:30 बजे पुत्तूर के बेलिपपाडी अधिभरी गांव में हुई जिससे दो घर तथा एक गौशाला क्षतिग्रस्त हो गईं और रोड में बंधी चार गायों की मारत

में दबकर मौत हो गई।

तेलंगाना सरकार 30,000 सरकारी स्कूलों को मुफ्त बिजली देगी

हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए र्वेंत रेड्डी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार बुनियादी सुविधाओं में सुधार के उपायों के तहत लगभग 30,000 सरकारी स्कूलों को मुफ्त बिजली प्रदान करेगी।हाल ही में पदोन्नत हुए शिक्षकों के एक सम्मेलन (ओर) हमें इसके लिए तैयारी करने की जरूरत है। चीन धीरे-धीरे हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है, जिसे पारंपरिक रूप से भारतीय नौसेना का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है।जयशंकर ने सेंटर फॉर एयर्पावर स्टडीज (सीएपीएस) में जसजीत सिंह स्मारक व्याख्यान देने के बाद

झारखंड में भाजपा विधायकों का अनोखा विरोध-प्रदर्शन, विधानसभा के बाहर बालू का स्टॉल लगाया

रांची। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की झारखंड इकाई ने शुक्रवार को विधानसभा के बाहर बालू का स्टॉल लगाकर अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया और हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार पर आरोप लगाया कि वह बालू की आसमान छूती कीमतों को नियंत्रित नहीं कर रही है। सौ रूप से लेकर 1,000 रूपए प्रति किलोग्राम तक की मूल्य सूची को दिखाते हुए भाजपा विधायक बालू का वजन करते और इसे 100 रूपए की विधायकों को बेचते देखे गए। इन विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने शुक्रवार अपराह्न दो बजे तक के लिए निलंबित कर दिया था। भाजपा

विधायक शशि भूषण मेहता ने आरोप लगाया, झारखंड में बालू बहुत महंगा है क्योंकि इसे दूसरे राज्यों में ले जाया जा रहा है। पार्टी के मुख्य सचेतक बिरेन्की नारायण ने कहा कि वे झारखंड में आम आदमी के हालात दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा, अब बालू टुक या ट्रेक्टर से नहीं, बल्कि किलो में बेचा जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इसे भाषणा की नोंटकी करार देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने गरीबों के लिए बालू मुफ्त कर दिया है। सोरेन ने कहा, हमारे मुख्यमंत्री ने राज्य के गरीब लोगों के लिए बालू को मुफ्त कर दिया है।

निर्यात प्रतिबंध नहीं हटाने से प्याज वाले क्षेत्र में हमें नुकसान हुआ : अजित पवार मुंबई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत गठबंधन को लोकसभा चुनाव में राज्य के प्याज की पैदावार वाले क्षेत्रों में नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि वहां के लोग प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध से नाराज थे। पवार ने नासिक जिले में एक जनसभा में कहा, यह आपका अधिकार है और मैं आपका अनादर नहीं करना चाहता। मैं आपको दोष नहीं दे रहा। प्याज निर्यात पर प्रतिबंध हटाने में हम पीछे रह गए। महायुति (भाजपा, शिवसेना और राकोंपा) का सत्तारूढ़ गठबंधन पीछे रह गया और हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकोंप) के नेता ने कहा, आपने (मतदाताओं ने) हमें नासिक क्षेत्र में, अहमदनगर, पुणे और सोलापुर क्षेत्रों में हराया है।

बिहार में आकशीय बिजली गिरने से आठ लोगों की मौत पटना। बिहार के चार जिलों में पिछले 24 घंटे की अवधि के दौरान आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में आठ लोगों की मौत हो गई। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने बताया कि रायचौरी (सीएमओ) ने बताया कि रायचौरी की राजधानी पटना और औरंगाबाद में तीन-तीन मौतें हुईं, जबकि नवादा और सारण में एक-एक व्यक्ति की जान चली गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मौतों पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रूपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। कुमार ने लोगों से अपील की कि वे आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी परामर्श का पालन करें। राज्य के चार जिलों में बृहस्पतिवार को आकाशीय बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई थी।

विवक न्यूज

वेणुगोपाल का नड्डा को पत्र: केरल के नीट-पीजी अभ्यर्थियों के लिए राज्य में परीक्षा केंद्र का आग्रह नई दिल्ली। कांग्रेस केसंगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री ने पी नड्डा से आग्रह किया कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-पीजी के लिए केरल के विद्यार्थियों के लिए उनके राज्य के भीतर या आस-पास के स्थानों में परीक्षा केंद्र सुनिश्चित किए जाएं। केरल के अलपुझा से सांसद ने नड्डा को पत्र लिखकर कहा कि केरल और अन्य जगहों के कई उम्मीदवारों के परीक्षा केंद्रों और तारीखों को लेकर परेशान करने वाले और असह्यचित्तक बदलाव किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसने गुराह वी जरूरत है। वेणुगोपाल ने कहा, नीट-पीजी परीक्षा कई बार स्थगित की जा चुकी है। हाल ही में, परीक्षा को 11 अगस्त से पुनर्निर्धारित किया गया था। 19 जुलाई को, उम्मीदवारों को एक परीक्षा केंद्रों का चयन करने के लिए कहा गया था। परेशान करने वाली बात यह है कि केरल के उम्मीदवारों को राज्य के भीतर सीमित विकल्प और आंध्र प्रदेश जैसे दूर के स्थानों में एक अनिवार्य चीज विकल्प प्रदान किया गया। उन्होंने देखा, इस अप्वाचन के बावजूद कि परीक्षा केंद्रों का विवरण 29 जुलाई को जारी किया जाएगा, उम्मीदवारों से 31 जुलाई को ईमेल प्राप्त हुए, जिसने केरल शहर के नाम का संकेत दिया गया। वेणुगोपाल ने बताया कि परीक्षा केंद्र विवरण का खुलासा परीक्षा से ठीक तीन दिन पहले 8 अगस्त को किया जाना है। उन्होंने कहा, इस स्थिति के कारण केरल के लगभग 1,000 अभ्यर्थियों में विशिष्ट तिथियां और विशाखापातनम जैसे स्थानों में परीक्षा केंद्रों और कई अन्य लोगों को इसी तरह वी परिस्थितियों में छोड़ दिया गया है। परीक्षा वी तारीख से शिफ्ट 11 दिन पहले परीक्षा केंद्रों की घोषणा ने महत्वपूर्ण तार्किक चुनौतियां पैदा की है।

आर्युष मंत्रालय नेयुरोपैथी का करेगा समग्र विकास : प्रतापराव जाधव'

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के नरेंद्रेट्टेशन वलर ऑफइंडिया में सूर्य फाउण्डेशन व इंटरनेशनल नेयुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा केन्द्रीय आर्युष राज्य मंत्री स्वर्तन प्रभार प्रतापराव जाधव का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया था। समारोह का उद्घाटन आर्युष राज्य मंत्री स्वर्तन प्रभार ने दीप प्रजनवलन के साथ किया। समारोह में 200 से अधिक योग प्राकृतिक चिकित्सा जगत के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त राजू बिरिच और मोनासिस्टोनों सांसद, कोसूम कर्नाकर देव जी वॉडस येवरेगैन सूर्य फाउण्डेशन, डॉ. डी. उम. शर्मा व डॉ आर एस डबास दोनों राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बिजान राज शिन्दे पूर्व विधायक बुलढान महापवार, नन्द किशोरी अग्रवाल अध्यक्ष व गानाराज अग्रवाल, बालाजी निरुमगामन वैलसन नेचर येथोे दिल्ली तथा प्राकृतिक चिकित्सा योग की अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि भी उपस्थित हुए। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में दर्जिलेन के सांसद श्री राजूबिचट्ट और बुलन्दशहर के सांसद डॉ मोनासिंह ने उपस्थित प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि पेशशी जगप्रपत्ता पिछले तीन दशकों से प्राकृतिक चिकित्सा योग के समग्र विकास हेतु प्रशस्त व सहायकीय योगदान दे रहे हैं। हम भी संसद में प्राकृतिक चिकित्सा के विकास हेतु आवाज बुलन्द करेगे। अभिनन्दन समारोह के अध्यक्ष व इंटरनेशनल नेयुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ अनंत बिराटार ने आर्युष मंत्रालय व नेशनल आर्युष मिशन द्वारा पिछले 8 वर्षों में नेयुरोपैथी के लिए किये गये रचनात्मक कार्यों हेतु आर्युष मंत्री व आर्युष सचिव का आभार प्रकट किया।

कस्तूर्रींगन रिपोर्ट खारिज करने पर वन मंत्री से बातचीत के बाद अतिम निर्णय लिया जाएगा: सिद्धरमैया

मेरिदेशी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार ने परिणामी घाट पर कस्तूर्रींगन रिपोर्ट को खारिज करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय वन मंत्री ईश्वर खांडे के साथ चर्चा के बाद लिया जाएगा। इससे के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूर्रींगन वी अध्यक्षता वाली परिणामी घाट समिति ने प्रस्ताव दिया है कि परिणामी घाट के सूखे क्षेत्रफल का 37 प्रतिशत भाग पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) घोषित किया जाए। सीटीएस प्रतिशत क्षेत्र लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर केसमक है। साठ हजार वर्ग किलोमीटर से से लगभग 21,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कर्नाटक में है। रिपोर्ट में खनन, उत्खनन, लाल श्रेणी केउद्योगों और ताप विद्युत परियोजनाओं वी स्थाना पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वी सिफारिश वी गई है। चेन्नू जिले के जिला मुख्यलय मेरिदेशी में भूस्खलन और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के बाद परक्यूड से बात करते हुए सिद्धरमैया ने कहा, कस्तूर्री रंगन रिपोर्ट को खारिज करने का फैसला किया गया है। वन मंत्री के साथ आगे वी चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 20 जून को भूस्खलन हुआ है, जबकि कई अन्य जगहों पर छोटें पैमाने पर भूस्खलन हुआ है। उन्होंने कहा कि इसने कुछ लोग घायल हुए हैं। सिद्धरमैया ने कहा कि 67 मकान पूर्ण तरह से नष्ट से गए हैं, और 176 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं।

देश में विकिरसक-जनसंख्या अनुपात डब्ल्यूएचओ मानक से बेहतर: सरकार

नई दिल्ली। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुरूपिया पटेल ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि देश में विकिरसक और जनसंख्या का अनुपात विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मानक से बेहतर है और भारत ने 836 लोगों पर एक विकिरसक है। डब्ल्यूएचओ मानक के अनुसार 1000 लोगों पर एक विकिरसक लेना चाहिए। पटेल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय विकिरसा आयोग (एनएनसी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जुलाई, 2024 तक राज्य विकिरसा परिदेशी और राष्ट्रीय विकिरसा आयोग (एनएनसी) से 13,86,136 एलेथोपिक विकिरसक फंजीकृत है। उन्होंने कहा, फंजीकृत एलेथोपिक विकिरसक वी 80 प्रतिशत उपलब्धता और लगभग 5.65 लाख आर्युष डॉक्टरों के उपलब्धता मानते हुए, देश में विकिरसक-जनसंख्या अनुपात लगभग 1:836 है, जो डब्ल्यूएचओ मानका:1000 से बेहतर है। उन्होंने यह भी कहा कि देश ने 731 मेडिकल कॉलेज है, जिनमें अभी 1,12,112 एमबीबीएस सीट है। इसके अलावा 72,627 पीजी सीट है। विकिरसा शिक्षा सुविधाओं को बढ़ाने और विकिरसा मानकों को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों ने जलानिरोपल अस्पतालों को अपग्रेड करके नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना वी खारिज केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसए) शामिल है, जिसके तहत 157 नए मेडिकल कॉलेजों को नंगूरु दी गई है और 109 पहले से ही काम कर रहे हैं।

नागरिकता के लिए मतदाता पहचान-पत्र को पर्याप्त प्रमाण बनाएं : तृणमूल सांसद

नई दिल्ली। राज्यसभा में शुक्रवार को तुणमूल कांग्रेस वी एक सदस्य ने विधानसभा या संसदीय चुनावों में मतदान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वैध पहचान पत्र को नागरिकता प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रमाण मानने की वसंतवती में और कहा कि पैकेट दरदतान नही दिखाने पर निरुद्ध शिदिसे ने जेजे जाने जैसी शर्त अमानवीय है। तुणमूल सदस्य मतदाता टाकुर से उच्च सदन में शुल्कवाल के दौरान यह गुद्दा उठया और कहा कि किसी को अपमानित करने वाली शर्त लागू करना सीटीएम नहीं है। उन्होंने बाला माषा से अपाणी बात रखते हुए कहा, जो मतदान करते है, जिनके पास कोई भी ऐसा वैध पहचान-पत्र है, जिसका इस्तेमाल हम मतदान के लिए और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्रियों या राज्यो के सरकारों से चुनने के लिए करते है, उन्हें फिर से दरदतावेज दिखाने के लिए मजबूर करना या नागरिकता के लिए फिर से आवेदन करने के लिए मजबूर करना अपमानजनक है...। मतदाता टाकुर नागरिकता प्रदान करने के लिए वैध प्रमाण के रूप में मतदाता पहचान-पत्र के इस्तेमाल का जिक्र कर रही थी। उन्होंने कहा, नागरिकता प्रदान करने के नाम पर शर्तों जोजना, उन्हें पैकेट दरदतावेज पेश करने के लिए बाध्य करना और ऐसा नहीं करने पर नागरिकता नही देना और उन्हें निरुद्ध शिदिसे ने मेजाना बेहद अमानवीय है।

नोएडा। इलेक्ट्रिक कॉमर्शियल वाहन बनाने वाली प्रमुख कम्पनी ऑटोएल मोटर्स ने इस्टाट सोल्यूशंस के साथ साझेदारी में गौतमबुद्द नगर नोएडा के सेक्टर-63 में अपनी पहली डीलरशिप खोली है। पूरे देश में कम्पनी की यह 21वीं डीलरशिप है और कर्नाथियन ईवी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कम्पनी अपनी डिटेल उपस्थिति का दावाय बढ़ा रही है। नए शोरूम में ऑटोएल मोटर्स के प्रमुख धी व्हीलर कर्नाथियल वाहन. झड़लौड ईवी को प्रदर्शित किया जाएगा।जिसे 30 फीसदी ज्यादा आमदनी और गुनाफा देने के लिलखन से डिजाइन किया गया है। ऑटोएल मोटर्स के फाउंडर और सीईओ सौरव कुमार ने कहा कि हम नोएडा में पहली डीलरशिप खोलकर काफी उत्साहित हैं। यह हम उपभोक्ताओं का कारोबार बढ़ाने के लिए उनके लिए एक ईवी समाधान पेश कर रहे हैं। ऑटोएल मोटर्स वित्त वर्ष 2025 के अंत तक कर्नाथियन ईवी मार्केट का 15 फीसदी हिस्सा हासिल करने के अपने मिशन से तालमेल बनाकर काम कर रहा है।

नाइजीरिया में आर्थिक संकट के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान 13 लोग मारे गए

मानवाधिकार समूह का दावा

भाषा। अबुजा

नाइजीरिया में आर्थिक संकट के खिलाफ व्यापक पैमाने पर जारी विरोध-प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 13 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। एक मानवाधिकार समूह ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। विरोध-प्रदर्शन ने कई राज्यों में हिंसक रूप ले लिया है, जिसके चलते कई जगह कर्फ्यू घोषित किया गया है। अधिकारियों ने बम धमाके में चार लोगों की मौत होने की पुष्टि की और कहा कि



देशभर में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के नाइजीरिया निदेशक ईसा सानुसी ने एक साक्षात्कार में

कहा कि समूह ने चरमदीयों, पीड़ितों के परिवारों और वकीलों द्वारा बताई गई मौतों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि की है। इस बीच, नाइजीरिया की पुलिस

ने कहा कि सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों की लूटपाट के चलते उत्तरी राज्यों - कानो और कटसीना में 300 से अधिक प्रदर्शनकारियों को

गिरफ्तार किया गया और कर्फ्यू लगा दिया गया। उसने बताया कि एक पुलिस अधिकारी की भी मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। प्रदर्शनकारों बढ़ते आर्थिक संकट को दूर करने की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते अफ्रीका के शीर्ष तेल उत्पादक देश के लोग सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने भ्रष्टाचार और कुशासन को समाप्त करने की मांग की। मॉडिया में आए विरोध-प्रदर्शन के वीडियो में कुछ प्रदर्शनकारियों को गोदामों में लूटपाट करते और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए देखा जा सकता है।

रूस से बंदियों की अदला-बदली के बाद रिहा हुए तीन अमेरिकी स्वदेश पहुंचे

भाषा। वाशिंगटन

रूसी खुफिया एजेंट को भी छोड़ा गया

तालिन (एस्टोनिया)। अमेरिका और रूस के बीच गीत युद्ध केबाद कैदियों की सबसे बड़ी अदला-बदली में रूस ने पहली बार स्वीकार किया किपरिष्नी देशो ने पकड़े गए कुछ रूसी नागरिकउसकी सुरक्षा सेवाओं से जुड़े थे। रिस फिमि गए कैदियों के परिवारो ने इस आश्चर्यजनकहिसई पर अपनी खुशी व्यक्त की। बहुर्रपातिवार रात अमेरिक्की प्रांत मैरीलैंडने एकत्रक इवान गेरशवोविच और अल्पसुर्केशीया तथा पूर्वी मरीन पील व्हेलन वा उनके परिवारो से स्वागत किया। अमेरिक्क केराष्ट्रपति जो बाइडन ने भी इस पर खुशी जताई। वही, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मास्यो के वातुक्वो हवाई अड्डे पर वापस आए प्रत्यक्षरूसी नागरिकको गले लगाया। "दोे वाले आठ लोगो ने वाफिन क्योक्वो भी शामिल था, जो एक रूसी हत्याार था और 2019 ने बर्लिन के एक पार्क में एक पूर्व चेचन लड़ाके की हत्या के लिए गर्जनी ने आजीवन कारावास की सजा कर रख था। गर्जन वय्याक्वोशो ने क्या था कि हत्या रूसी अधिकारियों के आदेश पर की गई थी।" रूस के राष्ट्रपति वर्यालय फ्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया कि क्योक्वोव सशरी सुरक्षा सेवा (एमएसबी) का अधिकारी है और परिष्नी देशो को भी यह तथ्य बताया गया। उन्होंने यह भी कहा कि क्योक्वोव ने एक बार पुतिन के कुछ अंगरक्षको के साथ एएसबी की विशेष अड्डा जर्मई ने वजन किया था।

मध्यरात्रि में स्वदेश पहुंचे। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किए जाने के कारण शीतयुद्ध के बाद

वाशिंगटन और मॉस्को के बीच संबंध

सबसे निचले स्तर पर आ गए थे, लेकिन इसके बावजूद बंदियों की अदला-बदली के लिए गुप्त बैठकें

अमेरिका में मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में दो भारतीय गिरफ्तार

भाषा। वाशिंगटन

अमेरिका में मादक पदार्थ की तस्करी करने के आरोप में दो भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से एक करोड़ अमेरिकी डॉलर का नशीला पदार्थ भी बरामद हुआ है। न्याय विभाग ने यह जानकारी दी। न्याय विभाग ने बताया कि आरोपियों की पहचान 28 वर्षीय सिमरन्जोत सिंह और 19 वर्षीय गुप्तिमरत सिंह के रूप में हुई है और वे कैलिफोर्निया के फ्रेस्नो के निवासी थे। उसने बताया कि भारतीय नागरिकों पर मादक पदार्थ की तस्करी करने का आरोप है। आरोपियों को 29 जुलाई को बोस्टन की एक अदालत में पेश किया गया था, जहां से उन्हें हिरासत में भेज दिया था। स्थानीय पुलिस ने एक ट्रैक्टर से 400 किलोग्राम से अधिक की कोकीन बरामद करने के बाद दोनों भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया था। कोकीन की कीमत लगभग 1.05 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। अमेरिका में मादक पदार्थ की तस्करी का दोषी पाए जाने पर अधिकतम 20 साल और कम से कम तीन साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही दस लाख अमेरिकी डॉलर तक के जुर्माने का प्रावधान है।

एआई के युग में दर्शनशास्त्र महत्वपूर्ण है

लंदन। नई वैज्ञानिक समझ और इंजीनियरिंग तकनीकें हमेशा प्रभावित और भयभीत करती रही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि आगे भी ऐसा होता रहेगा। ओपनएआई ने हाल ही में घोषणा की है कि उसे इस दशक में मानवीय क्षमताओं को पार करने वाला एआई 'सुपरइंटेलिजेंस' बन जाने का अनुमान है। यह तदनुसार एक नई टीम का निर्माण कर रहा है, और अपने कंयूटिंग संसाधनों का 20x यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित कर रहा है कि ऐसे एआई सिस्टम का व्यवहार मानवीय मूल्यों के साथ संतुलित होगा। ऐसा लगता है कि वे नहीं चाहते कि दुष्ट कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवता पर युद्ध छेड़े, जैसा कि जेम्स कैमरून की 1984 की विज्ञान कथा थ्रिलर, द टर्मिनेटर (बदकिस्मती से,



अनॉल्ड श्वार्ज़नेगर की टर्मिनेटर में 2029 से समय में वापस भेजा गया है) में हुआ था। ओपनएआई समस्या से निपटने में मदद के लिए शीर्ष मशीन-लर्निंग शोधकर्ताओं और इंजीनियरों को बुला रहा है लेकिन क्या दार्शनिकों के पास योगदान करने के लिए कुछ हो सकता है? अधिक सामान्यतः, अब उभर रहे नए तकनीकी रूप से उन्नत युग में इस सदियों पुराने विषय से क्या उम्मीद

की जा सकती है?इसका उत्तर देने के लिए, इस बात पर जोर देना जरूरी है कि दर्शन अपनी शुरुआत से ही एआई से सहायक रहा है। पहली एआई सफलता की कहानियों में से एक 1956 का कंयूटर प्रोग्राम था, जिसे लॉजिक थियोरिस्ट कहा जाता था, जिसे एलन नेवेल और हर्बर्ट साइमन ने बनाया था। इसका काम प्रिंसिपिया मैथमेटिका के प्रस्तावों का उपयोग करके प्रमेयों को सिद्ध करना था, जो 1910 में दार्शनिक अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड और बर्ट्रेड रसेल द्वारा तीन खंडों में लिखा गया काम था, जिसका लक्ष्य सभी गणित को एक तार्किक आधार पर फिर से बनाना था वास्तव में, एआई में तर्क पर शुरुआती फोकस गणितज्ञों और दार्शनिकों द्वारा अपनाई गई मूलभूत बहसों के कारण था।

मेटा ने इतिहास का सबसे बड़ा ओपन एआई मॉडल लॉन्च

इसका व्यापकहित में होना जरूर

सिडनी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को दुनिया में एक लड़ाई चल रही है। एक तरफ ऐसी कंपनियाँ हैं जो अपने उन्नत सॉफ्टवेयर के पीछे डेयसेट और एल्गोरिदम को निजी और गोपनीय रखने में विश्वास करती हैं। दूसरी ओर ऐसी कंपनियाँ हैं जो जनता को यह देखने की अनुमति देने में विश्वास करती हैं कि उनके परिष्कृत एआई मॉडल के के पीछे आखिर क्या है इसे खुले और बंद स्रोत एआई के बीच की लड़ाई के रूप में देखा जा सकता है।हाल के सप्ताहों में, फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने बड़े एआई मॉडल का एक नया संग्रह जारी करके ओपन-सोर्स एआई के लिए बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ी। इनमें

लामा 3.1 405वीं नाम का एक मॉडल शामिल है, जिसके बारे में मेटा के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी, मार्क जुकरबर्ग कहते हैं, े पहला फ्रंटियर-स्तरीय ओपन सोर्स एआई मॉडल है।ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए जो ऐसे किसी को प्रवाह करता है जिसमें हर कोई एआई के लाभों तक पहुंच सके, यह अच्छी खबर है।क्लोउड-सोर्स एआई का खतरा - और ओपन-सोर्स एआई का वादाखरोड़-सोर्स एआई उन मॉडलों, डेटासेट और एल्गोरिदम को संदर्भित करता है जो स्वामित्व वाले होते हैं और गोपनीय रखे जाते हैं। उदाहरणों में चैटजीपीटी, गूगल का जेमिनी और एंथ्रोपिक का क्लाउड शामिल हैं।हालाँकि कोई भी इन उत्पादों का उपयोग कर सकता है, लेकिन यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि एआई मॉडल या टूल बनाने के लिए

आई एनर्जी में नवाचार का प्रयोग जारी

ऊर्जा लेइएण के समाधानों में नवाचार में अग्रणी लिटावॉ को अपने नवीतम अभियान बनेो किसी की एनर्जी को लॉन्च करते हुए गर्व हो रहा है जिसमें प्रतिष्ठित अभिनेता अशय कुमार को भी दर्शाया गया है। ब्रंड ने हाल ही में अपन शानदार उत्पाद, डिजन एक्ट्रीएक्स 1100आई इनवर्टेड लॉन्च किया है जो पावर कट प्रोडिशनए चार्जिंग इंडिरेक्टर के साथ डिजिटल स्क्रैन डिस्प्ले,रॉलिंग लोड, बैकअप टाइम अदि जैसी उन्नत और स्मार्ट सुविधाओं के साथ आता है और इसे एक अत्याधुनिक उत्पाद बनाता है। दिल को छूने वाली यह लाइविंग परिवार के स्तंभ कर्ताथि होने के साथ आने वाली निम्नोदारी की अद्भुत भावना को उजागर करती है और बताती है कि कैसे लिटावॉई के स्मार्ट एआई चार्जिंग इनवर्टेड लोगों को अपने प्रियजनों की सहायता करने और उनका उत्थान करने में सक्षम बनाते है। यह उत्पाद आपका डिजन अजने तरीके से पलाने में सक्षमता करेगा। टीवीपी पर टिप्पणी करते हुए लिटावॉई फर्नांडो टेगनेलॉनी प्राइवेट लिमिटेड के एनडी और सीईओ गुरपीत भाटिया ने कहा कि हम अपने उपभोक्ताओं को समझते है और अपने प्रियजनोंकी प्रगति में उनकी मुक्ति को स्वीकार करते है। हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे उत्पाद उन्हें और उनके परिवार को ऊर्जा के बारे में अज्ञादी दक्षित करने में मदद करेए जिससे उनकी प्रगति को बढ़ावा मिलता है।

किस डेटासेट और स्रोत कोड का उपयोग किया गया है।हालाँकि यह कंपनियों के लिए अपनी बौद्धिक संपदा और अपने मुनाफे की रक्षा

करने का एक शानदार तरीका है, लेकिन इससे सार्वजनिक विश्वास और जवाबदेही को कम करने का जोखिम है। एआई प्रौद्योगिकी को बंद-स्रोत

बढ़ते तनाव के बीच इजराइल में रह रहे भारतीयों को सतर्क रहने की सलाह

भाषा। तेल अवीव

भारतीय दूतावास ने यहां शुक्रवार को इजराइल में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी कि वे सतर्क रहने के साथ स्थानीय प्रशासन की ओर से सुझाए गए सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें। इजराइल के हमले में एक के बाद एक दो हमास नेताओं और हिजबुल्ला के एक कमांडर के मारे जाने के बाद पश्चिम एशिया में नए सिरे से बढ़े तनाव के मद्देनजर भारतीय दूतावास ने यह परामर्श जारी किया। पिछले महीने हमास नेता इस्माइल हनिएह की ईमन में हत्या कर दी गई जबकि हमास की सैन्य शाखा के प्रमुख मोहम्मद जेफ गाजा में मारा गया। लेबनान में सक्रिय हिजबुल्ला का कमांडर फौद शुक्ूर बेरूत पर किए

गए हवाई हमले में मारा गया। 972-547520711 और 972-543278392 जैसे संपर्क नंबरों द्वारा गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई है और हनिएह की मौत से इलाके में तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंचने की आशंका है। भारतीय दूतावास ने यहां जारी एक परामर्श में कहा, कृपया सावधानी बरतें, देश के भीतर आवश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षा आश्रयों के करीब रहें। दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इजराइली अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में है। दूतावास के सभी सोशल मीडिया मंच पर पोस्ट करके अंग्रेजी, हिंदी, तेलगु और कन्नड़ में जारी किए गए परामर्श में इमेल पते के साथ टेलीफोन नंबर

972-547520711 और 972-543278392 जैसे संपर्क नंबरों दिए गए हैं जिस पर 24 घंटे मदद उपलब्ध रहेगी। एयर इंडिया ने बृहस्पतिवार को अपनी दिल्ली-तेल अवीव उड़ानें मराने का फैसला कर दिया है। इजराइली अधिकारियों के इस दावे के बावजूद कि उसका हवाई क्षेत्र बिस्कुल सुरक्षित है, लगभग 10 अंतरराष्ट्रीय विमानन कंपनियों ने अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। इजराइल में भारतीय मिशन की ओर से जारी परामर्श से पहले बेरूत स्थित भारतीय दूतावास ने बृहस्पतिवार को नागरिकों को अगली सूचना तक लेबनान की यात्रा नहीं करने की सलाह दी थी, इसके अलावा उन्हें लेबनान छोड़ने की भी सलाह दी गई है।

विक न्यूज

अपनी पहली विदेश यात्रा पर थाईलैंड जा सकते हैं नेपाल केनए प्रधानमंत्री ओली
कठमांडू। नेपाल के नव-निर्वाचित प्रधानमंत्री केपी. शर्मा ओली अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए संभवतः थाईलैंड जा सकते हैं, जिससे पहले किसी पड़ोसी देश की यात्रा करने की पधर दू जानगी। पूर्व में, नेपाल के प्रधानमंत्रियों ने अधिकतर पहले भारत का दौरा किया था, हालांकि कुछ ने चीन की भी यात्रा की थी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री ओली सिंबर के पहले सप्ताह में बिसपेदक (बहू-क्षेत्रीय तन्त्रीय) और आर्थिकसदस्यों के लिए बंगाल की खाड़ी (एनए) शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष होने के लिए थाईलैंड की यात्रा पर जाएंगे। ओली के एकसहयोगी ने बताया कि प्रधानमंत्री बिस्केट शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए अपनी पहली विदेश यात्रा केतहत सिंबर केपहले सप्ताह में थाईलैंड जाएंगे, हालांकि यात्रा केतिथिया को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। बंगलादेश, भूटान, भारत, क्याम्बो, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड सहित बिस्केट के सदस्य देशों के नेता शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए सिंबर के पहले सप्ताह में बैकेंग में मिल रहे है।प्रधानमंत्री ओली संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए सिंबर के तीसरे सप्ताह में अमेरिका की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री के एकसहयोगी ने कहा, अभी तक हमे भारत यात्रा के लिए कोई आधिकारिकनिर्माण नही मिला है।

नेपाल: नवनियुक्त प्रधानमंत्री ओली ने तीन लोगों को राज्य मंत्री बनाया

कठमांडू। नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने शुक्रवार को अपनी मंत्रिपरिषद का विस्तार करते हुए तीन लोगों को राज्य मंत्री बनाया। नेपाल के राष्ट्रपति रामप्रद पांडेय ने प्रधानमंत्री ओली की सिफारिश पर अरुण कुमार चौधरी, स्या बीके और पूर्व बहुराज तामां को राज्य मंत्री नियुक्त किया। राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी एक नोटिस के अनुसार, चौधरी को पर्यटन, संस्कृति और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री, स्या बीके को वन और पर्यावरण राज्य मंत्री और तामां को ऊर्जा एंव सिवार्ड राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है। स्या बीके और तामां नेपाली कांग्रेस से है जबकि चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी का प्रतिनिधित्व करते है। प्रधानमंत्री ओली की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित 25 सदस्य है। पिछले महीने सीपीएन-यूएमएल के अध्यक्ष 72 वींथीय ओली चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे, जिन्होंने पुष्प क्जाल दाहाल प्रवंद का स्थान लिया।

उत्तर-पश्चिम पाकिस्तान में न्यायाधीशों के कफिले पर हमला, दो पुलिसकर्मी मारे गए

पेशावर। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में शिया अशांत प्रांत खैबर पख्तूनख्वा ने आतंकवादियों ने शुक्रवार को ड्यूटी करके घर लौट रहे न्यायाधीशों के एक कफिले पर घात लगाकर हत्या कर दिया जिससे उनकी सुरक्षा में तैनात दो पुलिसकर्मीयों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। सभी तीन न्यायाधीश सुरक्षित है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, आतंकवादियों की ओर से घात लगाकर किए गए सशस्त्र हमले ने न्यायाधीशों की रक्षा करने समय ड्यूटी के दौरान दो पुलिसकर्मी मारे गए, जबकि दो अन्य घायल हो गए। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेप्ट इस्माइल खान ने टैक जितने की अदालतों ने ड्यूटी केबाद न्यायाधीशों का वाफिया उजा उरकेघरे और आतंज था तथा दो चर्डी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, लेकिन इसके बावजूद सशस्त्र आतंकवादियों ने घात लगाकर हत्या कर दिया। टैकडीअंश खान मार्ग पर पुलिस और आतंकवादियों केबीच गोलीबारी जारी है। इस बीच प्रांत के मुख्यमंत्री अली उम्रीन गंडापुर ने न्यायाधीशों को वाहनो पर हमले की निंदा करते हुए बयान देते हैं। गंडापुर ने दो पुलिसकर्मीयों की मौत पर संतपन व्यक्त करते हुए न्यायाधीशों के लिए सुरक्षा देय मजबूत करने का भी आह्वान किया। नेतेलन असेबली ने परस्तुत गृह मंत्रालय की एकरिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान में वर्ष 2023 में,1,514 आतंकवादी मराले हुए जिसने 2,922 लोग मारे गए।

पाकिस्तान : कुर्म जिले में हिंसक झड़पों में शामिल जनजातियों ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए

पेशावर। पाकिस्तान के अशांत उत्तर-पश्चिमी कुर्म जिले ने हिंसक झड़पों में शामिल जनजातियों ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए है, जिसकेबाद हिंसा रूक गई है। एकवर्षिक अधिकारी ने यह जानकारी दी। लगभग एकघण्टासे जो भी हिंसक झड़पों में 50 लोगों की मौत हो गई और 225 से अधिकलोग घायल हुए है। अधिकारी ने बताया किबृहस्पतिवार को जिन्ना (स्थानीय पंचायत) नेताओं के हस्तक्षेप के बाद शांति समझौता किया गया। उम्मुयुक्त जावेद उल्लेह मसूद ने कहा कि शांति समझौते के बाद अफ़गानिस्तान की सीमा से लगे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्म जिले में झड़पें बंद हो गईं। अधिकारियों ने बताया कि शांति समझौता कुर्म जिले में संपर्कित शिया और सुन्नी मुठों के बीच दो अलग-अलग अशोषित जिन्ना बैठकों में हुआ। दोनों पक्षों केपुसख लोगों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत दोनों जनजातियां सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में सहकार के साथ सहयोग करने पर सहमत हुईं। समझौते के अनुसार, शांति समझौते का उल्लंघन करने वाले किसी भी पक्ष को 12 क्सेड राइफ तक का जुर्माना देना होगा।

अमेरिका-रूस कैदी अदला-बदली : पत्रकारों के मू-राजनीतिक सौदेबाजी में इस्तेमाल का जोखिम

सिडनी। एक अमेरिकी दूताने ने कैदियों की वापसी की तस्वीर, जिनके चेहरे पर लंबी मुकुटसूट है, सब कुछ कहती है: खूनी, रहत और एक अविश्वसनीय जग से जटिल परिस्थिति में समाप्त। वॉल स्ट्रीट जर्नल केरिपोर्टर इवान गेरशवोविच, रेंडिओ प्री यूरोप केपत्रकार अल्पसुर्केशीया, पूर्व अमेरिकी मरीन पील व्हेलन और कई अन्य लोगों ने हिंसई शीत युद्ध की समाप्ति केबाद सबसे बड़ी कैदी अदला-बदली है छ्कू मिलाकर, सात अलग-अलग देशों के 26 लोगों को एक बेहद जटिल समझौते के तहत रिहा किया गया, जिस पर बातचीत करने में कई साल लग गए। उनमें रूस में कैद 16 लोग शामिल थे: तीन अमेरिकी, कई रूसी राजनीतिक कैदी, और एक 19 वींथीय रूसी-गर्जन नागरिक जो रूसी सैन्य अड्डे की तस्वीर लेने के कारण जेल में बंद था।बदले में, अपने रूसियों को भी रिहा कर दिया गया - उनमें से सबसे कुख्यात, वादिन फ़सिवोव, सशरीय सुरक्षा सेवा में एक कर्नल था, जिसे 2019 ने बर्लिन में एकपूर्व चेचन विद्रोही की हत्या करने पर गर्जनी ने जेल में डाल दिया गया था।अन्यव्यपपूर्ण तरीकेसे कैद किए गए लोगों के लिए स्वतंत्रता निर्दिष्ट रूप से अद्वैत सहार है, भले ही इसमें बहुत देर हो चुकी है, और बाइडेन प्रशासन सीटै पर बातचीत के दौरेन में कई महत्वात के लिए श्रेय का स्वरूप है।

फ़ोरेसिक विशेषज्ञ बताते हैं शव परीक्षण में क्या होता है

सिडनी। कमी-कमी यह सफर नहीं होता कि किसी व्यक्ति की मृत्यु कैसे और क्यों हुई। मृत्यु के बाद शरीर की विस्तृत जांच, जिसे शव परीक्षण या पोस्टमॉर्टल के रूप में जाना जाता है, इस प्रश्न का उत्तर खोजने में मदद कर सकती है। आपने टीवी द्रष्टांन शो में जो देखा होगा, उसके बावजूद अधिकांश शव-परीक्षाएं ज्यादा खट-खट किए बिना होती है।अधिकतर अलोक्यक प्रक्रिया के दौरान शरीर पर: अरुणार रहता है।हालाँकि, कमी-कमी अधिक विस्तृत जांच की आवश्यकता होती है।शव परीक्षण में शामिल सभी लोगों द्वारा इस प्रक्रिया के प्रत्यक्ष चरण में मृतक की पहिना और सम्बन्धन को प्राथमिकता दी जाती है।हामी शवों का परीक्षण नहीं होता-वह कि किसी भी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से होती है, संदिग्ध परिस्थितियों को कोई सबूत नहीं है या कोई हलिया थिरेक्सा इतिहास है, तो मृत्यु को उडिटेड द्वारा प्राणित किया जाता है। फिर व्यक्ति को अंतिम संस्कार सेवा तक ले जाया जाता है।लेकिन जब मौत के बारे में सवाल बने रहते हैं, तो विशेषज्ञ डॉक्टर, तकनीशियन और संस्यक कर्मचारी आगे की जांच कर सकते हैं। कमी-कमी इसमें शव-परीक्षा शामिल होती है।

